

इन्फार्मेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
की एक ई-शासन
प्रकाशन



06 दिल्ली राज्य

22 ई-डिटेक्शन

12 केरलम राज्य

24 एचजीवीएमएस

18 झज्जर, हरियाणा

26 सेवा सेतु शिकायत प्रबंधन ढांचा

20 मालेरकोटला, पंजाब

28 मिशन भगीरथ

संरक्षक

वी. टी. वी. रमणा

सलाहकार मंडल

अजय सिंह चहल
सुचित्रा प्यारेलाल
सी. जे. एन्टनी
मनी खनेजा
आलोक तिवारी

प्रधान संपादक

मोहन दास विश्वम्

क्षेत्रीय संपादक

सुषमा मिश्रा
निस्सी जॉर्ज
विनोद कुमार गर्ग

सामग्री सहयोग

अर्चना शर्मा
हेमेंद्र कुमार सैनी

डिजाइन सहयोग

मुकेश भारती
रोहित कुमार मौर्या

वेब एवं ई-बुक

सुनील कुमार
अमित कुमार लोधी
मो. पिंटू

भाषा अनुवाद सहयोग

अंकित कुमार

प्रिंट एवं समन्वय

यू.एक्स.डी.टी. विभाग

प्रकाशक

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय, भारत सरकार

संपर्क पता

इन्फॉर्मेटिक्स
379, ए4बी4, तृतीय तल, एनआईसी
ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003, भारत
फोन: 011-24305363/ 65
ईमेल: editor.info@nic.in

संपादकीय

पिछले एक दशक में भारत की डिजिटल शासन यात्रा को प्रायः विस्तार की भाषा में परिभाषित किया गया है: करोड़ों उपयोगकर्ता, हजारों सेवाएँ, राष्ट्रव्यापी प्लेटफॉर्म तथा तीव्र गति से विकसित होता डिजिटल अवसंरचना तंत्र। किन्तु, इनफॉर्मेटिक्स के इस अंक से स्पष्ट होता है कि शासन का अगला चरण अब केवल विस्तार तक सीमित नहीं है। अब इसका स्वरूप परिचालन परिपक्वता द्वारा अधिक परिभाषित हो रहा है।

देशभर में डिजिटल प्रणालियाँ प्रयोगात्मक चरण से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं। इस अंक में सम्मिलित पहलें इस परिवर्तन को अत्यंत स्पष्टता से प्रतिबिंबित करती हैं।

दिल्ली में शासन संबंधी प्लेटफॉर्म अब केवल पृथक सेवा पोर्टलों के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री जन सुनवाई, आई.एफ.एम.एस, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, ई-हॉस्पिटल तथा डी.डी.आई.एस जैसे तंत्र एक ऐसे विकसित होते पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाते हैं, जहाँ विभाग अब समानांतर प्रशासनिक ढाँचों के बजाय एकीकृत डिजिटल कार्यप्रवाहों के माध्यम से अधिक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।

इसी प्रकार, केरलम का व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी में निरंतर संस्थागत निवेश किस प्रकार शासन में स्थायित्व और सुदृढ़ता सुनिश्चित कर सकता है। स्पार्क, आई.एफ.एम.एस, केरलम सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फास्ट एंड ट्रांसपैरेंट क्लियरेंस, रेवेन्यू एंड लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम तथा ई-ऑफिस केरलम जैसे प्लेटफॉर्म यह स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल प्रणालियाँ अब वित्त, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, निर्वाचन तथा नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए आधारभूत सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित हो रही हैं।

डिजिटल शासन के स्वरूप में हो रहा परिवर्तन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब चर्चा केवल सेवाओं के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं रही है। इसका केन्द्रबिंदु अब विश्वसनीयता, अंतर-संचालनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता तथा संस्थागत विश्वास बनता जा रहा है।

इस अंक में सम्मिलित प्रौद्योगिकी संबंधी आलेख, जिनमें एंड्रॉयड अनुप्रयोगों के लिए डिटरमिनिस्टिक वेरिफिकेशन तथा आधुनिक एसआईईएम आधारित साइबर सुरक्षा परिचालन शामिल हैं, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित करते हैं। आज की शासन प्रणालियों को केवल बड़े स्तर पर कार्य करने योग्य ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुदृढ़ तथा सत्यापन योग्य भी होना आवश्यक है।

इसके साथ ही नागरिकों की अपेक्षाएँ भी तीव्र गति से बदल रही हैं। लोग अब ऐसे शासन प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो उत्तरदायी, पारदर्शी, मोबाइल-अनुकूल तथा भाषाई, भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं से परे सभी के लिए सुलभ हों। अतः डिजिटल शासन की सफलता केवल तकनीकी उन्नतता पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस पर भी निर्भर करेगी कि प्रणालियाँ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कितनी सहज, समावेशी और विश्वसनीय रूप से कर पाती हैं।

इस अंक में सम्मिलित पहलों के माध्यम से उभरती सबसे सकारात्मक प्रवृत्तियों में से एक है तकनीकी क्षमता और प्रशासनिक दृष्टि के बीच बढ़ता समन्वय। शासन में वास्तविक परिवर्तन तब संभव होता है जब डिजिटल प्रणालियों का निर्माण केवल तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संस्थागत वास्तविकताओं और नागरिक आवश्यकताओं की गहरी समझ के साथ किया जाए।

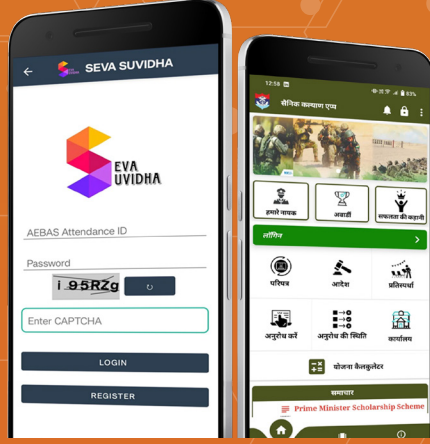
इनफॉर्मेटिक्स परिवार के लिए यह अंक एक महत्वपूर्ण संक्रमण का क्षण भी है। हम श्री अजय चहल, (उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हिमाचल प्रदेश) तथा श्रीमती सुचित्रा प्यारेलाल, (उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, केरलम) के अमूल्य योगदान के प्रति अपनी गहन सराहना व्यक्त करते हैं, जो क्रमशः अप्रैल एवं मई 2026 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके मार्गदर्शन, समर्पण तथा सतत प्रयासों ने इनफॉर्मेटिक्स त्रैमासिक को डिजिटल शासन विमर्श के एक सशक्त एवं प्रभावशाली मंच के रूप में सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जैसे-जैसे भारत एक अधिक परस्पर जुड़ी हुई डिजिटल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, प्रगति का वास्तविक मापदंड संभवतः अब निर्मित अनुप्रयोगों की संख्या नहीं, बल्कि यह होगा कि शासन स्वयं उनके माध्यम से कितनी सहजता से संचालित हो पाता है।

डिजिटल इंडिया की कहानी अब एक अधिक शांत, परंतु कहीं अधिक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है, जहाँ स्थिरता का महत्त्व नवाचार के समान है, और विचारपूर्ण एकीकरण का महत्त्व तकनीकी महत्वाकांक्षा के समान।

- प्रधान संपादक





विषय सूची

संपादकीय	02
विषय वस्तु	03
महानिदेशक संदेश	05

राज्यों से	
दिल्ली	06
केरलम	12

जिलों से	
झज्जर, हरियाणा	18
मालेरकोटला, पंजाब	20

ई-गवर्नेस उत्पाद एवं सेवाएँ	
ई-डिटेक्शन	22
एच.जी.वी.एम.एस	24
सेवा सेतु शिकायत प्रबंधन ढांचा	26
मिशन भागीरथ	28

सुर्खियों में	
संघमित्रा	31

प्रौद्योगिकी अद्यतन	
आईडीसी तिरुवनंतपुरम् मॉडल	32
एंड्रॉइड के लिए नियतात्मक सत्यापन	34
आधुनिक साइबर सुरक्षा संचालन में सीम की भूमि का	36

ऐपस्केप	42
अंतर्राष्ट्रीय ई-गवर्नेस उत्पाद	44
समाचारों में	46
पुरस्कार	48

अस्वीकरण

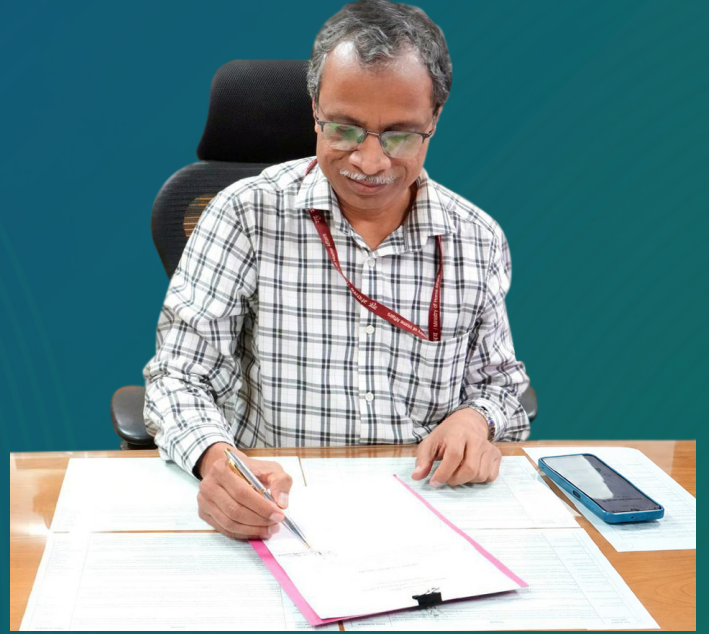
इस प्रकाशन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं, और ये संपादकों या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। साथ ही, लेखों में दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं की सटीकता की जिम्मेदारी लेखकों पर ही होगी।

श्री वी.टी.वी. रमणा ने एनआईसी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया

श्री वी.टी.वी. रमणा ने 8 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के 19वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना तथा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव ऐसे समय में विशेष महत्त्व रखते हैं, जब सुरक्षित एवं सुदृढ़ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना शासन व्यवस्था का एक केंद्रीय आधार बनती जा रही है।



कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री रमणा एनआईसी मुख्यालय में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने भारत सरकार की अनेक महत्त्वपूर्ण साइबर सुरक्षा एवं सूचना सुरक्षा पहलों का नेतृत्व किया। इस दायित्व के अंतर्गत उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर, एनकेएन/ डीआईआई पीएमयू, डेटा सेंटर ऑडिट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ऑडिट तथा एनआईसी सर्विस डेस्क सहित अनेक प्रमुख परिचालन एवं अवसंरचना प्रभागों का समन्वयन किया, जिससे सरकारी डिजिटल प्रणालियों की विश्वसनीयता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला।



विभागाध्यक्ष (हेड ऑफ ग्रुप) के रूप में श्री रमणा ने साइबर एवं सूचना सुरक्षा गवर्नेंस, एनालिटिक्स, मैनेजमेंट तथा सिस्टम्स से संबंधित रणनीतिक प्रभागों का भी नेतृत्व किया। उन्होंने परिचय, जनपरिचय तथा गव-डाइव जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं पहलों के मार्गदर्शन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सरकारी संस्थानों के लिए सुरक्षित डिजिटल पहचान, प्रमाणीकरण एवं सहयोग सेवाओं को सक्षम बनाते हैं।



उनका नेतृत्व दूरसंचार विभाग तथा डाक विभाग के प्रमुख इंफॉर्मेटिक्स प्रभागों तक भी विस्तृत रहा, साथ ही सुरक्षित ई-सेवा वितरण एवं डिजिटल परिवर्तन से संबंधित पहलों में भी उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इन दायित्वों के माध्यम से श्री रमणा ने देशभर में साइबर सुरक्षा ढाँचों, डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों तथा सुरक्षित सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया।

श्री रमणा ऐसे समय में एनआईसी का नेतृत्व संभाल रहे हैं, जब भारत की डिजिटल शासन यात्रा में साइबर सुरक्षा, अंतर-संचालनीयता, विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा बड़े स्तर की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। सूचना सुरक्षा, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा प्रौद्योगिकी संचालन के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव देश में कुशल, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने में एनआईसी की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएगा।



वी.टी.वी. रमणा महानिदेशक

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

प्रिय पाठकों,

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत की डिजिटल शासन यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इसने मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचारी एवं सुरक्षित तकनीकी समाधानों के माध्यम से परिवर्तन को सक्षम बनाया है। वर्षों से, एनआईसी ने मजबूत डिजिटल अवसंरचना विकसित करके तथा नागरिक-केंद्रित प्लेटफॉर्म प्रदान करके विश्वास और विश्वसनीयता का स्थान प्राप्त किया है, जो कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन को समर्थन देते हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकी परिवर्तन की गति अवसरों के साथ-साथ जिम्मेदारियाँ भी प्रस्तुत कर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत विश्लेषण, स्वचालन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकें सरकारों के कार्य करने, सेवाएँ प्रदान करने और सूचित निर्णय लेने के तरीके को पुनर्निर्भाषित कर रही हैं। साथ ही, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण का बढ़ता महत्व निरंतर सतर्कता और मजबूत संस्थागत तैयारी की मांग करता है।

एनआईसी इस डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है। अपने व्यापक संस्थागत अनुभव, देशव्यापी उपस्थिति, समर्पित कार्यबल और सरकारी प्रक्रियाओं के गहन ज्ञान के साथ, यह संगठन भविष्य-उन्मुख शासन प्रणालियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। हमारा ध्यान सुरक्षित, स्केलेबल, समावेशी और सतत डिजिटल समाधानों के निर्माण पर केंद्रित रहेगा, जो नागरिकों और संस्थानों दोनों के लिए वास्तविक मूल्य उत्पन्न करें।

सहयोग की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योगों और अन्य हितधारकों के साथ मजबूत साझेदारी नवाचार को और सशक्त बनाएगी तथा परिणामों को गति प्रदान करेगी। तकनीक को प्रशासनिक समझ के साथ जोड़कर, हम ऐसी प्रणालियाँ विकसित कर सकते हैं जो कुशल, सुलभ और प्रभावशाली हों।

एनआईसी की निरंतर सफलता देशभर में कार्यरत उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, पेशेवर दक्षता और उत्कृष्टता पर आधारित है। उनकी निष्ठा संगठन द्वारा प्राप्त प्रत्येक उपलब्धि की आधारशिला बनी हुई है।

मुझे विश्वास है कि सामूहिक संकल्प और दूरदर्शी सोच के साथ, एनआईसी डिजिटल इंडिया के मिशन तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के व्यापक उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। मैं हमारे सभी पाठकों और हितधारकों को निरंतर सफलता और एक सफल भविष्य यात्रा के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

सादर,
वी.टी.वी. रमणा



दिल्ली एनसीटी

सेवाओं से लेकर स्मार्ट शासन तक

संपादित : विनोद कुमार गर्ग

दिल्ली, जो हमारे राष्ट्र का प्रशासनिक, राजनीतिक और रणनीतिक केंद्र है, ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक शहरी परिवर्तन का एक अन्तः संगम प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली ने हाल के वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावी उपयोग करते हुए शासन तंत्र को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) दिल्ली ने अनेक डिजिटल पहलों का नेतृत्व किया है। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की प्रदायगी को अधिक कुशल बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना तथा शासन में पारदर्शिता को बढ़ाना रहा है।

इन प्रयासों के अंतर्गत ऐसे समेकित, विस्तार योग्य और नागरिक-केंद्रित डिजिटल मंच विकसित किए गए हैं, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकीकृत और सहज पहुँच प्रदान करते हैं। साथ ही, ये मंच विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी बनती है।

दिल्ली जैसे बड़े और विविधतापूर्ण शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन डिजिटल पहलों को डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और स्मार्ट शासन समाधानों के साथ जोड़ा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और लोक प्रशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इन तकनीकी हस्तक्षेपों ने सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता और दक्षता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

यह लेख दिल्ली में लागू प्रमुख आईसीटी पहलों और डिजिटल हस्तक्षेपों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करता है। ये पहलें पारदर्शी,



दिल्ली का डिजिटल परिवर्तन एक ऐसे शासन की ओर संकेत करता है जो अधिक समेकित और नागरिक-केंद्रित है। अब सेवाएँ, प्रशासन, वित्त, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े विभिन्न मंच मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और पहुँच में सुधार हुआ है। ई-डिस्ट्रिक्ट, -आई.एफ.एम.एस, ई-ऑफिस और डी.डी.आई.एस जैसे तंत्र विभागों के बीच बेहतर समन्वय को दर्शाते हैं। साथ ही, डेटा-आधारित उपकरण और मजबूत डिजिटल अवसंरचना यह सुनिश्चित करते हैं कि सेवाएँ आसानी से विस्तारित की जा सकें और आवश्यकताओं के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। कुल मिलाकर, दिल्ली अलग-अलग डिजिटल प्रयासों से आगे बढ़कर एक समेकित, तकनीक-सक्षम शासन प्रणाली के रूप में विकसित हो चुकी है।



उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और "डिजिटल इंडिया" के दृष्टिकोण के अनुरूप एक सशक्त डिजिटल शासन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान दे रही हैं।

राज्य में आईसीटी पहलें

नागरिक मंच

दिल्ली का डिजिटल परिवर्तन नागरिकों को केंद्र में रखते हुए सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाता है, देरी को कम करता है और पारदर्शिता को बढ़ाता है। एकीकृत मंचों के माध्यम से प्रमाणपत्र, पंजीकरण, शिकायतें और कल्याणकारी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे शासन अधिक उत्तरदायी और सुलभ बनता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट

ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली एक प्रमुख मंच है, जो सरकारी सेवाओं की शुरुआत से अंत तक पूरी तरह डिजिटल प्रदायगी सुनिश्चित करता है। इससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल बनती हैं। इसमें एकल साइन-ऑन सुविधा, आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, एकीकृत ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल सहायता जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

यह मंच विभागों के बीच सत्यापन, आवेदनों की वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी, स्वचालित कार्यप्रवाह और ई-एसएलए के माध्यम से समयबद्ध सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करता है। 41 विभागों की 453 से अधिक सेवाओं, 87 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 128 लाख से अधिक निपटाए गए आवेदनों के साथ, ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में डिजिटल शासन का एक मजबूत आधार बन चुका है।

सीएम जन सुनवाई पोर्टल

सीएम जन सुनवाई पोर्टल एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसकी प्रगति देख सकते हैं और सीधे सरकार को प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह वेब, मोबाइल अनुप्रयोग और सीएम हेल्पलाइन (1902) के माध्यम से उपलब्ध है।

यह मंच वास्तविक समय में शिकायत की स्थिति, विभागों को स्वचालित प्रेषण, लंबित मामलों का उच्च स्तर पर भेजना और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है। 21 फरवरी 2026 को पुनः प्रारंभ किया गया यह पोर्टल सहभागितापूर्ण शासन को और मजबूत बनाता है।



नित्तल श्रीनिवास

उप महानिदेशक व एसआईओ
nsrini@nic.gov.in

आरटीआई ऑनलाइन प्रणाली

आरटीआई ऑनलाइन प्रणाली नागरिकों को 200 से अधिक लोक प्राधिकरणों में डिजिटल रूप से सूचना के लिए आवेदन करने की सुविधा देती है। इससे मैनुअल प्रक्रियाएँ कम होती हैं और सूचना तक पहुँच आसान होती है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

एलजी लिसनिंग पोस्ट

एलजी लिसनिंग पोस्ट उपराज्यपाल सचिवालय के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली है, जिसे मोबाइल अनुप्रयोग का समर्थन प्राप्त है। यह शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी और बेहतर समन्वय के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

डीबीटी दिल्ली पोर्टल

डीबीटी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और संसाधनों की हानि कम होती है। यह प्रणाली डीबीटी भारत पोर्टल से जुड़ी हुई है, जिससे लक्षित वितरण, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होता है।

ई-एसएलए

ई-एसएलए प्रणाली “दिल्ली नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011” के तहत सेवाओं की समयसीमा की निगरानी करती है। 48 विभागों और 565 सेवाओं को शामिल करते हुए, यह प्रणाली जवाबदेही को मजबूत बनाती है और सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को सेवाएँ निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हों।

शासन एवं प्रशासन

एनआईसी दिल्ली ने आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर प्रशासन को अधिक दक्ष, समन्वित और डेटा-आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह, बढ़ी हुई पारदर्शिता और वास्तविक समय में जानकारी की उपलब्धता के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया को सशक्त किया गया है।

ई-ऑफिस

ई-ऑफिस मंच ने सरकारी कार्यप्रणाली को कागजरहित और अधिक कुशल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम

दिल्ली की ई-गवर्नेंस यात्रा उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एनआईसी दिल्ली द्वारा विकसित मंच, जैसे सीएम जन सुनवाई, नागरिकों और सरकार के बीच सीधे संवाद को सक्षम बनाकर शिकायत निवारण को सुदृढ़ करते हैं और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ने प्रमाणपत्रों और लाइसेंस जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को एकल डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सरल बनाया है। इन अनुप्रयोगों ने कागजी कार्यवाही को कम किया है, दक्षता में सुधार किया है और समयबद्ध सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की है।

दिल्ली विकास सूचना प्रणाली (डी.डी.आई.एस) एनआईसी दिल्ली की एक अन्य पहल है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास कार्यों की सुव्यवस्थित निगरानी और बेहतर शासन को सक्षम बनाती है। यह प्रस्ताव से लेकर क्रियान्वयन तक संपूर्ण ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है और पारदर्शिता तथा निधियों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है।

मैं एनआईसी, दिल्ली की टीम को उनके प्रयासों और पहलों के लिए बधाई देती हूँ, जिन्होंने दिल्ली सरकार को उसके डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में सहयोग दिया है और एक ऐसा शासन मॉडल विकसित करने में योगदान दिया है जो वास्तव में नागरिकों को सशक्त बनाता है और पारदर्शी तथा उत्तरदायी है।



श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली

से फाइलों का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, संचालन और ट्रैकिंग संभव होती है, साथ ही दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन और अभिलेख रखरखाव भी किया जाता है। कागजी कार्यवाही पर निर्भरता कम होने से पारदर्शिता बढ़ती है, निर्णय लेने की गति तेज होती है और विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है।

स्पैरो

स्पैरो प्रणाली सरकारी अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रक्रिया को डिजिटल बनाती है, जिससे मूल्यांकन अधिक पारदर्शी, मानकीकृत और समयबद्ध होता है। सुरक्षित और केंद्रीकृत सेवा अभिलेखों के साथ ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और प्रसंस्करण की सुविधा, प्रदर्शन प्रबंधन में एकरूपता और जवाबदेही को मजबूत करती है।

डी.डी.आई.एस

डी.डी.आई.एस एक समेकित मंच है, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों की निगरानी करता है और प्रस्ताव से लेकर क्रियान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया का ट्रैक रखता है। इसमें परियोजना

प्रस्ताव दर्ज करना, बहु-स्तरीय स्वीकृतियाँ, धनराशि निर्गमन की निगरानी और प्रगति अद्यतन (फोटो सहित) जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 8,000 से अधिक परियोजनाओं के साथ, इस प्रणाली ने पारदर्शिता, निधियों के उपयोग और निगरानी को काफी मजबूत किया है, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वास्तविक समय डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराए हैं।

दर्पण 2.0

दर्पण 2.0 एक 24x7 वास्तविक समय निगरानी और विश्लेषण मंच है, जो सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की स्थिति पर नजर रखता है। यह प्रवृत्ति विश्लेषण, तुलनात्मक मूल्यांकन और जनसांख्यिकीय प्रोफाइलिंग के माध्यम से उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को सक्षम बनाकर यह नीति निर्माण और प्रदर्शन निगरानी को सुदृढ़ करता है। सफल परीक्षण के बाद इसे सभी विभागों में लागू करने की स्वीकृति मिल चुकी है।

ई-समीक्षा

ई-समीक्षा मंच प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की सतत निगरानी और समीक्षा में सहायता करता है। इसके माध्यम से वास्तविक समय में प्रगति का आकलन, नियमित समीक्षा और समय पर हस्तक्षेप संभव होता है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष डैशबोर्ड उपलब्ध होने से जवाबदेही बढ़ती है और परियोजनाएँ निर्धारित समयसीमा में पूरी होती हैं।

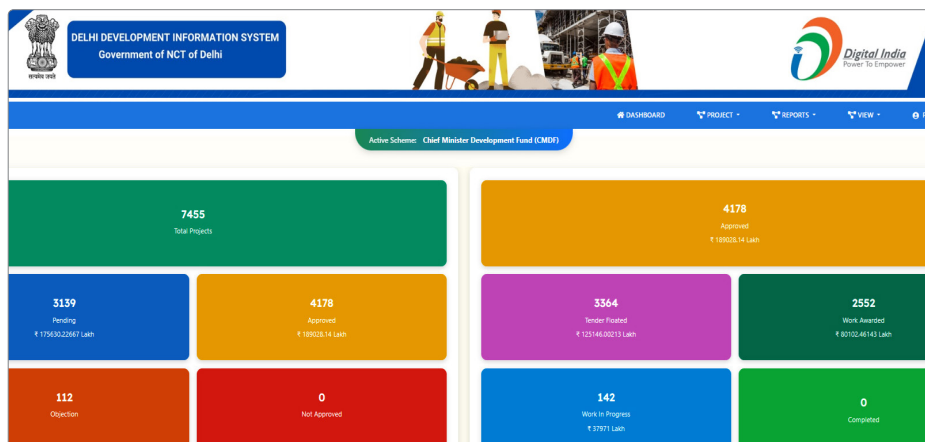
मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रबंधन प्रणाली

यह प्रणाली मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन को डिजिटल माध्यम से सुव्यवस्थित करती है। इसके अंतर्गत बैठकों और नियुक्तियों का केंद्रीकृत निर्धारण, वास्तविक समय अद्यतन और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है, जिससे समय का बेहतर उपयोग और प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।

वित्तीय प्रबंधन एवं सार्वजनिक व्यय प्रणाली

एनआईसी दिल्ली ने डिजिटल वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय शासन को सुदृढ़ किया है, जिससे सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ये मंच बजट निर्माण, बिल प्रसंस्करण, भुगतान और समायोजन की पूरी प्रक्रिया

▼ चित्र 2.1 : डी.डी.आई.एस पोर्टल का होमपेज



दिल्ली में डिजिटल शासन की प्रगति एक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-प्रथम प्रशासन के निर्माण की स्पष्ट दृष्टि को दर्शाती है। ई-डिस्ट्रिक्ट मंच, ई-एसएलए, ई-अबकारी, ई-हॉस्पिटल तथा ईडब्ल्यूएस प्रवेश जैसी पहलें सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के तरीके को परिवर्तित कर चुकी हैं, जिससे ये सेवाएँ अधिक सुलभ, दक्ष और जवाबदेह बनी हैं। इन अनुप्रयोगों ने प्रक्रियागत देरी को कम कर नागरिकों को सशक्त बनाया है और समयबद्ध सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की है।

एक सुदृढ़, सुरक्षित, विस्तार योग्य और समेकित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में एनआईसी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता ने विभिन्न विभागों में ई-गवर्नेंस पहलों के निर्बाध कार्यान्वयन को संभव बनाया है।

आगे बढ़ते हुए, दिल्ली सरकार डिजिटल एकीकरण को और गहरा करने, उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक नागरिक इन प्रगतियों का लाभ उठाए, जिससे शासन अधिक समावेशी, दक्ष और भविष्य के लिए तैयार बन सके।



श्री राजीव वर्मा, आईएएस

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

को डिजिटल बनाते हैं, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है और संसाधनों की हानि को रोका जा सकता है।

आई.एफ.एम.एस

आई.एफ.एम.एस दिल्ली सरकार की वित्तीय गतिविधियों का प्रमुख आधार है, जो वेतन वितरण को सरल बनाता है और बजट, व्यय तथा निधियों के प्रवाह की वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा देता है। इसे 1,700 से अधिक आहरण एवं वितरण अधिकारियों और 25 वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अपनाया गया है।

आई.एफ.एम.एस में केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली, सामान्य भविष्य निधि निगरानी प्रणाली, व्यय समेकन हेतु डी-लेखा, सुरक्षित भुगतान के लिए सरकारी ई-भुगतान द्वार तथा दिल्ली राज्य वस्तु एवं सेवा कर समायोजन प्रणाली जैसे घटक शामिल हैं। साथ ही, आई.एफ.एम.एस दिल्ली मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से कर्मचारी वेतन पर्चों और जीपीएफ विवरण आसानी से देख सकते हैं।

एसएनए-स्पर्श

एसएनए-स्पर्श एक समेकित मंच है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह का प्रबंधन करता है। यह सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर और राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ एकीकृत होकर "आवश्यकतानुसार" निधि जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

और अन्य भुगतानों दोनों का समर्थन करता है, जिससे नकदी प्रबंधन बेहतर होता है और निधियों का वास्तविक समय में पता चलता है।

ई-भुगतान

ई-भुगतान प्रणाली विभिन्न विभागों में सरकारी देयों के डिजिटल संग्रह को सक्षम बनाती है। बैंकिंग मंचों के साथ एकीकरण के माध्यम से नागरिकों और व्यवसायों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है तथा भुगतान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनती है।

ई-प्रोक्वोरमेंट

ई-प्रोक्वोरमेंट प्रणाली खरीद प्रक्रिया के पूरे चक्र को डिजिटल बनाती है, जिसमें निविदा प्रकाशन, बोली प्रस्तुत करना, मूल्यांकन और अनुबंध प्रबंधन शामिल हैं। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करती है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी को आसान बनाती है, जिससे सार्वजनिक खरीद में निष्पक्षता और दक्षता बढ़ती है।

ई-भविष्य

ई-भविष्य प्रणाली पेंशन स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाती है। इसके माध्यम से पेंशन मामलों का प्रारंभ से अंत तक ट्रैक किया जा सकता है, प्रपत्रों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण संभव होता है और एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी मिलती है। इससे देरी और मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है तथा पेंशन लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रदान किए जाते हैं।

दिल्ली एस.जी.एस.टी समायोजन प्रणाली

यह प्रणाली राज्य वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित आंकड़ों के सटीक समायोजन को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के साथ एकीकरण के माध्यम से यह समायोजन प्रक्रिया को स्वचालित बनाती है, जिससे राजस्व लेखांकन की शुद्धता बढ़ती है और वित्तीय पारदर्शिता एवं अनुपालन को सुदृढ़ किया जाता है।

न्याय एवं विधिक पारिस्थितिकी तंत्र

एनआईसी दिल्ली ने डिजिटल मंचों के माध्यम से न्याय प्रणाली को सुदृढ़ किया है, जिससे समन्वय, पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हुई है। सूचना के सहज आदान-प्रदान, डिजिटल कार्यप्रवाह और मामलों की वास्तविक समय में निगरानी के जरिए न्याय प्रदान करने और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनी है।

आई.सी.जे.एस

आई.सी.जे.एस आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख घटकों— पुलिस, न्यायालय, कारागार, अभियोजन और फॉरेंसिक विभाग—के बीच वास्तविक समय में एकीकरण सुनिश्चित करता है। यह मामले से संबंधित जानकारी के सुचारु आदान-प्रदान को सक्षम बनाकर विभिन्न पक्षों के बीच समन्वय बढ़ाता है, जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करता है और न्याय वितरण में पारदर्शिता को मजबूत करता है।

ई-लिटिगेशन

ई-लिटिगेशन प्रणाली सरकारी मामलों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच प्रदान करती है। इसके माध्यम से मामलों का इलेक्ट्रॉनिक दाखिला, ट्रैकिंग और निगरानी संभव होती है, जिससे मैनुअल प्रक्रियाएँ कम होती हैं और विभागों से जुड़े मुकदमों के संचालन में दक्षता और नियंत्रण बढ़ता है।

मेडलीपर

मेडलीपर प्रणाली चिकित्सकीय-वैधानिक और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाती है। यह मानकीकृत प्रारूप, सुरक्षित अभिलेखन और सीसीटीएनएस के साथ एकीकरण के माध्यम से कानूनी प्रक्रियाओं के लिए समय पर जानकारी उपलब्ध कराती है, जिससे कार्यप्रवाह अधिक सुव्यवस्थित और विश्वसनीय बनता है।

आर.सी.एम.एस

राजस्व न्यायालय प्रकरण निगरानी प्रणाली विभिन्न स्तरों—उप मंडलाधिकारी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और वित्त आयुक्त—के न्यायालयों में कार्यवाही को डिजिटल रूप देती है। नागरिक इसके माध्यम से ऑनलाइन याचिका दायर कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, सुनवाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपील का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे राजस्व न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ और पारदर्शी बनती है।

ओ.एस.डब्ल्यू.एस

ओ.एस.डब्ल्यू.एस अधिवक्ताओं के लिए एक डिजिटल एकल खिड़की तंत्र प्रदान करता है, जिसके माध्यम से शुल्क दावों का प्रस्तुतिकरण और प्रसंस्करण पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। इससे भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी बनती है तथा विभागीय कार्यप्रवाह के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होता है।

न्यायालय मामला प्रणाली

दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में विभिन्न डिजिटल प्रणालियाँ लागू की गई हैं, जिनसे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित हुई है। इनमें प्रकरण सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड, ई-फाइलिंग, ई-न्यायालय शुल्क और ई-निरीक्षण जैसी सेवाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ई-कारण सूची, जमानत याचिकाओं का स्वचालित आवंटन और आभासी सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं ने न्यायालयों की पहुँच, दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

यह प्रणाली श्रम से संबंधित मामलों के संपूर्ण डिजिटल प्रबंधन को सक्षम बनाती है। इसमें ऑनलाइन मामला दर्ज करना, सुनवाई प्रबंधन, मामलों का स्थानांतरण और पुनः खोलना, तथा मामले की जानकारी तक सार्वजनिक पहुँच जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। स्वचालित नोटिस और कारण सूची के माध्यम से यह श्रम विवाद निवारण को अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाती है।

स्वास्थ्य सेवाएँ

एनआईसी दिल्ली ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका उद्देश्य बेहतर रोगी देखभाल, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और वास्तविक समय में निर्णय लेने को सक्षम बनाना है। ये मंच अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हैं तथा सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता और त्वरित प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल एक समेकित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल प्रशासन को सुव्यवस्थित करती है। यह रोगी प्रबंधन को सरल बनाती है और निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय में डेटा उपलब्ध कराती है। वर्तमान में इसे दिल्ली के 38 सरकारी अस्पतालों में लागू किया जा रहा है और यह शहर की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रही है।

पी.सी.पी.एन.डी.टी ऑनलाइन फॉर्म-एफ पोर्टल

यह पोर्टल पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जिसके तहत डायग्नोस्टिक केंद्रों, विशेष रूप से निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की डिजिटल रिपोर्टिंग और निगरानी की जाती है। 95 लाख से अधिक फॉर्म-एफ प्रस्तुतियों और 2,400 से अधिक पंजीकृत केंद्रों के साथ, इस मंच ने पारदर्शिता, अनुपालन और नियामक निगरानी को सुदृढ़ किया है।

स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन पोर्टल

स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन पोर्टल दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। यह अस्पताल संसाधनों, बेड उपलब्धता (आईसीयू सहित), रोग निगरानी, दवा आपूर्ति और ऑक्सीजन प्रबंधन को समर्थन देता है, जिससे डेटा-आधारित शासन और प्रभावी स्वास्थ्य प्रशासन संभव होता है।

अस्पताल बेड सूचना मोबाइल अनुप्रयोग

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल से जुड़ा यह मोबाइल अनुप्रयोग नागरिकों को आईसीयू बेड सहित अस्पतालों में उपलब्ध बेड की वास्तविक समय जानकारी प्रदान करता है, जिससे गंभीर उपचार सेवाओं तक समय पर पहुँच सुनिश्चित होती है।

औषधि निगरानी प्रणाली

यह एक वेब-आधारित मंच है, जो नियंत्रित दवाओं की निगरानी करता है और उनके वितरण को व्यवस्थित बनाता है। स्टॉक की जानकारी, बिक्री का रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग की सुविधा के माध्यम से यह दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

नर्सिंग होम प्रबंधन प्रणाली

यह प्रणाली नर्सिंग होम के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और कागजरहित बनाती है। इसमें संस्थान, स्टाफ और सेवाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संकलित की जाती है, साथ ही निरीक्षण और अनुपालन प्रक्रिया को भी समर्थन मिलता है। ऑनलाइन भुगतान, सूचना और रिपोर्टिंग सुविधाओं के माध्यम से यह दक्षता, पारदर्शिता और नियामक निगरानी को मजबूत करती है।

खाद्य नमूना परीक्षण प्रबंधन प्रणाली

यह प्रणाली खाद्य नमूनों के संग्रह, परीक्षण और रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से ट्रैक करती है। समयबद्ध प्रसंस्करण और अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय में निगरानी के माध्यम से यह खाद्य सुरक्षा, अनुपालन और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाती है।

सामाजिक कल्याण प्रणालियाँ

एनआईसी दिल्ली ने डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कल्याणकारी सेवाओं की प्रदायगी को सुदृढ़ किया है, जिससे पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता में वृद्धि हुई है। ये मंच लाभार्थियों के प्रबंधन को सरल बनाते हैं, अनुपालन को बेहतर करते हैं और शहर भर में कल्याण एवं श्रम सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करते हैं।

ई-पीडीएस

ई-पीडीएस (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन के लिए एक पूर्ण डिजिटल मंच है। यह स्मार्ट-पीडीएस से एकीकृत है

और ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से संचालित होता है, जिससे वास्तविक समय में निगरानी, अंतिम चरण पर प्रमाणीकरण और “वन नेशन वन राशन कार्ड” के तहत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है। 72 लाख से अधिक लाभार्थियों और 17 लाख राशन कार्डों की सेवा करते हुए, इस प्रणाली ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और दक्षता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड पोर्टल

यह पोर्टल श्रम कल्याण योजनाओं और श्रम कल्याण निधि के प्रशासन को डिजिटल बनाता है। इसके माध्यम से नियोजित पंजीकरण, ऑनलाइन अंशदान भुगतान, कर्मचारी डेटा प्रबंधन और विभिन्न सूचनाओं तक पहुँच संभव होती है, जिससे श्रम कल्याण सेवाएँ अधिक सुलभ और पारदर्शी बनती हैं।

दुकान एवं स्थापना छूट प्रणाली

यह प्रणाली दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत छूट संबंधी आवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुति और प्रसंस्करण को सक्षम बनाती है। पारदर्शी और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया के माध्यम से यह मैनुअल हस्तक्षेप को कम करती है और व्यापार करने की सुविधा को बेहतर बनाती है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अपनी पत्रिका इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से, दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) के क्रियान्वयन को उजागर करने का प्रस्ताव रखता है। किसी भी विधायी संस्था की प्रतिष्ठा केवल उसकी संवैधानिक परंपराओं की निरंतरता में ही नहीं, बल्कि शासन की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सावधानी और विवेक के साथ स्वयं को ढालने की उसकी क्षमता में भी निहित होती है। इसी भावना के साथ, दिल्ली विधानसभा ने आठवीं विधानसभा के प्रथम भाग के मानसून सत्र के दौरान नेवा का पूर्ण क्रियान्वयन किया, जो उसके कार्यप्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेवा के क्रियान्वयन से विधानसभा को एक अधिक समेकित और दक्ष कार्यप्रणाली की ओर बढ़ने में सहायता मिली है, जहाँ विधायी कार्य समयबद्ध और संरचित डिजिटल पहुँच के माध्यम से समर्थित हैं। अब नोटिस, प्रश्न, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र और कार्यवाही एकीकृत डिजिटल मंच के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिससे सदस्यों की विधायी कार्य में अधिक तत्परता और निरंतरता के साथ भाग लेने में सुविधा होती है। इस परिवर्तन ने कार्य की तैयारी, संचालन और अभिलेखन की प्रक्रिया में एक शांत किंतु स्पष्ट सुधार लाया है, साथ ही संस्थागत अभिलेखों को विश्वसनीय और सुलभ रूप में बनाए रखना भी सुनिश्चित किया है।

इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक स्थिर और सहायक भूमिका निभाई है। उसकी तकनीकी सहायता, विधायी कार्य की प्रक्रियात्मक प्रकृति के साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करती है कि नेवा का क्रियान्वयन सहज और विधानसभा की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह प्रयास स्थापित प्रक्रियाओं के साथ प्रौद्योगिकी के संतुलित समन्वय को दर्शाता है, बिना उस अनुशासन और व्यवस्था को प्रभावित किए जो सदन के संचालन के लिए आवश्यक है।


विस्तृत स्तर पर, यह पहल केवल प्रशासनिक सुविधा तक सीमित नहीं है। एक डिजिटल विधायी ढांचा पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है, सूचना तक पहुँच को बेहतर बनाता है और सदन के भीतर अधिक सूचित सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। यह सार्वजनिक विश्वास को भी मजबूत करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि शासन प्रक्रियाएँ खुली, स्पष्ट और जवाबदेह बनी रहें।

दिल्ली विधानसभा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच यह सहयोग इस बात का एक विचारपूर्ण उदाहरण है कि संस्थाएँ अपनी मूलभूत आधारशिला को बनाए रखते हुए कैसे विकसित हो सकती हैं। मैं एनआईसी की निरंतर प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ और कुशल, पारदर्शी तथा उत्तरदायी विधायी शासन के लिए इस सहयोग को और सुदृढ़ करने की अपेक्षा करता हूँ।

मैं इन्फॉर्मेटिक्स की निरंतर सफलता और इस प्रकार की महत्वपूर्ण पहलों के दस्तावेजीकरण तथा प्रसार के उसके प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।



श्री विजेन्द्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा सदस्य



7152.92 करोड़
17% की वृद्धि


4079+
लाइसेंसधारी


70+ करोड़
बोतलों की बिक्री


12+ करोड़
बोतलों का स्टॉक


34,465
आयात परमित


6,520
पारगमन परिवहन परमित


16,94,667
परिवहन परमित

▲ चित्र 2.2

ई-अबकारी प्रणाली का सांख्यिकीय अवलोकन

तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—में ऑनलाइन प्रवेश के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करती है। यह ऑनलाइन पंजीकरण, विकल्प भरना और सीटों का स्वचालित आवंटन सक्षम बनाती है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी, दक्ष और छात्र-अनुकूल बनती है तथा प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता कम होती है।

ईडब्ल्यूएस शिक्षा पोर्टल

ईडब्ल्यूएस शिक्षा पोर्टल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है और सीट आवंटन को पारदर्शी बनाकर समावेशिता को बढ़ावा देता है तथा वंचित वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करता है।

डी.एस.एस.बी ओएआरएस

डी.एस.एस.बी ओएआरएस मंच दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रियाओं के संपूर्ण डिजिटल प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इसके माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन प्रस्तुत करना, शुल्क भुगतान और अभ्यर्थियों के साथ संवाद संभव होता है। यह बड़े पैमाने पर होने वाली भर्तियों को कुशलतापूर्वक संचालित करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करता है।

ई-अबकारी

ई-अबकारी प्रणाली आबकारी कार्यों के प्रबंधन के लिए एक

▼ चित्र 2.3 : ईफिल्म क्लीयरेंस पोर्टल

समग्र डिजिटल मंच है, जो लाइसेंस, परमित और मदिरा के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल रूप से संचालित करता है। यह लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण, परमित निर्माण, भंडार निगरानी, लेबल पंजीकरण और शुल्क प्रबंधन को समर्थन देता है, साथ ही निरीक्षण निगरानी और बारकोड आधारित ट्रैकिंग के माध्यम से प्रवर्तन को भी सुदृढ़ करता है। एकीकृत डैशबोर्ड निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। दिल्ली ई-अबकारी मोबाइल अनुप्रयोग उपयोगकर्ताओं को विक्रय केंद्रों का पता लगाने, उत्पाद की प्रामाणिकता की जाँच करने, शुष्क दिवस देखने और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।

व्यवसाय, विनियमन एवं व्यापार करने में सुगमता

एनआईसी दिल्ली ने नियामक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया है। लाइसेंस, स्वीकृतियाँ, निरीक्षण और अनुपालन को सरल बनाकर इन मंचों ने देरी कम की है, प्रत्यक्ष संपर्क को घटाया है और पारदर्शिता बढ़ाई है, जिससे एक अधिक कुशल और व्यापार-अनुकूल वातावरण विकसित हुआ है।

दिल्ली एकल खिड़की प्रणाली (उद्योग हेतु)

दिल्ली एकल खिड़की प्रणाली (उद्योग हेतु) व्यवसायों को विभिन्न विभागों से स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए

एक एकीकृत इंटरफेस प्रदान करती है। यह ऑनलाइन आवेदन, वास्तविक समय ट्रैकिंग, एकीकृत कार्यप्रवाह और समयबद्ध सेवा प्रदायगी को सक्षम बनाती है, जिससे कागजी कार्यवाही कम होती है, समन्वय बेहतर होता है और व्यापार करने की सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होता है।

डी-सीआईएस

दिल्ली केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (डी-सीआईएस) विभिन्न विभागों में निरीक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है। यह दोहराव को समाप्त कर मानकीकृत प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करती है, जिससे प्राधिकरणों के बीच समन्वय बेहतर होता है, व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम होता है और एक पारदर्शी तथा पूर्वानुमेय निरीक्षण ढांचा विकसित होता है।

ई-फिल्म अनुमति प्रणाली

ई-फिल्म अनुमति प्रणाली दिल्ली में फिल्मों के अनुमति प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की मंच प्रदान करती है। यह विभिन्न विभागों को एकीकृत कार्यप्रवाह में जोड़कर ऑनलाइन आवेदन, त्वरित स्वीकृति और कम कागजी कार्यवाही सुनिश्चित करती है, जिससे दिल्ली को फिल्म-अनुकूल गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलता है और नियामक अनुपालन भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित होता है।

मुख्य शासन प्रणालियों से परे, एनआईसी दिल्ली ने विधायी प्रक्रियाओं, संपत्ति पंजीकरण, भूमि प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन का विस्तार किया है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सुविधा में वृद्धि हुई है।

दिल्ली नेवा परियोजना

दिल्ली नेवा (राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग) परियोजना का शुभारंभ 3 अगस्त 2025 को दिल्ली विधानसभा में किया गया, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्णतः डिजिटल और कागजरहित विधायी कार्यप्रवाह को सक्षम बनाती है।

यह प्रश्न, नोटिस, विधेयक और कार्यवाही के वास्तविक समय प्रबंधन के साथ-साथ स्वचालित कार्यप्रवाह और डिजिटल अभिलेखन का समर्थन करती है। 100 दिनों की त्वरित अवधि में लागू यह मंच विधायकों और अधिकारियों के लिए पारदर्शिता, पहुँच और डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है। समर्पित नेवा सेवा केंद्रों और परिचालन समर्थन के साथ, दिल्ली इस प्रणाली को अपनाने वाली 20वीं विधानसभा बन गई है, जो “एक राष्ट्र, एक अनुप्रयोग” के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।

एन.जी.डी.आर.एस

एन.जी.डी.आर.एस (राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली) संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण, समय निर्धारण, ई-स्टाम्प एकीकरण, शुल्क की स्वचालित गणना और वास्तविक समय स्थिति ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। भौतिक उपस्थिति को कम करते हुए और प्रक्रियाओं का मानकीकरण करते हुए, यह पारदर्शिता में सुधार करता है और संपत्ति लेन-देन को सरल बनाता है।

वाहन स्थान ट्रैकिंग एवं आपातकालीन अलर्ट प्रणाली (वीएलटी एवं ईएसएस)

वीएलटी एवं ईएसएस वास्तविक समय जीपीएस ट्रैकिंग और निगरानी के माध्यम से वाहन सुरक्षा को बढ़ाता है। यह अधिकारियों को वाहनों की गतिविधि पर नजर रखने और अनुपालन सुनिश्चित





▲ चित्र 2.4 : दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर 'सीएम जनसुनवाई पोर्टल' का शुभारंभ किया

करने में सक्षम बनाता है। आपातकालीन अलर्ट सुविधा तुरंत संकट संकेत नियंत्रण केंद्र तक भेजती है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया, बेहतर यात्री सुरक्षा और प्रभावी घटना प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

भूमि अभिलेख प्रणाली

भूमि अभिलेख प्रणाली भूमि स्वामित्व, रिकॉर्ड और लेनदेन को डिजिटलाइज करती है, जिससे पारदर्शिता और आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। यह विवादों को कम करती है, सटीकता बढ़ाती है, ऑनलाइन सत्यापन सक्षम बनाती है और नागरिकों तथा अधिकारियों के लिए भूमि प्रशासन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है।

मापतोल पोर्टल

मापतोल पोर्टल विधिक माप विज्ञान विभाग को माप उपकरणों के सत्यापन और प्रमाणन की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है, साथ ही शिकायत दर्ज करने और उसकी निगरानी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। मोबाइल अनुप्रयोग और वास्तविक समय निरीक्षण क्षमताओं के माध्यम से, यह उपभोक्ता संरक्षण, नियामक दक्षता और प्रवर्तन में पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है।

नेटवर्क एवं अवसंरचना सेवाएँ

एक सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना दिल्ली के ई-गवर्नेंस तंत्र की आधारशिला है, जो सुरक्षित कनेक्टिविटी, निर्बाध संचार और

विभिन्न विभागों में विश्वसनीय सेवा प्रदायगी को सक्षम बनाती है। यह नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और आंतरिक प्रशासनिक कार्यों दोनों का समर्थन करती है, जिससे शासन में विस्तार क्षमता, दक्षता और निरंतरता सुनिश्चित होती है।

दिल्ली राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (डी.एस.डब्ल्यू.ए.एन) इस तंत्र की रीढ़ के रूप में कार्य करता है, जो 185 से अधिक सरकारी स्थलों को 240 से अधिक समर्पित लीड लाइनों के माध्यम से उच्च गति और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह स्थानीय नेटवर्क प्रबंधन, इंटरनेट और ईमेल सेवाएँ, क्लाउड पहुँच, वीपीएन कनेक्टिविटी, वेब होस्टिंग और वाई-फाई जैसी सेवाओं का समर्थन करता है, जिससे वास्तविक समय में संचार और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय संभव होता है।

एनजीसी क्लाउड सेवाएँ अनुप्रयोगों और डेटा की होस्टिंग के लिए एक सुरक्षित और विस्तार योग्य वातावरण प्रदान करती हैं, जिससे विभाग तेजी से सेवाएँ लागू कर सकते हैं और केंद्रीकृत संसाधन प्रबंधन के माध्यम से अवसंरचना का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) कर्मचारियों की उपस्थिति की वास्तविक समय में निगरानी को सक्षम बनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता

में सुधार होता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ राज्य और जिला स्तर पर आभासी बैठकों को सक्षम बनाती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होती है, यात्रा की आवश्यकता कम होती है और शासन की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

इन सभी पहलों के माध्यम से एक सुदृढ़ डिजिटल आधार तैयार होता है, जो दिल्ली में दक्ष, सुरक्षित और विस्तार योग्य ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाता है।

एनआईसी राज्य कार्यालय से संबंधित कार्यक्रम

- माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के साथ सीएम जन सुनवाई पोर्टल, सीएससी डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ तथा ईडब्ल्यूएस प्रवेश पोर्टल का उद्घाटन किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा मेडलीपर प्रणाली का उद्घाटन किया गया।
- दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिल्ली नेवा परियोजना का उद्घाटन किया गया।

अग्रिम दिशा

आगे बढ़ते हुए, गहन एकीकरण, परस्पर कार्य-संगतता और डेटा-आधारित शासन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विश्लेषण के उपयोग से सक्रिय सेवा प्रदायगी को सक्षम बनाया जा सकता है। साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना, क्षमता निर्माण और मोबाइल-प्रथम समावेशी पहुँच सुनिश्चित करना प्रमुख प्राथमिकताएँ होंगी। नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने और एकीकृत मंचों के विस्तार से पारदर्शिता और दक्षता में और सुधार किया जा सकता है, जिससे दिल्ली एक अधिक बुद्धिमान और सुदृढ़ शासन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर होगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी दिल्ली राज्य केंद्र
बी विंग, लेवल-7, दिल्ली सचिवालय
नई दिल्ली, दिल्ली - 110002
ईमेल: sio-del@nic.in, फ़ोन: 011-23392184

▼ चित्र 2.5 : नेवा दिल्ली विधानसभा पोर्टल

The screenshot shows the Delhi Legislative Asses portal. At the top, there are navigation tabs: 'आज कार्य प्रश्न विधायी कार्य समिति सदस्य शिफ्ट परतलकालस वाद-निवाद संके'.

The main content area is divided into two sections:

- सूचना पृष्ठ** (Information Page): A list of bills with their titles and dates.
 - दिल्ली दूकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 - (28/03/2026)
 - दिल्ली जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 - (28/03/2026)
 - न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 - (28/03/2026)
 - दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, वर्ष 2026 - (28/03/2026)
 - दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, वर्ष 2026 - (28/03/2026)
 - बुलेटिन भाग I संख्या 26 (26 मार्च 2026) - (27/03/2026)
 - संशोधित कार्य-सूची (26 मार्च 2026) - (27/03/2026)
- सत्र कैलेंडर** (Session Calendar): A calendar for April 2026 showing the dates of the session. The calendar is for the 10th day of the session.

At the bottom, there are navigation buttons: 'नौटिस प्राप्त', 'प्रश्न', 'सरकारी विधेयक', 'परतल पर रखे गये कावस्थि', 'समिति की रिपोर्ट', and 'सदस्य'.

केरल राज्य

प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन एवं नागरिक सेवाओं का रूपांतरण

संपादित : विनोद कुमार गर्ग

तीन दशकों से अधिक समय से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केरल राज्य में डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस पहलों, सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना तथा नवोन्मेषी आईसीटी समाधानों के माध्यम से एनआईसी केरल ने राज्यभर में पारदर्शी, कुशल एवं उत्तरदायी शासन सुनिश्चित किया है।

कृषि सेवाओं के आधुनिकीकरण से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डिजिटल भूमि प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और चुनाव प्रबंधन समाधानों तक, एनआईसी केरल ने राज्य की डिजिटल यात्रा में एक प्रमुख तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य किया है। केन्द्र द्वारा विकसित विभिन्न मिशन-क्रिटिकल प्लेटफॉर्मों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया, सेवा वितरण में सुधार किया तथा नागरिकों के लिए सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाया है।

एनआईसी केरल का योगदान केवल एप्लीकेशन विकास तक सीमित नहीं है। सुदृढ़ नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्लाउड सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना, साइबर सुरक्षा सहायता तथा डिजिटल संचार प्लेटफॉर्मों के माध्यम से राज्य में एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया गया है, जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करता है। ई-ऑफिस केरल, रिलिस, के-स्विफ्ट, आईएफएमएस, स्पार्क तथा संदेश जैसी पहलें नवाचार-आधारित शासन एवं डिजिटल सशक्तीकरण के प्रति केन्द्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

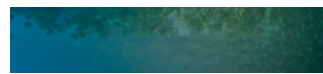
केरल एक प्रगतिशील डिजिटल राज्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में एनआईसी केरल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्मों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहा है, ताकि शासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पारदर्शिता, समावेशन तथा भविष्य उन्मुख डिजिटल अवसंरचना पर विशेष ध्यान



डॉ. सुचित्रा प्यारेलाल
उप महानिदेशक व एसआईओ
suchitra@nic.in



एनआईसी केरल ने कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव, भूमि प्रशासन तथा सार्वजनिक प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60 से अधिक आईसीटी पहलों को लागू कर राज्य में डिजिटल शासन को सशक्त बनाया है। ई-ऑफिस केरल, आईएफएमएस, स्पार्क, रिलिस, के-स्विफ्ट तथा ई-डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफॉर्मों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया, पारदर्शिता बढ़ाई तथा नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। एनआईसीनेट, एनकेएन, क्लाउड सेवाओं तथा आधार-सक्षम प्रणालियों जैसी डिजिटल अवसंरचना के सहयोग से एनआईसी केरल राज्य में प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।



देते हुए एनआईसी केरल राज्य के लिए एक स्मार्ट, रपरस्पर जुड़ी तथा नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राज्य में आईसीटी पहलें

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (ए.आई.एम.एस)

एआईएमएस किसानों को पंजीकरण, भूमि एवं फसल विवरण दर्ज करने तथा कृषि विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) केरल, राज्य भर में वित्तीय लेनदेन के कुशल प्रबंधन और निष्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देती है। विभिन्न विभागों में व्यापक और सहयोगात्मक डिजिटलीकरण को सक्षम करके और विविध हितधारकों को जोड़कर, यह प्रणाली निर्बाध डेटा सत्यापन सुनिश्चित करती है, डेटा-संचालित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही को मजबूत करती है।

मैं इस परिवर्तनकारी पहल में शामिल सभी विभागों की सराहना करता हूँ, जिसमें वित्त और कोष (ट्रेजरी) विभागों को उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केरल को तकनीकी आधार और निरंतर सहयोग प्रदान करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष मान्यता देता हूँ।

मैं निरंतर सहयोग और निरंतर प्रगति के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हम सार्वजनिक वित्तीय प्रणालियों के डिजिटल परिवर्तन में और भी बड़े मील के पत्थर हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।



डॉ. ए. जयतिलक, आईएसएस
मुख्य सचिव

विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करने हेतु एकल-विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। किसान फसल बीमा, फसल क्षति सहायता, खेती योग्य धान भूमि हेतु रॉयल्टी सहायता तथा अन्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों का प्रसंस्करण कृषि भवन, ब्लॉक, जिला तथा निदेशालय स्तर पर डिजिटल माध्यम से



▲ चित्र 3.1 : माननीय प्रधानमंत्री की केरल यात्रा, एनआईसी केरल द्वारा दिया गया आईसीटी समर्थन

किया जाता है। यह प्रणाली केंद्रीकृत डीबीटी मॉड्यूल एवं राज्य कोषागार के साथ एकीकृत है, जिससे लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं।

एग्रो सर्विसेज एवं हायरिंग सेंटर गतिविधियों के लिए ऑटोमेशन सिस्टम (आशा)

आशा एक ऑनलाइन वर्कफ्लो एवं लेखा प्रणाली है, जिसे कृषि सेवाएं प्रदान करने वाले केन्द्रों जैसे कृषि मशीनरी किराया सेवा एवं कृषि तकनीशियन सहायता के लिए विकसित किया गया है। किसान सेवा केन्द्रों, मशीनरी की उपलब्धता, किराया शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन सेवाएं बुक कर सकते हैं। यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को बुकिंग की स्थिति देखने, बिल प्राप्त करने तथा डिजिटल माध्यम से ग्राहक खातों का प्रबंधन करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

फार्म मैकेनाइजेशन सिस्टम (एफएमएस)

एफएमएस कृषि मशीनरी की खरीद से संबंधित सब्सिडी प्रबंधन हेतु विकसित एक वर्कफ्लो आधारित एप्लीकेशन है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण, सत्यापन तथा सब्सिडी स्वीकृति की सुविधा प्रदान करता है। स्वीकृत सब्सिडी ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जाती है।

डेयरी विकास विभाग

क्षीरश्री

क्षीरश्री एक वेब-सक्षम प्लेटफॉर्म है, जो डेयरी सहकारी समितियों, डेयरी किसानों तथा डेयरी विकास विभाग के लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रणाली किसान पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी चयन, वर्कफ्लो आधारित स्वीकृति तथा सब्सिडी वितरण की सुविधा प्रदान करती है। पोर्टल को दूध

▼ चित्र 3.3 : एनआईसी केरल द्वारा विकसित क्षीरश्री पोर्टल का उद्घाटन



विक्षेपक मशीनों, वजन मशीनों तथा डिस्पले उपकरणों के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे दूध गुणवत्ता मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

नागरिक आपूर्ति विभाग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्लेटफॉर्म सीएससी तथा नागरिक पोर्टलों के माध्यम से राशन कार्ड प्रबंधन से संबंधित डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। यह एनएफएसए प्रावधानों के अंतर्गत राशन कार्डों

▼ चित्र 3.2 : डायरेक्ट-सेलिंग-बिजनेस-पोर्टल का शुभारंभ एनआईसी केरल द्वारा विकसित पोर्टल



के वर्गीकरण तथा समावेशन एवं बहिष्करण मानदंडों के आधार पर डिजिटल लाभार्थी पहचान का समर्थन करता है।

डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पोर्टल

डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पोर्टल को उपभोक्ता संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 के अंतर्गत केरल में डायरेक्ट सेलिंग

संस्थाओं के पंजीकरण एवं निगरानी हेतु प्रारंभ किया गया। यह द्विभाषीय पोर्टल वर्कफ्लो आधारित प्रबंधन तथा नियामक निगरानी का समर्थन करता है।

एंटे राशन कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन

“एंटे राशन कार्ड” मोबाइल एप्लीकेशन नागरिकों को राशन कार्ड विवरण, आवेदन स्थिति तथा संबंधित ई-सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन डिजिटल राशन कार्ड डेटा का उपयोग कर राशन खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है।

ई-कार्ड प्रणाली

ई-कार्ड प्रणाली नागरिकों को नए राशन कार्ड हेतु आवेदन करने अथवा मौजूदा राशन कार्ड में संशोधन करने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान करती है, जिससे कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। स्वीकृत द्विभाषीय ई-कार्ड डाउनलोड कर देशभर में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आई.एम.पी.डी.एस) के अंतर्गत उपयोग किए जा सकते हैं।

लीगल मेट्रोलाजी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (एल.एम.ओ.एम.एस)

एल.एम.ओ.एम.एस निर्माताओं, डीलरों एवं रिपेयरर्स के लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल पैकर्स एवं आयातकों के पंजीकरण तथा माप एवं तौल सत्यापन सेवाओं का भी समर्थन करता है।

स्टेट फूड कमीशन केरल पोर्टल

यह पोर्टल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से संबंधित सूचनाओं के प्रसार तथा राज्य खाद्य आयोग की जागरूकता एवं शिकायत निवारण गतिविधियों का समर्थन करता है।

सिविल सप्लाइज पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल

यह शिकायत पोर्टल नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। शिकायतों के साथ ऑडियो एवं वीडियो फाइलों सहित सहायक प्रमाण भी अपलोड किए जा सकते हैं। प्रणाली शिकायतों के रूटिंग, निगरानी तथा फीडबैक आधारित शिकायत निवारण तंत्र का समर्थन करती है।

शिक्षा विभाग

आई-एग्जाम्स-एचएसई एवं आई-एग्जाम्स-वी.एच.एस.ई

आई-एग्जाम्स एक ओपन-सोर्स वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसे उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक उच्च माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक समकक्ष परीक्षाओं के प्रबंधन हेतु विकसित किया गया

है। यह प्लेटफॉर्म अभ्यर्थी पंजीकरण से लेकर परिणाम प्रसंस्करण एवं प्रकाशन तक की सभी गतिविधियों का समर्थन करता है।

एचएसकैप

एचएसकैप केरल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्लस वन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली है। छात्र एकल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अनेक विद्यालय एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन कर सकते हैं।

स्कॉलरशिप पोर्टल

स्कॉलरशिप पोर्टल डीसीई, डीएमडब्ल्यू तथा एचईसी सहित विभिन्न विभागों की छात्रवृत्ति एवं मेधावी पुरस्कार योजनाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है। विद्यार्थी निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

केरल डिफरेंशियल एडीट्यूड टेस्ट (के-डैट)

के-डैट एक ऑनलाइन अभिरुचि मूल्यांकन प्रणाली है, जिसे कक्षा 10 पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च माध्यमिक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म परामर्श एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स एवं चार्ट तैयार करता है।

स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन्स (एस.बी.टी.ई) पोर्टल

एसबीटीई पोर्टल केरल के पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी गतिविधियों के ऑनलाइन प्रबंधन का समर्थन करता है। इसमें प्रवेश, परीक्षा तथा परिणाम प्रबंधन जैसी सेवाएं शामिल हैं।

निर्वाचन विभाग

स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल

यह पोर्टल निर्वाचन नामावली प्रबंधन, मतदान गतिविधियों, मतगणना संचालन तथा स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम एवं सांख्यिकीय जानकारी के प्रकाशन का समर्थन करता है।

ऑफिशियल्स रैंडमली डिप्लॉयड फॉर इलेक्शन केरल (ऑर्डर)

ऑर्डर चुनावों के दौरान मतदान अधिकारियों की यादृच्छिक

नियुक्ति हेतु विकसित वेब-आधारित समाधान है। यह प्रणाली तीन-स्तरीय रैंडमाइजेशन के माध्यम से अधिकारियों को डिजिटल रूप से मतदान केन्द्रों पर नियुक्त करती है।

ट्रेंड

ट्रेंड का उपयोग मतदान प्रतिशत एवं मतगणना आंकड़ों सहित चुनाव संबंधी डेटा के संग्रहण एवं प्रसार हेतु किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म टेबल-वार मतगणना डेटा एकत्र कर मतदान प्रतिशत एवं परिणाम प्रकाशित करता है।

पोल मैनेजर

पोल मैनेजर में चुनावों के दौरान मतदान गतिविधियों के प्रबंधन हेतु विकसित मोबाइल एप्लीकेशन्स, पोर्टल्स एवं डैशबोर्ड शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय का समर्थन करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

ई-ऑफिस केरल

ई-ऑफिस केरल को सचिवालय विभागों, जिला कलेक्टरट्स, तालुक कार्यालयों, ग्राम कार्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में लागू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म फाइलों की आवाजाही एवं कार्यालय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करता है। सहायक एप्लीकेशन्स में ई-तपाल, आरटीआई पोर्टल, कोर्ट केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम तथा कर्मचारी शिकायत प्रबंधन पोर्टल शामिल हैं।

ई-एप्लीकेशन

ई-एप्लीकेशन नागरिकों को सीधे अथवा अक्षय केन्द्रों के माध्यम से सरकार को ऑनलाइन आवेदन एवं याचिकाएं प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है।

ई-ऑफिस सिटिजन पोर्टल

यह पोर्टल नागरिकों को ई-ऑफिस सांख्यिकी के साथ-साथ फाइल खोज, सरकारी आदेश खोज तथा रसीद ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट केरल

ई-डिस्ट्रिक्ट केरल, एनईजीपी के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य कॉमन सर्विस सेंटरों, सार्वजनिक पोर्टलों तथा विभागीय कार्यालयों के माध्यम से सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करना है। यह प्लेटफॉर्म स्थानीय स्तर पर कुशल एवं पारदर्शी सेवा वितरण का समर्थन करता है।

ई-प्रोक्योरमेंट केरल

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल जीईपीएनआईसी प्रणाली का उपयोग करते हुए केरल में सरकारी निविदा गतिविधियों हेतु एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह ऑनलाइन निविदा प्रकाशन, बोली प्रस्तुतिकरण, भुगतान प्रसंस्करण तथा बोली खोलने की प्रक्रिया का समर्थन करता है।

वित्त विभाग

इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आई.एफ.एम.एस)

आई.एफ.एम.एस एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, जो वित्त विभाग, कोषागार विभाग, आरबीआई, लेखा महानियंत्रक तथा अन्य हितधारकों को जोड़ता है। यह प्रणाली कोषागार के एंड-टू-एंड आधुनिकीकरण तथा स्पार्क, पीएफएमएस, ई-कुबेर एवं प्लानस्पेस जैसी एप्लीकेशन्स के साथ एकीकरण का समर्थन करती है।

सर्विस एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपॉजिटरी फॉर केरल (स्पार्क)

स्पार्क सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत मानव संसाधन, वेतन एवं स्थापना प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रणाली विभागों, विद्यालयों, न्यायपालिका एवं विश्वविद्यालयों में कार्मिक अभिलेख, वेतन प्रसंस्करण तथा प्रशासनिक सेवाओं का केंद्रीकृत प्रबंधन करती है।

बजट वेब पोर्टल

बजट वेब पोर्टल केरल सरकार के बजट की तैयारी एवं प्रबंधन का समर्थन करता है। इसमें बजट अनुमान, बजट प्रकाशन तथा अनुपूर्क आवंटन एवं निधि विनियमन जैसी बजट-पश्चात गतिविधियां शामिल हैं।

ई-अनुमति

ई-अनुमति एक वर्कफ्लो आधारित सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करने तथा व्यय ट्रैकिंग के लिए किया जाता है।

बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम (बीडीएस)

बीडीएस ठेकेदारों को स्वीकृत बिलों के विरुद्ध सहभागी बैंकों के माध्यम से रियायती भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म प्रतिज्ञा पत्र जारी करने तथा बिल भुगतान के डिजिटल प्रसंस्करण का समर्थन करता है।

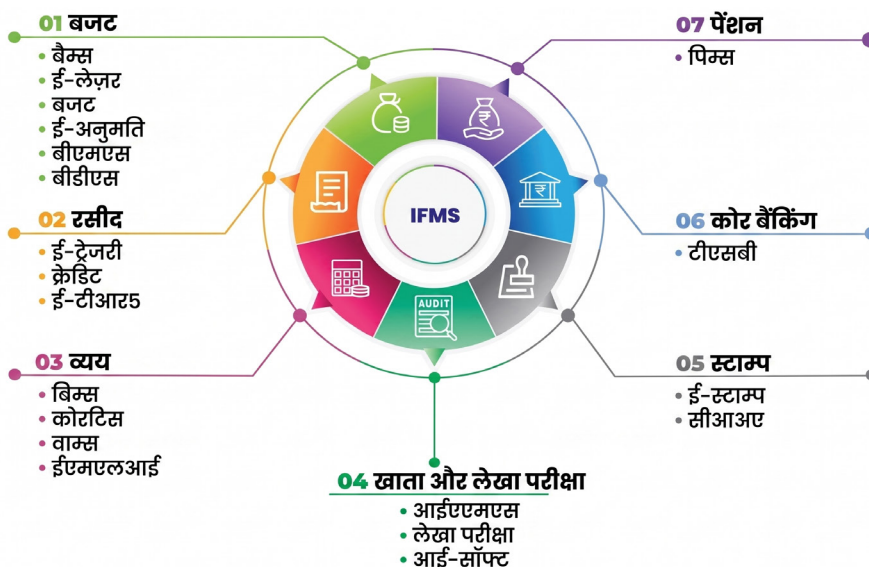
इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूअंस (ई.एम.एल.आई)

ई.एम.एल.आई सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने हेतु विकसित वेब-आधारित प्रणाली है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बिल प्रसंस्करण, निधि आवंटन तथा सरकारी आदेश जारी करने का समर्थन करता है।

गेनपीएफ-आई.एफ.एम.एस

गेनपीएफ-आई.एफ.एम.एस केरल के सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए विकसित वेब-आधारित भविष्य निधि निगरानी प्रणाली है।

चित्र 3.4 आई.एफ.एम.एस का कार्यप्रवाह



यह प्रणाली विभिन्न विभागों के अंतर्गत संस्थानों के पीएफ खातों, अग्रिमों एवं वर्कफ्लो आधारित प्रसंस्करण का प्रबंधन करती है।

लेजिस्लेटिव असेम्बली कॉन्स्टिट्यूएन्सी - एसेट डेवलपमेंट स्कीम पोर्टल

यह पोर्टल विधायकों द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र परिसंपत्ति विकास कार्यों की स्वीकृति एवं निगरानी का समर्थन करता है। यह विभिन्न सरकारी विभागों में वर्कफ्लो आधारित अनुमोदन एवं वित्तीय सहमति तंत्र प्रदान करता है।

गजेटेड एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (जेम्स)

जेम्स केरल के राजपत्रित अधिकारियों के वेतन निर्धारण, अवकाश एवं पेंशन संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करता है। यह प्रणाली पदोन्नति, ग्रेड निर्धारण तथा अन्य सेवा-संबंधी अधिकारों के प्रसंस्करण का समर्थन करती है।

पेंशनर वेब मैनेजमेंट सिस्टम

पेंशनर वेब मैनेजमेंट सिस्टम केरल में लेखा महानियंत्रक कार्यालयों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं एवं प्रबंधन का समर्थन करता है।

अकाउंटेंट जनरल जीपीएफ वेब पोर्टल

जीपीएफ पोर्टल राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का प्रबंधन करता है। इसमें खाता निर्माण, अग्रिम, निकासी तथा खाते बंद करने जैसी गतिविधियां वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

मात्स्य विभाग

रीयलक्राफ्ट

रीयलक्राफ्ट तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु विकसित एक राष्ट्रीय डेटाबेस प्रणाली है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने वाले नौकाओं के पंजीकरण एवं निगरानी के लिए किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक नौका को विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान करता है तथा तटीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त यह मछुआरों के लिए सब्सिडी एवं बीमा सहायता भी उपलब्ध कराता है।

फिशरीज इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (फिम्स)

फिम्स मछुआरा परिवार रजिस्टर के ऑनलाइन प्रबंधन तथा कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन हेतु विकसित वर्कफ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली आधार विवरण, बैंक खाते, व्यवसाय, शैक्षणिक स्थिति तथा नौका स्वामित्व संबंधी

चित्र 3.5 : रीअल-क्राफ्ट डैशबोर्ड



▲ चित्र 3.6 : आयुष क्षेत्र के लिए आईटी समाधानों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

जानकारी संग्रहीत करती है, जिससे योजनाओं के प्रसंस्करण एवं डीबीटी आधारित लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया जाता है।

सिस्टम फॉर ईजी एंड लीगल इश्यूअंस ऑफ फ्यूल परमिट्स एंड फ्यूल (सेल्फ)

सेल्फ रीयलक्राफ्ट, फिम्स तथा सागरा से जुड़ी एक एकीकृत वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है, जिसका उपयोग पंजीकृत नौका स्वामियों को ईंधन कार्ड वितरण एवं ईंधन परमिट जारी करने हेतु किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म मछुआरों के लिए ईंधन वितरण से संबंधित एंड-टू-एंड डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग

कोर्ट केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सी.सी.आई.एस)

सी.सी.आई.एस सरकारी विभागों से संबंधित न्यायालयीन मामलों के डिजिटल प्रसंस्करण एवं प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली विभागों तथा महाधिवक्ता कार्यालय के बीच दस्तावेजों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाती है।

गेस्ट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम

गेस्ट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम नागरिकों को सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सरकारी अतिथि गृहों एवं सम्मेलन हॉल की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल आवेदन प्रसंस्करण, बुकिंग स्वीकृति तथा एसएमएस आधारित स्थिति अद्यतन का समर्थन करता है।

जीवन रेखा

जीवन रेखा केरल में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण बोर्ड

पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए विकसित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्लेटफॉर्म है। पेंशनभोगी अक्षय केन्द्रों के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाणन पूर्ण कर सकते हैं।

सरकार डायरी

सरकार डायरी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो केरल के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सरकारी कार्यालयों की संपर्क जानकारी उपलब्ध कराता है। यह एप्लीकेशन सरकारी निर्देशिका प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत है, जिससे वार्षिक अद्यतन एवं डिजिटल पहुंच सुनिश्चित होती है।

स्वास्थ्य विभाग

लैब डायग्नोसिस मैनेजमेंट सिस्टम (लैबिसिस पोर्टल)

लैब डायग्नोसिस मैनेजमेंट सिस्टम (लैबिसिस पोर्टल) सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए डायग्नोस्टिक परीक्षणों की निगरानी हेतु विकसित वेब-आधारित पोर्टल है। यह प्लेटफॉर्म परीक्षण डेटा, अस्पताल में भर्ती विवरण तथा रोग प्रवृत्तियों को ट्रैक कर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी एवं प्रतिक्रिया का समर्थन करता है।

केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पोर्टल

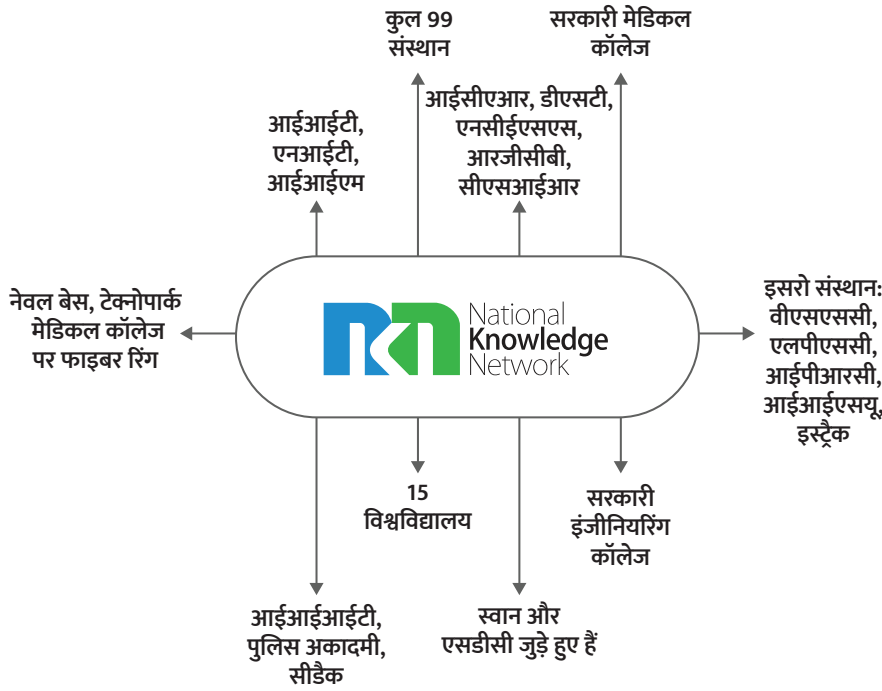
यह पोर्टल केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 2018 के अंतर्गत क्लिनिकल संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन का समर्थन करता है। इसमें आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के संस्थान शामिल हैं।

केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (के-सोटी)

केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (के-सोटी) दाताओं एवं प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण, अंग आवंटन तथा प्रत्यारोपण एवं अंग पुनःप्राप्ति केन्द्रों के लाइसेंस प्रबंधन का कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म अंग प्रत्यारोपण संबंधी विनियमों के कार्यान्वयन एवं निगरानी गतिविधियों का समर्थन करता है।

ई-हॉस्पिटल केरल

ई-हॉस्पिटल@एनआईसी एक ओपन-सोर्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे केरल में भारतीय चिकित्सा पद्धति निदेशालय के अंतर्गत अस्पतालों में लागू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म अस्पताल प्रशासन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन का समर्थन करता है।



▲ चित्र 3.7 एनकेएन कनेक्टिविटी

उद्योग विभाग

केरल सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस (के-स्विफ्ट)

के-स्विफ्ट व्यवसायों एवं निवेशकों को वैधानिक स्वीकृतियां एवं अनुमतियां प्रदान करने हेतु विकसित सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली ओपन एपीआई के माध्यम से विभिन्न विभागों को एकीकृत करती है तथा परियोजना जीवनचक्र के दौरान ऑनलाइन अनुमति एवं स्वीकृति प्रसंस्करण का समर्थन करती है।

केरल - सेंट्रलाइज्ड इंसपेक्शन एंड कम्प्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम (के-सिस्को)

के-सिस्को, के-स्विफ्ट का विस्तारित रूप है, जिसे विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं अनुपालन गतिविधियों को सुव्यवस्थित

करने हेतु विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म निरीक्षण प्रक्रियाओं में समन्वय, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देता है तथा दोहराव को कम करता है।

एंटरप्रेन्योर सपोर्ट स्कीम (ईएसएस)

ईएसएस में स्टार्टअप, निवेश एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजनाओं से संबंधित आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु सार्वजनिक एवं कार्यालय पोर्टल शामिल हैं। उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्वीकृतियों की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं तथा समझौता दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

श्रम विभाग

एम्प्लॉयमेंट पोर्टल

एम्प्लॉयमेंट पोर्टल रोजगार विनियम सेवाओं का डिजिटलीकरण

करता है, जिसमें पंजीकरण, वरिष्ठता प्रबंधन, नियोक्ता प्रबंधन तथा रोजगार मेलों का समन्वय शामिल है।

अतिथि पोर्टल

अतिथि एक बहुभाषीय पोर्टल है, जिसे केरल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण एवं प्रबंधन हेतु विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म प्रवासी श्रमिकों के अनिवार्य पंजीकरण तथा संबंधित प्रशासनिक गतिविधियों का समर्थन करता है।।

विधि विभाग

केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सिस्कैट)

सिस्कैट केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण हेतु विकसित केस प्रबंधन प्रणाली है। यह प्लेटफॉर्म आवेदन दायर होने से लेकर निस्तारण तक की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है तथा केस स्थिति, निर्णय, कारण सूची एवं केस इतिहास जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडवोकेट जनरल केरल (मिसागो)

मिसागो महाधिवक्ता कार्यालय की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु विकसित वर्कफ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली केस दस्तावेजों के डिजिटल आदान-प्रदान, कार्मिक प्रबंधन तथा हितधारकों को सूचना प्रसार का समर्थन करती है।

लोक निर्माण / इंजीनियरिंग विभाग

प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट एस्टीमेशन (प्राइस)

प्राइस सार्वजनिक निधियों से निष्पादित अवसंरचना परियोजनाओं हेतु विकसित कार्य प्रबंधन एवं लागत अनुमान सॉफ्टवेयर है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों में कार्यप्रणाली, परियोजना अनुमान तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण करता है।

पंजीकरण विभाग

पर्ल

पर्ल सूट पंजीकरण विभाग हेतु विकसित वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग उप-पंजीयक कार्यालयों की गतिविधियों एवं ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के समर्थन हेतु किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म रिलिस एवं ई-ताल जैसी प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जिससे डिजिटल सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

राजस्व विभाग

आरआरऑनलाइन

आरआरऑनलाइन राजस्व वसूली गतिविधियों के स्वचालन हेतु विकसित केंद्रीकृत वर्कफ्लो आधारित वेब एप्लीकेशन है। यह प्रणाली अनुरोध करने वाली एजेंसियों तथा राजस्व विभाग के विभिन्न स्तरों के बीच ऑनलाइन फाइल मूवमेंट को सक्षम बनाती है तथा सरकारी विभागों, बैंकों, निगमों, न्यायालयों एवं अन्य संस्थाओं के लिए पारदर्शी प्रसंस्करण सुनिश्चित करती है।

रेवेन्यू लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (रिलिस)

रिलिस एक एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली है, जिसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डी.आई.एल.आर.एम.पी) के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म भूमि प्रबंधन, राजस्व ई-पेमेंट तथा पुनः सर्वेक्षण अभिलेख प्रबंधन को एकीकृत करता है तथा ऑनलाइन नागरिक सेवाओं एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख रखरखाव का समर्थन करता है।

▼ चित्र 3.8 : निकनेट कनेक्टिविटी





▲ चित्र 3.9 : एनआईसी केरल यात्रा के दौरान एनआईसी केरल टीम के साथ महानिदेशक एनआईसी

भूमि सर्वेक्षण विभाग

एंटेभूमि / रिसर्व मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आर.एम.आई.एस)

आर.एम.आई.एस / एंटेभूमि एक एकीकृत भूमि सूचना प्रणाली है, जिसे केरल में डिजिटल पुनः सर्वेक्षण गतिविधियों हेतु विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों एवं नागरिकों को अद्यतन भूमि संबंधी जानकारी की रीयल-टाइम पहुंच प्रदान करता है तथा भूमि डेटा की पारदर्शिता एवं उपलब्धता को बढ़ाता है।

ई-मैप्स (भूणक्शा)

भूणक्शा पोर्टल ग्राम स्तर के पुनः सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्रों को उपलब्ध कराता है तथा नागरिकों को फील्ड मेजरमेंट बुक (एफएमबी) स्केच ऑनलाइन देखने एवं डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त स्केच सेवाओं हेतु राजस्व ई-पेमेंट प्रणाली के साथ एकीकृत है।

राज्य सूचना आयोग

द्वितीय अपील हेतु आरटीआई प्रणाली

द्वितीय अपील हेतु आरटीआई प्लेटफॉर्म नागरिकों को राज्य सूचना आयोग के समक्ष ऑनलाइन अपील याचिकाएं (एपी) एवं शिकायत याचिकाएं (सीपी) दायर करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली वर्कफ्लो आधारित प्रसंस्करण, याचिका ट्रैकिंग तथा अंग्रेजी एवं मलयालम में अंतिम आदेश जारी करने का समर्थन करती है।

डिजिटल समाधान

एनआईसीडीसाइन

एनआईसीडीसाइन एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म डिजिटल हस्ताक्षर समाधान है, जो पीकेसीएस#11 टोकन के माध्यम से ब्राउज़र-स्वतंत्र डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा प्रदान करता है। यह समाधान विंडोज, लिनक्स तथा मैकओएस वातावरण में दस्तावेजों एवं पीडीएफ फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर का समर्थन करता है तथा जावा, पीएचपी एवं .NET आधारित एप्लीकेशन्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

मोबाइल एप डेवलपमेंट कम्पिटेन्सी सेंटर, कन्नूर

मोबाइल एप डेवलपमेंट कम्पिटेन्सी सेंटर सरकारी परियोजनाओं हेतु एंड्रॉयड एवं आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन्स के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह केन्द्र एक प्रकाशन, परामर्श सेवाओं तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है।

संदेश (गवर्नमेंट इंस्टैंट मैसेजिंग सिस्टम)

संदेश एनआईसी केरल द्वारा सरकारी संगठनों के लिए विकसित एक ओपन-सोर्स इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, एन्क्रिप्टेड बैकअप तथा सुरक्षित ओटीपी डिलीवरी का समर्थन करता है।

कोर सेवाएं

- केरल का ई-गवर्नेंस ढांचा एक सुदृढ़ एवं भविष्य उन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम पर आधारित है, जो सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान, निर्बाध कनेक्टिविटी तथा सरकारी विभागों में सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करता है। यह एकीकृत अवसंरचना प्रशासनिक समन्वय को मजबूत बनाते हुए नागरिक-केंद्रित सेवाओं एवं सुव्यवस्थित आंतरिक कार्यप्रवाह को सक्षम बनाती है।

- इस इकोसिस्टम के केंद्र में निकनेट, एनकेएन तथा केरल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (के.एस.डब्ल्यू.ए.एन) हैं, जो सरकारी कार्यालयों को उच्च क्षमता एवं सुरक्षित संचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं। ये नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस, ईमेल संचार, वीपीएन कनेक्टिविटी, क्लाउड इंटीग्रेशन, वेब होस्टिंग, लैन सपोर्ट तथा वाई-फाई सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं का समर्थन करते हैं।

- इसके अतिरिक्त, एनजीसी क्लाउड सेवाएं विभागों को एप्लीकेशन होस्टिंग एवं डेटा प्रबंधन हेतु केंद्रीकृत, सुरक्षित एवं स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं। यह क्लाउड वातावरण डिजिटल सेवाओं की त्वरित तैनाती, आईटी संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा परिचालन लचीलापन को सक्षम बनाता है।

- आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस) रीयल-टाइम उपस्थिति ट्रैकिंग एवं स्वचालित निगरानी के माध्यम से जवाबदेही एवं कार्यबल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है।

- इसके अतिरिक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर के कार्यालयों के बीच निर्बाध वचुअल संवाद सुनिश्चित करती हैं, जिससे समयबद्ध निर्णय, यात्रा आवश्यकताओं में कमी तथा शासन कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

- सामूहिक रूप से ये प्रौद्योगिकी-आधारित पहलें केरल में कुशल शासन, सुरक्षित सेवा वितरण तथा सतत डिजिटल परिवर्तन के लिए मजबूत डिजिटल आधार प्रदान करती हैं।

महत्वपूर्ण घटनाएं

- केरल को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डी.

पी.आई.आई.टी), भारत सरकार द्वारा आयोजित स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान मूल्यांकन के अंतर्गत लगातार दूसरे वर्ष उद्योग समागम 2025 में मान्यता प्राप्त हुई।

- माननीय सामान्य शिक्षा एवं श्रम मंत्री द्वारा तिरुवनंतपुरम में एनआईसी केरल द्वारा विकसित प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

- भूमि राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, केरल द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस सम्मेलन में 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने डिजिटल भूमि प्रशासन पहलों पर चर्चा की।

- माननीय मुख्यमंत्री, केरल द्वारा तिरुवनंतपुरम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पोर्टल तथा डायरेक्ट सेलिंग दिशानिर्देश एवं जागरूकता वीडियो का शुभारंभ किया गया।

- डिजिटल कियोस्क के माध्यम से सर्वेक्षण अभिलेखों की ऑनलाइन वितरण प्रणाली का उद्घाटन माननीय राजस्व मंत्री, केरल द्वारा किया गया।

- केरल के मुख्य सचिव ने राज्य में लागू आईटी परियोजनाओं एवं डिजिटल शासन पहलों की समीक्षा हेतु एनआईसी केरल राज्य केन्द्र का दौरा किया।

- एनआईसी के महानिदेशक द्वारा एनआईसी केरल राज्य केन्द्र में डीआईओ/डीआईए कार्यशाला 2025 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सचिव (ई एंड आईटी), सीईओ केरल, स्टेट कोऑर्डिनेटर केरल, डीडीजी एवं एचओजी (कार्मिक) तथा डीडीजी एवं एसआईओ (केरल एवं लक्षद्वीप) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भावी दिशा

एनआईसी केरल राज्य में डिजिटल शासन को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा साइबर सुरक्षा समाधानों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। भविष्य की पहलें शासन दक्षता में सुधार, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने तथा नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित होंगी।

मुख्य फोकस क्षेत्रों में ई-ऑफिस के व्यापक उपयोग, विभागीय डिजिटल सेवाओं के एकीकरण, विभिन्न सरकारी प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने तथा पेपरलेस शासन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एनआईसी केरल मोबाइल-सक्षम सेवाओं के विस्तार तथा विभागों के बीच सुरक्षित डिजिटल संचार अवसंरचना को और मजबूत करने की दिशा में भी कार्य करेगा।

राज्य सूचना विज्ञान केंद्र केरल राज्य के सरकारी विभागों को तकनीकी परामर्श, क्षमता निर्माण सहायता तथा डिजिटल समाधान प्रदान करना जारी रखेगा तथा पारदर्शी, कुशल एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी

राज्य सूचना विज्ञान केरल राज्य केंद्र
सी-डैक बिल्डिंग वेल्लायम्बलम, तिरुवनंतपुरम
केरल - 695033

ईमेल: sio-ker@nic.in, फ़ोन: 0471-2729894

झज्जर, हरियाणा

प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन को सशक्त बनाना

संपादित : सुषमा मिश्रा



हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित झज्जर जिला सांस्कृतिक गहराई और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है। बेरी धाम (माता भीमेश्वरी देवी मंदिर) जैसे प्रमुख स्थल इसकी सशक्त सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करते हैं।

एनआईसी जिला केंद्र झज्जर के डिजिटल परिवर्तन में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म, रियल-टाइम डेटा प्रणाली तथा सुरक्षित संचार तंत्र की शुरुआत के माध्यम से इसने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और सेवा वितरण में सुधार किया है।

और भी महत्वपूर्ण यह है कि एनआईसी झज्जर शासन और नागरिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है—प्रणालियों को सुलभ, प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सेवाओं को समावेशी बनाते हुए। परिणामस्वरूप, यह जिला केवल डिजिटल रूप से सक्षम ही नहीं, बल्कि सार्थक रूप से जुड़ा हुआ भी है।

जिले में आईसीटी पहले

इलेक्शन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम

चुनाव प्रबंधन में एक अग्रणी पहल के रूप में, इलेक्शन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम ने मतदान अनुभव को परिवर्तित किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान केंद्रों पर कतार की वास्तविक समय की जानकारी अपडेट करने में सक्षम बनाकर, मतदाता मतदान केंद्र पर जाने से पहले प्रतीक्षा समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस नवाचार से भीड़भाड़ में कमी आई है, भीड़ का बेहतर वितरण हुआ है और मतदाताओं की सुविधा में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि सरल किन्तु प्रभावी डिजिटल हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दौरान सार्वजनिक सेवा वितरण को किस प्रकार उल्लेखनीय रूप से बेहतर बना सकते हैं।



अमित बंसल
वैज्ञानिक - डी एवं डीआईओ
amit.bansal78@nic.in



कुसुम लता
वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायक - ए
sarvjeet.kumar@nic.in



झज्जर में शासन काउंटर से स्क्रीन तक स्थानांतरित हो चुका है—और अधिक तेज, अधिक स्पष्ट तथा नागरिक के और अधिक निकट। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) जिला केंद्र की एक प्रमुख पहल नागरिक सेवाओं का निर्बाध डिजिटलीकरण है। प्रमाण पत्र, शिकायतें और सेवा अनुरोध अब ऑनलाइन तथा रियल-टाइम ट्रैकिंग के साथ संचालित किए जा रहे हैं, जिससे विलंब में कमी आई है और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर को पाटते हुए यह प्रयास समावेशी और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक सहजता से प्रणाली के साथ जुड़ सकता है।



इलेक्शन ड्यूटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (ई.डी.एम.एस)

इलेक्शन ड्यूटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (ई.डी.एम.एस) एक व्यापक वेब-आधारित डिजिटल समाधान है, जिसे चुनावी कार्यों के नियोजन, प्रबंधन और निष्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। यह कर्मचारी डेटा के संग्रहण, मतदान एवं गणना कर्मियों के व्यवस्थित यादृच्छिकीकरण तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ड्यूटी आवंटन को सक्षम बनाता है।

इसकी प्रमुख विशेषताओं में द्विभाषी भाषा समर्थन, अनुकूलित ड्यूटी आदेशों का निर्माण, प्रशिक्षण उपस्थिति प्रबंधन तथा स्वचालित संचार योजना का निर्माण शामिल है। यह प्रणाली

चरणबद्ध चुनावों का भी समर्थन करती है और फॉर्म 12 एवं 12ए की प्रक्रिया को सरल बनाती है।

पंचायत, नगर निगम, लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों सहित प्रमुख चुनावों में तथा अरुणाचल प्रदेश में इसके सफल उपयोग ने इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया है।

मैनुअल हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, ई.डी.एम.एस ने चुनाव प्रबंधन की दक्षता और विश्वसनीयता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।

वोटर लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (वी.एल.एम.एस)

वोटर लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (वी.एल.एम.एस) एक अन्य महत्वपूर्ण नवाचार है, जो निर्वाचन नामावली की तैयारी और प्रबंधन को डिजिटल रूप प्रदान करता है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डेटा का उपयोग कर मतदाता अभिलेखों की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है।

द्विभाषी इंटरफेस, फोटो तथा बिना फोटो वाली मतदाता सूचियों का निर्माण, उन्नत खोज विकल्प तथा सुरक्षित प्रकाशन तंत्र जैसी विशेषताओं के माध्यम से वी.एल.एम.एस पारदर्शिता और सुलभता को बढ़ाता है।

विभिन्न चुनावों में इसके सफल कार्यान्वयन ने इसकी विश्वसनीयता और विस्तार क्षमता को रेखांकित किया है, जिससे यह आधुनिक चुनावी शासन का एक अनिवार्य अंग बन गया है।

अन्य प्रमुख आईसीटी पहले

अंत्योदय सरल पोर्टल (सरल)

अंत्योदय सरल पोर्टल एक एकीकृत मंच के रूप में 700 से अधिक सरकारी सेवाएँ प्रदान करता है। यह फेसलेस, पेपरलेस और केशलेस शासन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है।

नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति का अनुकरण कर सकते हैं और समयबद्ध सेवा वितरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ एकीकृत है, जिससे डेटा तक सहज पहुँच संभव होती है।

एनआईसी झज्जर के सतत सहयोग से जिले का प्रदर्शन उच्च स्तर पर बना हुआ है, जहाँ जिला स्कोर 9.2 से अधिक है, जो सेवा वितरण की गुणवत्ता को दर्शाता है।

जिला वेबसाइट

झज्जर की आधिकारिक जिला वेबसाइट एक व्यापक एवं केंद्रीकृत डिजिटल सूचना मंच के रूप में कार्य करती है। एस.3डब्ल्यू.ए.एस फ्रेमवर्क पर विकसित यह पोर्टल ई-सेवाएँ,

आरटीआई आवेदन, निविदाएँ, सूचनाएँ तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है।

नियमित अद्यतन और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से यह प्लेटफॉर्म पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करता है।

ई-ऑफिस कार्यान्वयन

ई-ऑफिस के कार्यान्वयन ने प्रशासनिक कार्यप्रवाह को कागजरहित प्रणाली में परिवर्तित करते हुए एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। यह फाइलों के तीव्र संचलन, रियल-टाइम ट्रैकिंग तथा बेहतर अभिलेख प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

इससे न केवल दक्षता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है, बल्कि कागज के उपयोग में कमी के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिला है।

सीएम विंडो: शिकायत निवारण प्रणाली

सीएम विंडो एक प्रमुख पहल है, जो नागरिकों को शिकायत दर्ज करने के लिए एक पारदर्शी मंच प्रदान करती है। 15 लाख से अधिक शिकायतों की प्राप्ति और उच्च निस्तारण दर के साथ यह प्रणाली प्रभावी शासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

एनआईसी झंझर इसके सुचारु संचालन, निगरानी और तकनीकी सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्रशासनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुदृढ़ होती है।

क्षेत्र-विशिष्ट डिजिटल पहले

मेडलीपर प्रणाली

मेडिको-लीगल जांच एवं पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रणाली (मेडलीपर) स्वास्थ्य संस्थानों में कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाती है। झंझर में इसके व्यापक उपयोग से रिपोर्टिंग की दक्षता और डेटा की सटीकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

वेब-हलरिस (वेब-एच.ए.एल.आर.आई.एस)

वेब-हलरिस भूमि अभिलेख और संपत्ति पंजीकरण के लिए एक समग्र मंच है। बिक्री विलेख पंजीकरण, म्यूटेशन तथा अभिलेख प्रबंधन जैसी सेवाओं के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

झंझर में दर्ज उच्च लेन-देन मात्रा और मूल्य इस प्रणाली की विश्वसनीयता और व्यापक उपयोग को दर्शाते हैं।

▼ चित्र 4.1 : मुख्यमंत्री सुशासन दिवस 2024 में समग्र प्रदर्शन हेतु तृतीय पुरस्कार



परिवहन एवं राजस्व सेवाएँ

एनआईसी झंझर वाहन (वाहन), सारथी (सारथी), विलेख पंजीकरण तथा भूमि अभिलेख जैसी प्रमुख सेवाओं का समर्थन करता है। ये प्लेटफॉर्म जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं और नागरिकों के लिए उन्हें अधिक सुलभ बनाते हैं।

नेटवर्क एवं अवसंरचना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: रियल-टाइम शासन को सक्षम बनाना

एनआईसी झंझर ने एक सुदृढ़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना स्थापित की है, जो विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम बनाती है। यह परियोजना निगरानी, शिकायत समीक्षा, कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन तथा प्रशिक्षण सत्रों के संचालन में सहायक है।

प्रति वर्ष 500 से अधिक सत्रों के साथ यह प्रणाली प्रभावी समन्वय और निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करती है, जिससे शासन अधिक समयबद्ध और प्रभावी बनता है।

महत्वपूर्ण आयोजनों एवं वीडियो गतिविधियों में सहयोग

एनआईसी झंझर ने प्रमुख आयोजनों और वीडियो दौड़ों के दौरान निरंतर तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। केएमपी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर आईटी अवसंरचना के प्रबंधन से लेकर बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के समर्थन तक, टीम ने निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने में इसकी भूमिका इसकी तकनीकी दक्षता और विश्वसनीयता को दर्शाती है।

उपलब्धियाँ

एनआईसी झंझर की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को अनेक पुरस्कारों और सम्मानों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है:

- डीआईओ मीट 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला - प्रथम पुरस्कार
- सुशासन दिवस 2023 - प्रथम स्थान
- सुशासन दिवस 2024 - तृतीय स्थान

मैं डिजिटल शासन को आगे बढ़ाने तथा जिले की आईटी अवसंरचना को सशक्त बनाने में एनआईसी झंझर के महत्वपूर्ण योगदान को हृदय से स्वीकार करता हूँ। ई-गवर्नेंस पहलों के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने सार्वजनिक सेवाओं की कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित उपलब्धता सुनिश्चित की है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास, रखरखाव और समर्थन में टीम की समर्पित भावना ने प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व को अत्यधिक सुदृढ़ किया है। उनके निरंतर प्रयासों और तकनीकी विशेषज्ञता ने जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ और पूरी टीम को उनके निरंतर सफलता एवं भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।



श्री स्वामित रविंद्र पाटिल, आईएएस उपायुक्त, झंझर

- राज्य निर्वाचन आयोग एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से प्रशंसा
- आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान विशेष सम्मान
- ये उपलब्धियाँ जिले के कुशल एवं नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के सतत प्रयासों को दर्शाती हैं।

अग्रिम दिशा

आगामी समय में एनआईसी झंझर नवाचारपूर्ण और विस्तार योग्य समाधानों के माध्यम से डिजिटल शासन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए तत्पर है। चुनाव प्रबंधन प्रणालियों का निरंतर एकीकरण, नागरिक सेवाओं का विस्तार और उभरती प्रौद्योगिकियों का अपनाना भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप, एनआईसी झंझर एक ऐसे शासन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है, जो पारदर्शी, दक्ष और समावेशी हो। इसका मुख्य फोकस नागरिक अनुभव को बेहतर बनाना, सेवा वितरण में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी का लाभ जिले के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी झंझर जिला केंद्र
कमरा संख्या 208, द्वितीय तल, मिनी सचिवालय,
झंझर, हरियाणा - 124103
ई-मेल: dio-jhj@nic.in, फोन: 01251-253119

मालेरकोटला, पंजाब

समयबद्ध डिजिटल शासन को नई गति

संपादित : विनोद कुमार गर्ग

पंजाब का 23वाँ जिला मालेरकोटला तकनीक-आधारित प्रशासनिक कार्यप्रणालियों को अपनाते हुए एक डिजिटल रूप से सक्षम प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से जिला प्रशासन विभिन्न विभागों में परिचालन दक्षता, संचार, निगरानी और नागरिक सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), जिला केंद्र मालेरकोटला, ई-गवर्नेंस समाधानों, सुरक्षित नेटवर्किंग अवसंरचना, एप्लिकेशन प्रबंधन, साइबर सुरक्षा सहायता और तकनीकी परामर्श सेवाओं के माध्यम से जिले के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनआईसी मालेरकोटला डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, रियल-टाइम निगरानी प्रणालियों और पेपरलेस प्रशासनिक उपकरणों के कार्यान्वयन के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। निरंतर नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से एनआईसी मालेरकोटला जिले में पारदर्शी, उत्तरदायी, कुशल और तकनीक-आधारित शासन को बढ़ावा दे रहा है।

जिले में आईसीटी पहले

समयसेतु

“समयसेतु” एनआईसी मालेरकोटला द्वारा विकसित एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जिसे सरकारी संचार और प्रशासनिक बैठकों की समयबद्ध निगरानी के लिए तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म नए आवंटित कार्यों, लंबित मामलों, समय-सीमा अनुस्मारक तथा बैठक कार्यक्रमों से संबंधित स्वचालित व्हाट्सएप और ई-मेल सूचनाएँ अधिकारियों को भेजता है।

इस प्रणाली को प्रशासनिक संचार में देरी कम करने और विभागों के बीच कार्यप्रवाह प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अधिकारियों को लंबित मामलों से संबंधित समय पर अलर्ट प्राप्त होते हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई और कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है। यह प्लेटफॉर्म वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीकृत निगरानी सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे वे संचार की स्थिति की समीक्षा कर समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।



शाइन कमल
वैज्ञानिक - बी व डीआईओ
shine.kamal@nic.in



एनआईसी मालेरकोटला द्वारा विकसित “समयसेतु” एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे प्रशासनिक संचार को सुव्यवस्थित करने तथा सरकारी कार्यों की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म आधिकारिक डाक तथा बैठकों की समय-सारणी की डिजिटल ट्रैकिंग सक्षम करता है और अधिकारियों को स्वचालित व्हाट्सएप तथा ई-मेल अलर्ट भेजता है। रियल-टाइम रिमाइंडर और अपडेट उपलब्ध कराकर “समयसेतु” विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाता है, जवाबदेही को मजबूत करता है तथा प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है।



प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

- आधिकारिक डाक का डिजिटल पंजीकरण और निगरानी
- प्रशासनिक बैठकों की केंद्रीकृत समय-सारणी
- अधिकारियों के लिए स्वचालित व्हाट्सएप और ई-मेल अलर्ट
- स्वचालित अनुस्मारकों के साथ समय-सीमा ट्रैकिंग
- आधिकारिक संचार का डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन
- लंबित मामलों की रियल-टाइम निगरानी और स्थिति ट्रैकिंग

यह एप्लिकेशन विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाता है, आधिकारिक पत्राचार में देरी को कम करता है तथा प्रशासनिक निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करता है। रियल-टाइम अलर्ट और केंद्रीकृत निगरानी जिला प्रशासन में जवाबदेही,

पारदर्शिता और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं।

लाभ एवं प्रभाव

- आधिकारिक संचार और समय-सीमा की बेहतर निगरानी
- प्रशासनिक प्रतिक्रिया और निर्णय-निर्माण में तेजी
- शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि
- डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन के माध्यम से मैनुअल प्रक्रियाओं में कमी
- विभागों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय
- प्रशासनिक बैठकों और संचार प्रबंधन में अधिक दक्षता

अन्य प्रमुख पहलें एवं नवाचार

सामूहिक संदेशों के माध्यम से नागरिक जागरूकता अभियान

एनआईसी मालेरकोटला ने पराली जलाने के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु नागरिकों को सामूहिक व्हाट्सएप संदेश भेजने में जिला प्रशासन का सहयोग किया। इस पहल ने पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया, सरकारी सलाहों के अनुपालन को प्रोत्साहित किया तथा नागरिक संपर्क में डिजिटल संचार उपकरणों के प्रभावी उपयोग को प्रदर्शित किया।

नशा मुक्ति पंजीकरण पोर्टल (डी.डी.आर.पी)

एनआईसी ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नशा मुक्ति पंजीकरण पोर्टल के चरणबद्ध कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की। यह पोर्टल आधार आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से ओ.ओ.ए.टी तथा निजी नशा मुक्ति केंद्रों में रोगियों के पंजीकरण और उपचार की केंद्रीकृत निगरानी सक्षम करता है। इस प्रणाली ने रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाया और उपचार सेवाओं की निगरानी को मजबूत किया।

ई-डार

एनआईसी मालेरकोटला ने पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभागों के समन्वय से इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डार) प्रणाली के कार्यान्वयन में सहयोग दिया। यह प्रणाली सड़क दुर्घटनाओं की डिजिटल रिपोर्टिंग सक्षम करती है, जिससे दुर्घटना दावा प्रक्रिया तेज होती है और विभागीय समन्वय बेहतर बनता है। प्रणाली के प्रभावी उपयोग हेतु विभिन्न विभागीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

ई-सनद

एनआईसी ने एपोस्टिल और सत्यापन सेवाओं हेतु दस्तावेजों के

ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और सत्यापन के लिए ई-सनद पोर्टल के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्लेटफॉर्म ने नागरिकों के लिए संपर्करहित, नकदरहित और कागजरहित सेवा वितरण को बढ़ावा दिया।

ई-ऑफिस

ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म को डीसी कार्यालय और एसडीएम कार्यालयों में पेपरलेस प्रशासन और फाइलों की कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। एनआईसी ने अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे प्रणाली को सुचारु रूप से अपनाया जा सके। इस पहल ने फाइल प्रसंस्करण की दक्षता बढ़ाई और भौतिक अभिलेखों पर निर्भरता कम की।

निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी सहायता

एनआईसी मालेरकोटला ने चुनावों के दौरान नेक्स्टजेन डाइस तथा मतदान दिवस गतिविधि निगरानी प्रणाली (पी.ए.एम.एस) जैसी प्रणालियों के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की। इन प्रणालियों ने निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान समन्वय और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया।

नागरिक सेवाएँ

जिला वेबसाइट नागरिकों के लिए एक डिजिटल प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है, जहाँ सरकारी योजनाओं, सेवाओं, सार्वजनिक सूचनाओं और जिला प्रशासन से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी और विभागीय सेवाओं तक सरलता से पहुँच सकते हैं।

एनआईसी मालेरकोटला पंजाब स्पोर्ट्स इवेंट पोर्टल, आईवीएफआरटी प्रणाली तथा एम.एस.वाई जैसी योजनाओं के तकनीकी क्रियान्वयन में भी सहयोग प्रदान कर रहा है, जिससे जिले में डिजिटल सेवा वितरण और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूती मिल रही है।

जिला प्रशासन मालेरकोटला ने एनआईसी मालेरकोटला के सहयोग से जिले में डिजिटल शासन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत बनाने के लिए कई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहलें लागू की हैं। समयसेतु जैसे नवाचारी समाधानों और विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को सुदृढ़ किया गया है। मैं नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रभावी डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन में एनआईसी मालेरकोटला के प्रयासों और तकनीकी विशेषज्ञता की सराहना करता हूँ।



श्री विराज एस. तिडके, आईएएस
उपायुक्त, मालेरकोटला



▲ चित्र 5.1 : एनआईसी मालेरकोटला, द्वारा समयसेतु लॉन्च करते हुए



▲ चित्र 5.2 : मालेरकोटला के उपायुक्त, श्री विराज एस. तिडके, आईएएस, मुख्य अतिथि के रूप में सुरक्षित इंटरनेट दिवस जागरूकता कार्यशाला में भाग लेते हुए।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना और कार्यक्रम सहायता

एनआईसी मालेरकोटला मुख्यमंत्री दौड़ों, समीक्षा बैठकों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और वीवीआईपी आयोजनों सहित प्रमुख प्रशासनिक कार्यक्रमों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी सहायता प्रदान करता है, जिससे निर्बाध डिजिटल संचार और समन्वय सुनिश्चित होता है।

महत्वपूर्ण आयोजन एवं भ्रमण

- “समयसेतु” एप्लिकेशन का औपचारिक शुभारंभ उपायुक्त, मालेरकोटला द्वारा किया गया, जिसने जिले में समयबद्ध प्रशासनिक निगरानी और डिजिटल शासन को नई दिशा प्रदान की।
- एनआईसी मालेरकोटला ने छात्रों और सरकारी अधिकारियों के बीच सुरक्षित एवं जिम्मेदार डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए “सुरक्षित इंटरनेट दिवस” जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। उपायुक्त, मालेरकोटला ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- एनआईसी प्रमुख प्रशासनिक कार्यक्रमों, समीक्षा बैठकों, चुनावों और वीवीआईपी दौड़ों के दौरान नियमित रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे विश्वसनीय कनेक्टिविटी और निर्बाध डिजिटल संचार सुनिश्चित हो सके।

उपलब्धियाँ

- लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रभावी तकनीकी सहायता के

लिए उपायुक्त द्वारा प्रशंसा

- डिजिटल शासन पहलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योगदान के लिए सम्मान
- साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु प्रशंसा प्रमाणपत्र

अग्रिम दिशा

एनआईसी मालेरकोटला अभिनव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से डिजिटल शासन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की योजनाओं में “समयसेतु” जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार, अन्य सरकारी प्रणालियों के साथ बेहतर एकीकरण, डिजिटल निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को जारी रखना शामिल है। तकनीक-आधारित शासन और नागरिक-केंद्रित डिजिटल समाधानों के माध्यम से एनआईसी जिले में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा वितरण को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्यरत रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
उपायुक्त कार्यालय
मालेरकोटला, पंजाब
ई-मेल: punmlr@nic.in, फ़ोन: 01675-2520005

ई-डिटेक्शन

बुद्धिमान डिजिटल प्रवर्तन के माध्यम से सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना

संपादित : निस्सी जॉर्ज

राष्ट्रीय राजमार्गों तथा शहरी परिवहन गलियारों में वाहनों की निरंतर बढ़ती आवाजाही ने परिवहन प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। वाहन दस्तावेजों के मैन्युअल निरीक्षण पर आधारित पारंपरिक प्रवर्तन प्रणालियाँ अक्सर अधिक मानव संसाधन की मांग करती हैं, समय की खपत बढ़ाती हैं तथा अनुपालन निगरानी में कई स्तरों पर अंतराल छोड़ देती हैं। इन चुनौतियों के समाधान के रूप में ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन एक प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जिसे मोटर वाहन उल्लंघनों की स्वचालित पहचान करने तथा परिवहन पारितंत्र में डिजिटल प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

यह एप्लीकेशन एक बुद्धिमान निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो बिना वैध मोटर वाहन दस्तावेजों के संचालित वाहनों की पहचान करने में सक्षम है। इनमें टैक्स रिकॉर्ड, फिटनेस प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र तथा परमिट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। यह प्रणाली ब्लैकलिस्टेड वाहनों तथा फर्जी अथवा परिवर्तित रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का उपयोग करने वाले संदिग्ध वाहनों की पहचान में भी सहायता प्रदान करती है। टोल लेनदेन डेटा को केंद्रीकृत परिवहन डेटाबेस के साथ एकीकृत करके यह प्लेटफॉर्म बिना निरंतर भौतिक हस्तक्षेप के स्वचालित अनुपालन सत्यापन सुनिश्चित करता है।

डिजिटल प्रवर्तन संरचना

डेटा संग्रहण एवं सत्यापन

ई-डिटेक्शन का परिचालन ढांचा टोल प्लाज़ा से वाहन लेनदेन डेटा के संग्रहण से प्रारंभ होता है। टोल ऑपरेटर वाहन संख्या, लेनदेन तिथि तथा वाहन वर्ग से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड को ई-डिटेक्शन पोर्टल पर अपलोड करते हैं। डेटा अपलोड होने के पश्चात प्रणाली, वाहन डेटाबेस तथा संबंधित परिवहन प्रणालियों के साथ एकीकृत शेड्यूलर-आधारित प्रोसेसिंग तंत्र के माध्यम से स्वचालित विश्लेषण प्रारंभ करती है।

अपलोड किए गए डेटा का निरंतर सत्यापन आधिकारिक परिवहन अभिलेखों के साथ किया जाता है, ताकि ऐसे वाहनों



प्रसांत कुमार नायक

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
pk.nayak@nic.in



ई-डिटेक्शन एक बुद्धिमान डिजिटल प्रवर्तन प्लेटफॉर्म है, जो टोल प्लाज़ा लेनदेन डेटा और केंद्रीकृत परिवहन डेटाबेस का उपयोग करके मोटर वाहन उल्लंघनों की स्वचालित पहचान करता है। यह प्रणाली बिना वैध टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, पीयूसी प्रमाणपत्र अथवा परमिट के संचालित वाहनों का पता लगाती है तथा राष्ट्रीय ई-चालान ढांचे के साथ एकीकरण के माध्यम से स्वतः ई-चालान जनरेट करती है। यह सड़क सुरक्षा में सुधार, अनुपालन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा प्रभावी डिजिटल परिवहन सुशासन को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।



की पहचान की जा सके जो वैध अनुपालन दस्तावेजों के बिना संचालित हो रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म टैक्स वैधता, परमिट स्थिति, फिटनेस प्रमाणन, इंश्योरेंस कवरेज तथा पीयूसी अनुपालन सहित विभिन्न मानकों की जांच करता है। यह स्वचालित सत्यापन प्रक्रिया प्राधिकरणों को बड़े पैमाने पर वाहन आवागमन की प्रभावी निगरानी करने में सक्षम बनाती है तथा मैन्युअल जांच पर निर्भरता को कम करती है।

स्वचालित ई-चालान जनरेशन

इस प्लेटफॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक इसकी “वन नेशन वन चालान” ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-चालान प्रणाली के साथ एकीकृत कार्यप्रणाली है। किसी उल्लंघन की पुष्टि होने पर प्रणाली संबंधित डिफॉल्टर वाहन के विरुद्ध स्वतः ई-चालान जनरेट

करती है। वाहन स्वामी बाद में डिजिटल माध्यम से चालान विवरण प्राप्त कर सकते हैं तथा एकीकृत ई-चालान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

यह प्लेटफॉर्म कुछ विशेष लंबित मामलों अथवा अतिरिक्त जांच की आवश्यकता वाले टैक्स-संबंधित उल्लंघनों के लिए मैन्युअल इनवर्डींग एवं सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करता है। स्वचालन तथा नियंत्रित मैन्युअल निगरानी का यह संयोजन प्रवर्तन की सटीकता बनाए रखने के साथ-साथ परिचालन लचीलापन भी सुनिश्चित करता है।

प्रमुख कार्यात्मक क्षमताएँ

बुद्धिमान उल्लंघन पहचान

ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन स्वचालित डेटाबेस सत्यापन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन उल्लंघनों की पहचान करने में सक्षम है। यह प्लेटफॉर्म बिना अनिवार्य दस्तावेजों के संचालित वाहनों का पता लगाता है तथा संदिग्ध प्रवृत्तियों को प्रवर्तन कार्रवाई हेतु चिन्हित करता है। इसके अतिरिक्त, यह केंद्रीकृत वाहन अभिलेखों के साथ पंजीकरण विवरण का मिलान कर गलत नंबर प्लेट की पहचान करने में भी सक्षम है, जिससे प्राधिकरणों को नकली अथवा धोखाधड़ी वाले वाहनों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

एनालिटिक्स एवं मॉनिटरिंग

चालान जनरेशन से आगे बढ़कर यह प्लेटफॉर्म परिवहन विभागों के लिए एक व्यापक विश्लेषणात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। प्राधिकरण डिफॉल्टर वाहनों के डेटा की निगरानी कर सकते हैं, श्रेणीवार चालान आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं तथा एकीकृत डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्टों के माध्यम से प्रवर्तन प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन चालान इतिहास खोज तथा वाहन वर्ग तुलना जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करता है, जिससे विभाग अनुपालन व्यवहार तथा बार-बार होने वाले उल्लंघनों के पैटर्न का विश्लेषण कर सकते हैं।

संचार एवं प्रशासनिक दक्षता

यह प्रणाली वाहन स्वामियों को उल्लंघनों तथा चालान विवरण से संबंधित एसएमएस सूचनाएँ भेजने की सुविधा प्रदान करती है। इससे संचार प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है तथा शीघ्र अनुपालन को प्रोत्साहन मिलता है। चूंकि संपूर्ण कार्यप्रवाह डिजिटल रूप से संचालित होता है, इसलिए यह प्लेटफॉर्म कागजी कार्यवाही को कम करता है, मैन्युअल त्रुटियों को न्यूनतम करता है तथा प्रवर्तन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाता है।

सड़क सुरक्षा एवं सुशासन पर प्रभाव

ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह बिना वैध नियामकीय स्वीकृतियों के वाहनों के संचालन को हतोत्साहित करता है। स्वचालित निगरानी एक अधिक मजबूत अनुपालन वातावरण तैयार करती है तथा प्रवर्तन एजेंसियों को केवल भौतिक निरीक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय निरंतर उल्लंघनों की पहचान करने में सक्षम बनाती है।

यह प्लेटफॉर्म परिवहन प्रशासन में जवाबदेही को भी बेहतर बनाता है। चूंकि चालान जारी करने तथा सत्यापन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए प्रवर्तन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य बन जाती है। इससे प्रक्रियागत असंगतियों की संभावना कम होती है तथा पेपरलेस गवर्नेंस और

73,000 से अधिक ई-चालान जारी किए गए। बिहार में भी इस प्लेटफॉर्म का तीव्र विस्तार देखा गया है, जहाँ 33 एन.एच.ए.आई टोल प्लाज़ा पर कार्यान्वयन के बाद मात्र एक माह में 25,000 से अधिक ई-चालान जनरेट किए गए।

प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किए गए सांख्यिकीय विश्लेषण फिटनेस डिफॉल्ट, परमिट उल्लंघन, टैक्स अनुपालन की कमी, पीयूसी संबंधित समस्याएँ तथा इंश्योरेंस से जुड़े उल्लंघनों जैसी प्रमुख श्रेणियों को उजागर करते हैं। ऐसे विश्लेषण परिवहन प्राधिकरणों को साक्ष्य-आधारित प्रवर्तन योजना तैयार करने तथा लक्षित अनुपालन अभियानों को संचालित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

राज्य-विशिष्ट कस्टमाइजेशन

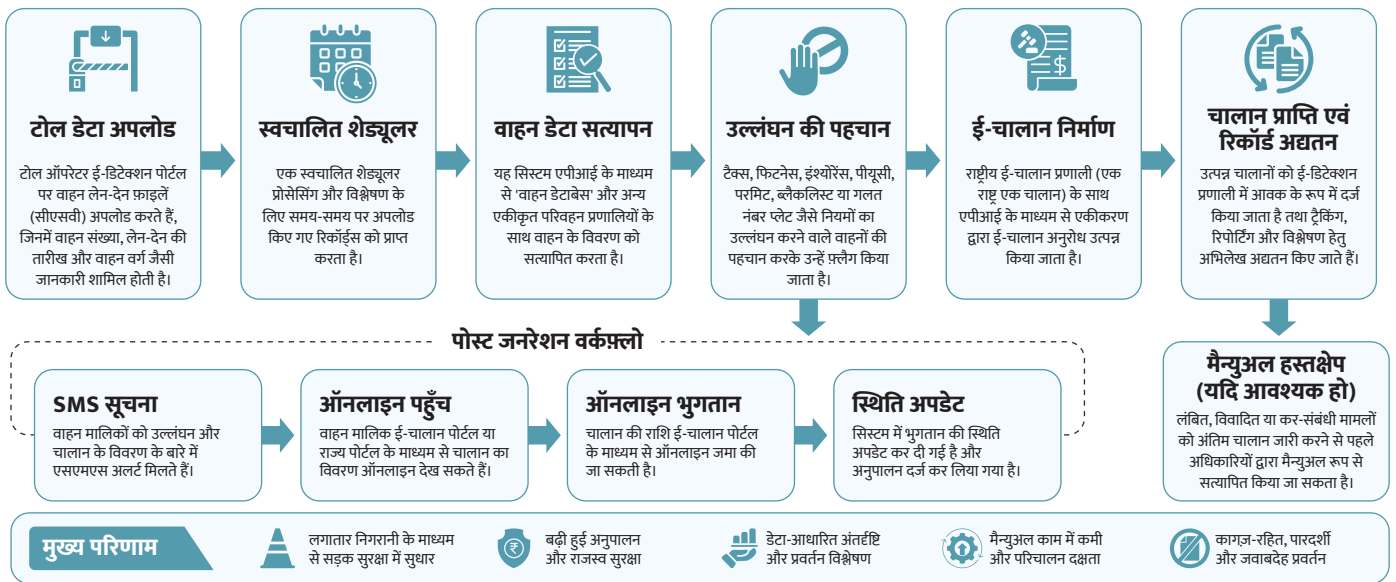
ई-डिटेक्शन प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी राज्य-विशिष्ट कस्टमाइजेशन क्षमता है। विभिन्न राज्य अपनी

भविष्य में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा जीएसटी, माइनिंग, पोर्ट और ई-वे बिल प्लेटफॉर्म जैसी बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकरण इस एप्लीकेशन की क्षमताओं को और अधिक विस्तारित कर सकता है। ये विकास ई-डिटेक्शन को केवल चालान जनरेशन प्रणाली से आगे बढ़ाकर एक व्यापक डिजिटल परिवहन इंटीग्रेज्ड प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने की दिशा को दर्शाते हैं, जो बहु-एजेंसी समन्वय तथा उन्नत अनुपालन निगरानी को समर्थन प्रदान कर सकेगा।

निष्कर्ष

ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन स्वचालित डेटा विश्लेषण, केंद्रीकृत डेटाबेस एकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक चालान जनरेशन को एकीकृत गवर्नेंस ढांचे के अंतर्गत संयोजित करके डिजिटल परिवहन प्रवर्तन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धिमान

मोटर वाहन उल्लंघनों का स्वचालित पता लगाना और ई-चालान जारी करना



ई-डिटेक्शन - प्रक्रिया प्रवाह आरेख

सुव्यवस्थित प्रवर्तन संचालन को बढ़ावा मिलता है।

राजस्व संरक्षण के क्षेत्र में भी इस प्लेटफॉर्म का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना वैध टैक्स, परमिट अथवा प्रमाणपत्रों के संचालित वाहन परिवहन विभागों को उल्लेखनीय वित्तीय हानि पहुँचाते हैं। स्वचालित पहचान और चालान जनरेशन के माध्यम से यह एप्लीकेशन अनुपालन वसूली को बेहतर बनाता है तथा नियामकीय प्रवर्तन को मजबूत करता है।

विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन

ई-डिटेक्शन का विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन इसकी स्केलेबिलिटी तथा परिचालन प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। ओडिशा में इस प्लेटफॉर्म को 24 एन.एच.ए.आई टोल प्लाज़ा पर लागू किया गया है, जहाँ लगभग 1.9 वर्षों में 155,000 से अधिक ई-चालान जनरेट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में यह प्रणाली 22 एनएचएआई टोल प्लाज़ा तथा 37 ए.एन.पी.आर कैमरों पर कार्यान्वित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.5 वर्षों में

स्थानीय नियामकीय प्राथमिकताओं तथा परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अपराध श्रेणियों और प्रवर्तन मानकों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यह लचीलापन प्राधिकरणों को ओवरलॉड डिटेक्शन, परमिट मॉनिटरिंग, पीयूसी अनुपालन अथवा इंश्योरेंस सत्यापन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि एकीकृत डिजिटल प्रवर्तन ढांचा भी बनाए रखता है।

भविष्य की रूपरेखा

ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन की भविष्य की रूपरेखा बुद्धिमान एवं एकीकृत परिवहन सुशासन की व्यापक दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावित उन्नयन में एपीआई आधारित डेटा साझाकरण, समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का विकास तथा ओवरलॉड उल्लंघनों की पहचान के लिए वेट-इन-मोशन प्रणालियों के साथ एकीकरण शामिल है। प्लेटफॉर्म से गैर-एचएसआरपी वाहनों की पहचान तथा पंजीकरण अभिलेखों के आधार पर गलत वाहन वर्ग की पहचान का समर्थन करने की भी अपेक्षा की जा रही है।

निगरानी तथा स्वचालित अनुपालन सत्यापन के माध्यम से यह प्लेटफॉर्म सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है, प्रवर्तन पारदर्शिता में सुधार करता है तथा प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है।

विभिन्न राज्यों में इसका सफल कार्यान्वयन आधुनिक परिवहन सुशासन में प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवर्तन प्रणालियों की व्यावहारिक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। अतिरिक्त एकीकरणों तथा उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ विकसित होते हुए ई-डिटेक्शन से अपेक्षा की जाती है कि यह भविष्य में सुरक्षित, अधिक जवाबदेह तथा डिजिटल रूप से सशक्त सड़क परिवहन प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
सचिवालय मार्ग, यूनिट - IV
भुवनेश्वर, ओडिशा - 751001
ईमेल: sio-ori@nic.in, फ़ोन: 0674-2508438

एच.जी.वी.एम.एस

डिजिटल सुशासन के माध्यम से होम गार्ड्स स्वयंसेवक प्रबंधन में बदलाव

संपादित : सुषमा मिश्रा



आधुनिक शासन व्यवस्था में प्रशासनिक कार्यों के बढ़ते दायरे और जटिलता को देखते हुए ऐसे एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश होम गार्ड्स विभाग के लिए होम गार्ड्स वॉलंटियर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एच.जी.वी.एम.एस) का डिजाइन एवं विकास किया है। यह प्रणाली राज्यभर में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के संपूर्ण जीवनचक्र प्रबंधन हेतु एक व्यापक डिजिटल समाधान के रूप में विकसित की गई है।

यह प्लेटफॉर्म एच.जी.वी.एम.एस पोर्टल (<https://hgvm.s.hp.gov.in/>) के माध्यम से उपलब्ध है। इसका औपचारिक शुभारंभ 22 मार्च 2026 को माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं राजस्व) श्री कमलेश कुमार पंत, पुलिस महानिदेशक (होम गार्ड्स) श्रीमती सतवंत अटवाल, निदेशक-सह-पदेन विशेष सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) श्री डी.सी. राणा, उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी हिमाचल प्रदेश श्री अजय सिंह चहल सहित होम गार्ड्स विभाग और एनआईसी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एच.जी.वी.एम.एस को एक एंड-टू-एंड वर्कफ्लो आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका



होम गार्ड्स वॉलंटियर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एच.जी.वी.एम.एस) हिमाचल प्रदेश में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रभावी प्रबंधन हेतु एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली नामांकन, तैनाती, उपस्थिति तथा मानदेय प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुव्यवस्थित करती है, जिससे सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही तथा त्वरित समन्वय सुनिश्चित होता है।



उद्देश्य होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की तैनाती एवं प्रबंधन में समन्वय, पारदर्शिता तथा परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करना है। यह पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने और डेटा-आधारित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाती है।

डिजिटल रूपांतरण की आवश्यकता को समझना

हिमाचल प्रदेश में होम गार्ड्स संगठन कानून प्रवर्तन एजेंसियों, आपदा प्रतिक्रिया अभियानों, सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन तथा विभिन्न सरकारी गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वयंसेवकों पर आधारित इस व्यापक तंत्र के प्रबंधन के लिए मुख्यालय, बटालियन कमांडेंट्स, मांग प्रस्तुत करने वाले विभागों तथा होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक होता है।

डिजिटलीकरण से पूर्व स्वयंसेवकों के नामांकन, तैनाती अनुमोदन, उपस्थिति संधारण तथा मानदेय प्रसंस्करण जैसी अनेक परिचालन प्रक्रियाएँ मुख्यतः मैनुअल थीं और विभिन्न प्रशासनिक

स्तरों पर संचालित होती थीं। इन प्रक्रियाओं के कारण प्रायः विलंब, अभिलेखों की पुनरावृत्ति तथा परिचालन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं।

विभागीय हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एक ऐसे केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो सभी परिचालन वर्कफ्लो को एकीकृत डिजिटल तंत्र में समाहित कर सके। उद्देश्य केवल अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी पारदर्शी एवं स्केलेबल प्रणाली विकसित करना था, जो प्रभावी प्रशासन तथा रियल-टाइम निगरानी को सक्षम बना सके।

इसी दृष्टि के साथ एनआईसी हिमाचल प्रदेश ने एच.जी.वी.एम.एस को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया, जो होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के संपूर्ण जीवनचक्र प्रबंधन—नामांकन से लेकर मानदेय वितरण तक—को समाहित करता है।

एंड-टू-एंड वर्कफ्लो स्वचालन

एच.जी.वी.एम.एस के विकास के दौरान प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि सभी महत्वपूर्ण परिचालन प्रक्रियाएँ संरचित डिजिटल वर्कफ्लो के माध्यम से एकीकृत हों। इसी कारण प्रणाली को अनेक परस्पर संबद्ध मॉड्यूल के साथ विकसित किया गया, ताकि प्रशासनिक कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

मास्टर डेटा प्रबंधन

यह प्रणाली स्वयंसेवकों, बटालियनों, प्रशासनिक इकाइयों तथा मांग प्रस्तुत करने वाले विभागों से संबंधित केंद्रीकृत मास्टर अभिलेखों का संधारण करती है। मानकीकृत डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म में एकरूपता और सटीकता सुनिश्चित करता है।

होम गार्ड्स स्वयंसेवक नामांकन

नामांकन मॉड्यूल स्वयंसेवकों के डिजिटल पंजीकरण तथा अभिलेख प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। इससे मैनुअल कागजी कार्य में उल्लेखनीय कमी आती है तथा स्वयंसेवकों की जानकारी के त्वरित प्रसंस्करण और सत्यापन को बढ़ावा मिलता है।

चरित्र विवरण प्रबंधन

यह प्लेटफॉर्म स्वयंसेवकों के चरित्र विवरण तथा सेवा-संबंधी सूचनाओं के सुरक्षित डिजिटल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अभिलेखों का प्रभावी संधारण एवं पुनर्प्राप्ति संभव हो पाती है।

प्रशिक्षण प्रबंधन

परिचालन तत्परता और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रमों,



संजय कुमार
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sanjay.kmr@nic.in



विनोद कुमार गर्ग
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
vinod.garg@nic.in



मंगल सिंह
वैज्ञानिक - डी
s.mangal@nic.in

सहभागिता विवरणों तथा पूर्णता अभिलेखों के प्रबंधन हेतु संरचित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराती है।

मांग प्रस्तुत करने वाले विभागों का ऑनबोर्डिंग

विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेंसियाँ समय-समय पर अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की मांग प्रस्तुत करती हैं। एच.जी.वी.एम.एस.ए.एस. जैसे विभागों के लिए सुव्यवस्थित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया उपलब्ध कराता है, जिससे मानकीकृत डिजिटल संवाद सुनिश्चित होता है।

मांग प्रबंधन

मांग प्रबंधन मॉड्यूल तैनाती अनुरोधों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, अनुमोदन तथा निगरानी को सक्षम बनाता है। इससे प्रशासनिक विलंब में कमी आती है और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बेहतर होता है।

ड्यूटी आदेश प्रबंधन

ड्यूटी आवंटन एवं तैनाती आदेश प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है तथा समयबद्ध संचार सुनिश्चित होता है।

उपस्थिति प्रबंधन

उपस्थिति रिकॉर्डिंग एवं निगरानी को डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे स्वयंसेवकों की तैनाती और ड्यूटी निष्पादन की सटीक ट्रैकिंग संभव हो पाती है।

वेतन एवं मानदेय प्रबंधन

यह प्लेटफ़ॉर्म वेतन एवं मानदेय प्रसंस्करण को भी स्वचालित बनाता है, जिससे भुगतान प्रबंधन में विलंब कम होता है तथा पारदर्शिता बढ़ती है। होम गार्ड्स स्वयंसेवक प्रणाली के माध्यम से अपनी तैनाती स्थिति, उपस्थिति तथा भुगतान संबंधी जानकारी को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

पारदर्शिता और परिचालन दक्षता को सुदृढ़ बनाना

एच.जी.वी.एम.एस. के विकास के दौरान प्रमुख फोकस सभी प्रशासनिक स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। यह प्रणाली परिचालन संबंधी सूचनाओं का एक केंद्रीकृत भंडार उपलब्ध कराती है, जिससे प्राधिकरण गतिविधियों की अधिक प्रभावी निगरानी कर सकते हैं।

डिजिटल वर्कफ़्लो खंडित मैनुअल अभिलेखों पर निर्भरता

▼ चित्र 7.1: माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह द्वारा होम गार्ड वॉलंटियर्स मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ



को न्यूनतम करते हैं तथा त्रुटियों और असंगतियों की संभावनाओं को उल्लेखनीय रूप से कम करते हैं। मांग प्रस्तुत करने से लेकर उपस्थिति रिकॉर्डिंग और मानदेय निर्माण तक प्रत्येक चरण का डिजिटल रूप से ट्रैकिंग एवं ऑडिट किया जा सकता है।

यह प्लेटफ़ॉर्म प्रशासकों को रिपोर्ट तैयार करने, तैनाती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने तथा परिचालन गतिविधियों की रियल-टाइम निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है। ये क्षमताएँ प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अधिक त्वरित और सूचित निर्णय लेने में सहायता करती हैं।

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के लिए यह प्लेटफ़ॉर्म तैनाती विवरण तथा भुगतान स्थिति की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराकर अधिक पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करता है। इससे प्रशासन और स्वयंसेवकों के बीच विश्वास तथा संवाद दोनों मजबूत होते हैं।

प्रौद्योगिकी संरचना और प्रणाली डिज़ाइन

प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से एच.जी.वी.एम.एस. को स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक माइक्रोसर्विसेज आधारित आर्किटेक्चर पर विकसित किया गया है।

यह प्लेटफ़ॉर्म एक सख्त माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर का पालन करता है, जिसमें प्रत्येक व्यावसायिक क्षमता को एक स्वतंत्र सेवा के रूप में लागू किया गया है। यह मॉड्यूलर दृष्टिकोण रखरखाव, स्केलेबिलिटी तथा लचीलेपन को बेहतर बनाता है और भविष्य के उन्नयन एवं एकीकरण को सरल करता है।

पूरे प्लेटफ़ॉर्म को डॉकर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कंटेनरीकृत किया गया है तथा लिनक्स सर्वरों पर एन.जी.आई.एन.एक्स. (ओपनरेस्टी) रिवर्स प्रॉक्सी अवसंरचना के पीछे परिनियोजित किया गया है। बाहरी उपयोगकर्ता ट्रैफिक सुरक्षित एच.टी.टी.पी.एस. चैनलों के माध्यम से एन.जी.आई.एन.एक्स. में प्रवेश करता है, जो अनुरोधों को बुद्धिमतापूर्वक उपयुक्त फ्रंटएंड और बैकएंड कंटेनरों तक मार्गित करता है।

सेवाएँ सुरक्षित आर.ई.एस.टी.पी.आई. के माध्यम से एक-दूसरे से संवाद करती हैं, जिससे पूरे तंत्र में सुरक्षित एवं निर्बाध डेटा विनिमय सुनिश्चित होता है।

यह आर्किटेक्चर अनेक परिचालन एवं तकनीकी लाभ प्रदान करता है :

- बेहतर स्केलेबिलिटी और प्रदर्शन
- त्रुटियों का बेहतर पृथक्करण और विश्वसनीयता

- सरल परिनियोजन और रखरखाव
- संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग
- सुरक्षित और उच्च उपलब्धता वाली परिचालन व्यवस्था
- भविष्य के विस्तार और एकीकरण के लिए लचीलापन

कंटेनरीकृत परिनियोजन मॉडल पोर्टेबिलिटी और प्रभावी अवसंरचना प्रबंधन भी सुनिश्चित करता है, जिससे यह प्लेटफ़ॉर्म बदलती परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है।

डेटा-आधारित सुशासन को सहयोग

एच.जी.वी.एम.एस. को केवल एक परिचालन अनुप्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि प्रशासकों और नीति-निर्माताओं के लिए निर्णय-सहायक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में भी डिज़ाइन किया गया है।

केंद्रीकृत डेटाबेस और एनालिटिक्स-सक्षम वर्कफ़्लो तैनाती प्रवृत्तियों, उपस्थिति पैटर्न, स्वयंसेवक उपयोग तथा भुगतान प्रसंस्करण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करते हैं। ऐसी जानकारीयें बेहतर योजना निर्माण, संसाधन अनुकूलन तथा परिचालन निगरानी में सहायता करती हैं।

प्रणालीगत गतिविधियों की रियल-टाइम दृश्यता प्राधिकरणों को अवरोधों की शीघ्र पहचान करने और प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार यह प्लेटफ़ॉर्म डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा एकीकृत डिजिटल प्रशासन के माध्यम से सुशासन को सुदृढ़ बनाने में योगदान देता है।

भविष्य की रूपरेखा

भविष्य की रूपरेखा में स्वयंसेवकों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, एसएमएस एवं व्हाट्सएप सूचनाएं, जीआईएस आधारित तैनाती ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा एआई आधारित एनालिटिक्स डैशबोर्ड जैसी सुविधाओं को शामिल करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, स्टेट ट्रेजरी सिस्टम, ई-ऑफिस एकीकरण तथा आपदा प्रतिक्रिया कमांड डैशबोर्ड का समावेश भी प्रस्तावित है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और सशक्त बनाया जा सके।

निष्कर्ष

एच.जी.वी.एम.एस. का विकास हिमाचल प्रदेश होम गार्ड्स विभाग तथा एनआईसी हिमाचल प्रदेश के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक, सुरक्षित एवं दक्ष डिजिटल गवर्नेस प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है। इस प्रणाली को विभागीय कार्यप्रवाह को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने, मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। स्केलेबल एवं वर्कफ़्लो-आधारित आर्किटेक्चर पर निर्मित यह प्रणाली हिमाचल प्रदेश में होम गार्ड स्वयंसेवकों के प्रबंधन एवं तैनाती को अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ राज्य की डिजिटल गवर्नेस की परिकल्पना को भी सशक्त करेगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना अधिकारी

एनआईसी हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र
छठी मंजिल, आर्म्सडिल बिल्डिंग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171002
ई-मेल: sio-hp@nic.in, फोन: 0177 - 2624045

सेवा सेतु शिकायत प्रबंधन ढांचा

एन8एन-संचालित बुद्धिमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान

संपादित : विनोद कुमार गर्ग

पारंपरिक शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाएँ मुख्यतः मैनुअल ट्रायेजिंग और स्थिर नियम-आधारित कार्यप्रवाहों पर निर्भर रहती हैं। इसके कारण ऐसे “फ्रिक्शन पॉइंट्स” उत्पन्न होते हैं, जहाँ उपयोगकर्ता द्वारा चुनी गई श्रेणियों और वास्तविक आशय के बीच असंगति के चलते शिकायतों की गलत रूटिंग, लंबित प्रसंस्करण कतारें तथा एसएलए उल्लंघन जैसी समस्याएँ सामने आती हैं।

सेवा सेतु (sewasetu.assam.gov.in) जैसे नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण प्लेटफॉर्म, जो वर्तमान में प्रतिदिन 10,000 से अधिक आवेदनों को संभालते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। वेब पोर्टल, ई-मेल और कॉल सेंटर जैसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें असंरचित डाटा की निरंतर धारा उत्पन्न करती हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए एनआईसी असम ने एन8एन को केंद्रीय ऑर्केस्ट्रेशन लेयर के रूप में उपयोग करते हुए एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिकायत प्रबंधन ढांचा विकसित किया। यह ढांचा सेवा सेतु शिकायत डाटासेट पर फाइन-ट्यून किए गए बर्ट-आधारित ट्रांसफॉर्मर मॉडल का उपयोग करता है, जो असंरचित शिकायत पाठ का विश्लेषण कर वास्तविक आशय और संदर्भ की सटीक पहचान करता है, साथ ही सरकारी अवसंरचना के भीतर डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इससे शिकायतों की पूर्वनिर्धारित कार्यप्रवाहों में गतिशील रूटिंग संभव होती है।

इस ढांचे के माध्यम से:

- भुगतान संबंधी शिकायतों का “जीरो-टच” स्वचालित समाधान किया जाता है, जहाँ प्रणाली भुगतान गेटवे से जानकारी सत्यापित कर सफल लेनदेन को बिना मानवीय हस्तक्षेप के बंद कर देती है।
- सेवा-विलंब से संबंधित मामलों को 24 घंटे के बैच में संकलित



प्रांजल बेजबरुआह
उप महानिदेशक व एसआईओ
bezbaruah.p@nic.in



राहुल डेका
वैज्ञानिक - डी
r.deka@nic.in



एनआईसी असम द्वारा विकसित “सेवा सेतु शिकायत प्रबंधन ढांचा” एक एन8एन-संचालित एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान है, जो शिकायतों के वर्गीकरण, रूटिंग और समाधान की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। इंटेन्ट इन्फरेंस के लिए फाइन-ट्यून किए गए रोबर्ट मॉडल का उपयोग करते हुए यह प्रणाली “जीरो-टच” भुगतान समाधान, बुद्धिमान सेवा-विलंब निगरानी तथा स्वचालित तकनीकी टिकट प्रबंधन सक्षम करती है। यह ढांचा शिकायत वर्गीकरण की सटीकता बढ़ाता है, समाधान समय कम करता है, एसएलए अनुपालन को मजबूत बनाता है तथा सक्रिय और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन को बढ़ावा देता है।



कर विभागीय समीक्षा और निगरानी हेतु स्वचालित रूप से भेजा जाता है।

- तकनीकी समस्याओं को स्वतः संबंधित डेवलपर्स को आवंटित किया जाता है और उन्हें Jira या Taiga जैसे परियोजना प्रबंधन प्लेटफॉर्म पर ट्रैक योग्य टिकटों में परिवर्तित किया जाता है।

यह ऑर्केस्ट्रेशन ढांचा 90 प्रतिशत से अधिक ट्रायेज सटीकता के साथ मैनुअल प्रयासों को उल्लेखनीय रूप से कम करता है और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को प्रतिक्रियात्मक मॉडल से सक्रिय सेवा-स्तरीय शासन की दिशा में परिवर्तित करता है।

प्रस्तावित समाधान

यह ढांचा पारंपरिक रैखिक और नियम-आधारित शिकायत

प्रबंधन प्रणाली के स्थान पर एन8एन पर आधारित एक केंद्रीकृत एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर प्रदान करता है। एन8एन एक लो-कोड वर्कफ्लो इंजन के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न प्रणालियों के बीच शिकायत प्राप्ति, बुद्धिमान निर्णय-निर्माण और आगे की प्रक्रियाओं का समन्वय करता है। टिकटिंग प्लेटफॉर्म, संचार माध्यमों और बाहरी एपीआई के साथ सहज एकीकरण के माध्यम से यह ढांचा बिना जटिल कस्टम कोड की आवश्यकता के अत्यधिक कॉन्फिगर योग्य बना रहता है।

यह समाधान केवल साधारण स्वचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटेन्ट इन्फरेंस को गतिशील निष्पादन के साथ जोड़ता है। नियमित मामलों का समाधान स्वचालित रूप से किया जाता है, जबकि जटिल मामलों को पूर्ण संदर्भ और ऑडिट ट्रेकिंग के साथ संबंधित टीमों को भेजा जाता है।

समाधान दृष्टिकोण

इस ढांचे को एक मानकीकृत चार-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया है: एपीआई हैडशेक, पेलोड मैपिंग, लॉजिक कॉन्फिगरेशन और डेशबोर्ड सिंक्रोनाइजेशन। चित्र-1 में दर्शाए अनुसार, जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, सुरक्षित वेबहुक के माध्यम से कार्यप्रवाह सक्रिय हो जाता है और चार अलग-अलग स्तरों में स्वचालित प्रोसेसिंग पाइपलाइन प्रारंभ हो जाती है।

शिकायत प्री-प्रोसेसिंग और संज्ञानात्मक वर्गीकरण

संज्ञानात्मक स्तर पर सेवा सेतु शिकायत डाटासेट पर फाइन-ट्यून किया गया RoBERTa मॉडल, जो BERT आधारित पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल का उन्नत संस्करण है, कच्चे शिकायत पाठ का विश्लेषण कर उसे तीन प्रमुख श्रेणियों — भुगतान संबंधी, सेवा विलंब और तकनीकी शिकायतों — में वर्गीकृत करता है।

- **इंटेन्ट इन्फरेंस:** मॉडल को ऐतिहासिक डाटा पर प्रशिक्षित किया गया है ताकि यह सामान्य शब्दावली और विफलता परिदृश्यों की पहचान कर सके। इससे ड्रॉपडाउन चयन गलत होने पर भी उपयोगकर्ता के वास्तविक आशय का सही अनुमान लगाया जा सकता है।
- **डाटा रेजिडेंसी:** स्थानीय निष्पादन यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील सरकारी डाटा सुरक्षित अवसंरचना के भीतर ही रहे, साथ ही लगभग रियल-टाइम विश्लेषण भी उपलब्ध हो सके।
- **डायनेमिक निर्णय-निर्माण:** यह स्तर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए त्रुटिपूर्ण इनपुट को अनदेखा कर सटीक संदर्भ ऑर्केस्ट्रेशन प्रवाह को प्रदान करता है, जहाँ शिकायतों की रूटिंग और आवश्यक कार्रवाई गतिशील रूप से निर्धारित की जाती है।

बहु-पथ कार्यप्रवाह निष्पादन

ऑर्केस्ट्रेशन लेयर तीन प्रमुख कार्यप्रवाहों के लिए निर्णय-तर्क, पुनः प्रयास तथा स्थिति ट्रैकिंग का प्रबंधन करती है:

- **भुगतान संबंधी शिकायतें (जीरो-टच):** प्रणाली भुगतान गेटवे से लेनदेन की स्थिति की पुष्टि करती है। सफल लेनदेन स्वतः बंद कर दिए जाते हैं और नागरिकों को एसएमएस सूचना भेजी जाती है। वहीं, असफल या संदिग्ध मामलों को आगे की जाँच के लिए जीरा या टैगा जैसे परियोजना प्रबंधन प्लेटफॉर्म पर ट्रैक योग्य टिकट के रूप में सेवा इंजीनियरों को भेजा जाता है।

- **सेवा विलंब मामले (बुद्धिमान समेकन):** व्यक्तिगत अलर्ट भेजने के बजाय इन मामलों को 24 घंटे के बैच में संकलित किया जाता है। इसके बाद विभागों को निर्धारित सुबह की रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे अत्यधिक सूचनाओं के दबाव के बिना व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

- **तकनीकी समस्याएँ (अपवाद रूटिंग):** तकनीकी समस्याओं को सीधे संबंधित सेवा इंजीनियरों को मैप किया जाता है। टैगा या जीरा में संरचित टिकट तैयार कर के संबंधित हितधारकों को सलैक या प्रत्यक्ष संदेशों के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाता है।

सिंक्रोनाइजेशन, स्थायित्व और डैशबोर्डिंग

एक्शन लेयर निरंतर सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से टिकटिंग प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले “ब्लैक होल” को समाप्त करती है।

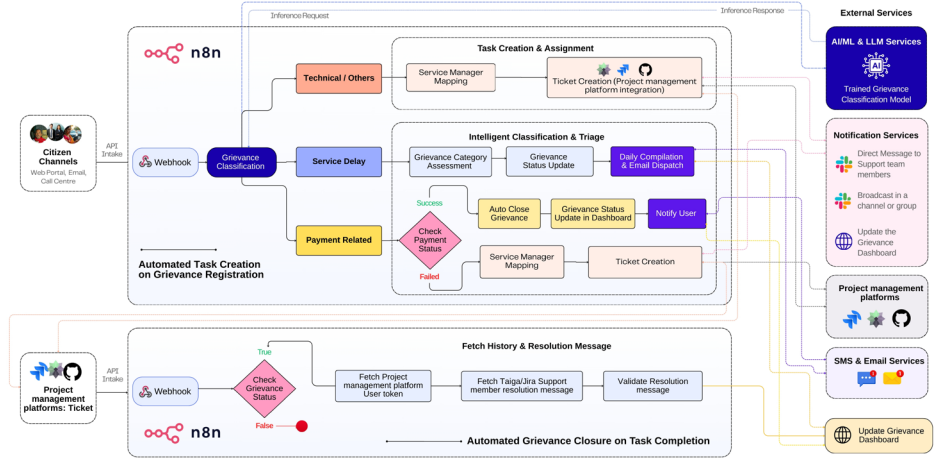
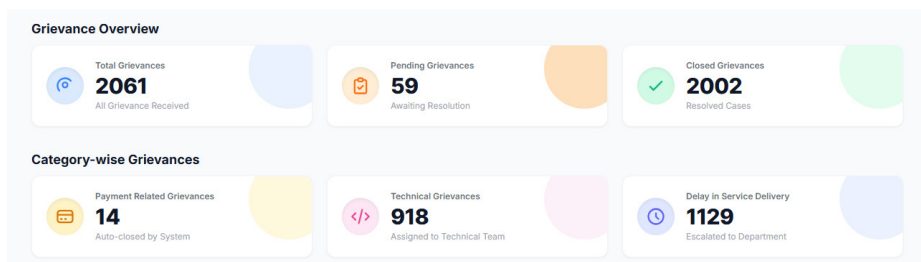
- **स्वचालित समापन:** प्रणाली बाहरी प्लेटफॉर्म की निरंतर निगरानी करती है। जब कोई इंजीनियर टिकट बंद करता है, तब एन8एन समाधान संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त कर मूल शिकायत रिकॉर्ड को रियल-टाइम में अपडेट कर देता है।

- **प्रक्रिया स्थायित्व:** स्टेट पर्सिस्टेंस और ऑटो-रिट्राई लॉजिक यह सुनिश्चित करते हैं कि बाहरी प्रणाली में व्यवधान आने पर भी कोई डाटा नष्ट न हो।

▼ चित्र 8.1 : प्रदर्शन प्रभाव और मेट्रिक्स

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक	पारंपरिक मैनुअल प्रक्रिया	एजेंटिक ढांचा
ट्रायेज सटीकता	लगभग 95-100% (मैनुअल)	94% से अधिक (AI सत्यापित)
औसत समाधान समय	दिन/सप्ताह	मिनटों में (सामान्य)/ 24 घंटे से कम (जटिल)
स्वचालित समाधान दर	नहीं	उच्च (जीरो-टच)
एस्केलेशन दर	अधिक	उल्लेखनीय रूप से कम
एसएलए अनुपालन	प्रतिक्रियात्मक	सक्रिय एवं स्वचालित

▼ चित्र 8.2 : शिकायत डैशबोर्ड



▲ चित्र 8.3 शिकायत प्रबंधन ढांचा

- **एकीकृत विश्लेषण:** शिकायत विश्लेषण डैशबोर्ड, जैसा कि चित्र-2 में दर्शाया गया है, कुल मामलों, समाधान दरों और श्रेणी-स्तरीय रुझानों का समेकित दृश्य प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2026 में प्राप्त 1,722 शिकायतों का विश्लेषण डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया गया। यह दृश्यता प्रणालीगत समस्याओं की प्रारंभिक पहचान कर सक्रिय हस्तक्षेप को सक्षम बनाती है।

प्रदर्शन प्रभाव एवं मापदंड

सेवा सेतु में इस ढांचे के कार्यान्वयन ने मैनुअल ट्रायेजिंग को समाप्त कर परिचालन कार्यप्रणाली में मूलभूत परिवर्तन किया है। एजेंटिक ढांचे ने नियम-आधारित बाधाओं को बुद्धिमान ऑर्केस्ट्रेशन से प्रतिस्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रदर्शन सुधार प्राप्त हुए हैं जो कि चित्र : 8.1 में दिए गये हैं।

नियंत्रण और विश्वसनीयता

यह ढांचा केवल साधारण स्वचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्तर की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया स्थायित्व को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसके प्रमुख नियंत्रण तंत्र निम्नलिखित हैं:

- **एसएलए आधारित एस्केलेशन:** स्वचालित निगरानी प्रणाली प्रतिक्रिया समय-सीमा के उल्लंघन होने पर स्वतः एस्केलेशन सक्रिय कर देती है।

- **कॉन्फिगर योग्य रूटिंग:** विभाग-विशिष्ट लॉजिक और स्वामित्व नियमों को एन8एन के भीतर बिना मूल कोड में परिवर्तन किए अद्यतन किया जा सकता है।

- **मल्टी-चैनल सूचनाएँ:** हितधारकों को ई-मेल, एसएलएck, एसएमएस तथा समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।

- **स्टेट पर्सिस्टेंस:** अंतर्निहित स्टेट पर्सिस्टेंस यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई बाहरी प्रणाली विफल हो जाए तो कार्यप्रवाह अंतिम रिकॉर्ड की गई स्थिति से पुनः प्रारंभ हो सके, जिससे डाटा हानि शून्य बनी रहे।

आगे की दिशा

यह ढांचा पूर्वानुमान आधारित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। नियमित ट्रायेजिंग प्रक्रियाओं को मानवीय प्रशासनिक भार से अलग कर राज्य सरकार अब उच्च-मूल्य नागरिक सेवाओं और हस्तक्षेपों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। यह मॉड्यूलर और एन8एन-आधारित संरचना तीव्र क्षैतिज विस्तार के लिए तैयार की गई है और भारत के सभी राज्य स्तरीय डिजिटल पोर्टलों पर बुद्धिमान शिकायत प्रबंधन के लिए एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करती है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र, छठी मंजिल, आम्सडिल भवन
एचपी सचिवालय, शिमला – 171002
ईमेल: sio-hp@nic.in, फ़ोन: 0177-2624045

मिशन भागीरथ

तेलंगाना का एकीकृत डिजिटल जल नेटवर्क

संपादित : निस्सी जॉर्ज



मिशन भागीरथ, तेलंगाना सरकार की एक प्रमुख पेयजल पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को सुरक्षित, शुद्ध एवं पाइपलाइन आधारित पेयजल उपलब्ध कराना है। लगभग 5.5 मिलियन परिवारों में 10 मिलियन नागरिकों को आच्छादित करते हुए यह विश्व के सबसे बड़े केंद्रीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति नेटवर्कों में से एक है।

इस स्तर पर केवल अवसंरचना पर्याप्त नहीं होती—इसके साथ-साथ दृश्यता, अनुसंधान और प्रणाली का रियल-टाइम में प्रभावी संचालन एवं शासन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य ने एक उन्नत एंटरप्राइज वेबजीआईएस-आधारित जल अवसंरचना प्रबंधन प्रणाली लागू की है। यह प्लेटफॉर्म एक राज्यव्यापी भू-स्थानिक निर्णय-सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो जल आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण—स्रोत से सेवा वितरण तक—एंड-टू-एंड दृश्यता प्रदान करता है। इस प्रकार यह तेलंगाना को प्रौद्योगिकी-सक्षम जल शासन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय मानक के रूप में स्थापित करता है।

एकीकृत डिजिटल जल नेटवर्क आर्किटेक्चर

एंटरप्राइज वेबजीआईएस प्लेटफॉर्म संपूर्ण जल आपूर्ति शृंखला—कच्चे जल के स्रोत से लेकर अंतिम घर-स्तरीय वितरण तक—एंड-टू-एंड भू-स्थानिक दृश्यता प्रदान करता है। यह एकीकृत डिजिटल परिवेश में सभी महत्वपूर्ण अवसंरचना घटकों का समेकन



मिशन भागीरथ का एंटरप्राइज वेबजीआईएस प्लेटफॉर्म ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को डेटा-आधारित शासन प्रणाली में रूपांतरित करता है। भू-स्थानिक एसेट मैपिंग, बस्ती-स्तरीय मॉनिटरिंग, रियल-टाइम एनालिटिक्स तथा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म लिंकिंग के एकीकरण के माध्यम से यह प्रणाली स्रोत से सेवा वितरण तक एंड-टू-एंड दृश्यता प्रदान करती है, सेवा विश्वसनीयता को सुदृढ़ करती है तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सार्वजनिक अवसंरचना प्रबंधन के लिए एक स्केलेबल और प्रतिरूपणीय मॉडल स्थापित करती है।



एवं स्थानिक मानचित्रण करता है, जिससे प्रणाली के डिज़ाइन और संचालन का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

यह प्रणाली निम्नलिखित अवसंरचना स्तरों को एकीकृत करती है:

स्रोत एवं बल्लक जल अवसंरचना

- सतही जलाशय
- इंटेक कुएँ एवं इंटेक संरचनाएँ
- कच्चे जल के ट्रांसमिशन मेन
- जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)

शोधित जल भंडारण एवं विनियमन

- सम्म
- ग्राउंड लेवल बैलेंसिंग रिज़र्वायर (जी.एल.बी.आर)
- ब्रेक प्रेशर टैंक (बीपीटी)
- ओवरहेड बैलेंसिंग रिज़र्वायर (ओ.एच.बी.आर)
- ओवरहेड सर्विस रिज़र्वायर (ओ.एच.एस.आर)

परिवहन एवं वितरण नेटवर्क

- ग्रेविटी मेन
- पम्पिंग मेन
- पम्पिंग स्टेशन एवं इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एसेट्स
- नियंत्रण वाल्व एवं दाब विनियमन प्रणालियाँ
- ग्राम-स्तरीय वितरण नेटवर्क
- कार्यात्मक धरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी)

इन सभी घटकों को एक एकीकृत भू-स्थानिक फ्रेमवर्क में समाहित करके यह प्लेटफॉर्म नेटवर्क का निर्बाध दृश्यांकन सक्षम बनाता है, प्रणाली-स्तरीय समझ को सुदृढ़ करता है तथा योजना निर्माण, निगरानी और संचालन प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करता है।

जोनिंग-आधारित नेटवर्क शासन मॉडल

हाइड्रोलिक परिवहन घटकों को प्रशासनिक एवं बस्ती सीमाओं के साथ एकीकृत करके यह प्रणाली जल आपूर्ति शृंखला की एंड-टू-एंड अनुसंधान सुनिश्चित करती है—स्रोत की स्थिरता से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक।

वेबजीआईएस अनुप्रयोग में बहु-स्तरीय प्रशासनिक सीमाएँ—सेगमेंट, जिला, मंडल, निर्वाचन क्षेत्र तथा बस्ती—को संबंधित सेवा जलाशयों के साथ व्यवस्थित रूप से जोड़ा गया है। यह संरचित भू-स्थानिक आर्किटेक्चर जल आपूर्ति नेटवर्क के योजना निर्माण, निगरानी और शासन के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करता है।

इस जोनिंग-आधारित संरचना के माध्यम से अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली के प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं, स्पष्ट स्थानिक अधिकार-क्षेत्रों के माध्यम से जवाबदेही को सुदृढ़ कर सकते हैं, सेवा अंतराल एवं वितरण असंतुलन की पहचान कर सकते हैं तथा समयबद्ध, डेटा-आधारित निर्णय ले सकते हैं।

प्रशासनिक पदानुक्रम को बस्ती-स्तरीय स्थानिक डेटा के साथ एकीकृत करते हुए यह प्लेटफॉर्म एक सुसंगत भू-स्थानिक इंटीग्रेजेंस लेयर स्थापित करता है। इस एकीकरण से परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा मिशन भागीरथ के अंतर्गत साक्ष्य-आधारित अवसंरचना योजना को मजबूती मिली है।

उन्नत कार्यात्मक क्षमताएँ

एंड-टू-एंड नेटवर्क कवरेज विश्लेषण

जीआईएस प्लेटफॉर्म इंटेक संरचनाओं से लेकर बस्ती-स्तरीय अंतिम बिंदु तक संपूर्ण नेटवर्क का ट्रेसिंग सक्षम बनाता है। इसके माध्यम से इंजीनियर सेवा कवरेज का आकलन करते हुए आंशिक



गुंटुकु प्रसाद

उप महानिदेशक व एसआईओ
gprasad@nic.in



टी बाला सुंदरम

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एचओडी
balasundaram@nic.in



कार्तिक कृष्ण विजयशरिदी

वैज्ञानिक - डी
kartik.m@gov.in

रूप से आच्छादित बस्तियों, टेल-एंड आपूर्ति कमियों, नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी तथा वितरण असमानताओं की पहचान कर सकते हैं।

यह स्थानिक विश्लेषण अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की प्राथमिकता निर्धारण तथा प्रभावी लास्ट-माइल कनेक्टिविटी योजना को सक्षम बनाता है।

अवसंरचना-विहीन बस्तियों की पहचान

प्रणाली भू-स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से उन बस्तियों की पहचान करती है जहाँ आवश्यक अवसंरचना का अभाव है, जैसे:

- ओ.एच.एस.आर की अनुपस्थिति
- पृथक या दूरस्थ बस्तियाँ
- पहाड़ी अथवा भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र
- नेटवर्क के डेड-एंड बिंदु

यह स्थानिक निदान लक्षित, सूक्ष्म-स्तरीय इंजीनियरिंग हस्तक्षेपों को सक्षम बनाता है, जैसे विकेन्द्रीकृत भंडारण, समर्पित पम्पिंग व्यवस्था, स्थानीय वैकल्पिक जल स्रोत तथा नेटवर्क पुनर्संरचना।

परिणामस्वरूप, जल सेवा वितरण अधिक समावेशी और संदर्भ-संवेदनशील बनता है।

ग्रामीण वितरण नेटवर्क का व्यापक डिजिटलीकरण

देश के सबसे बड़े ग्रामीण पाइपलाइन मानचित्रण अभियानों में से एक के अंतर्गत लगभग 65,000 किलोमीटर ग्राम-स्तरीय वितरण पाइपलाइन का डिजिटलीकरण मात्र छह माह की अवधि में किया गया।

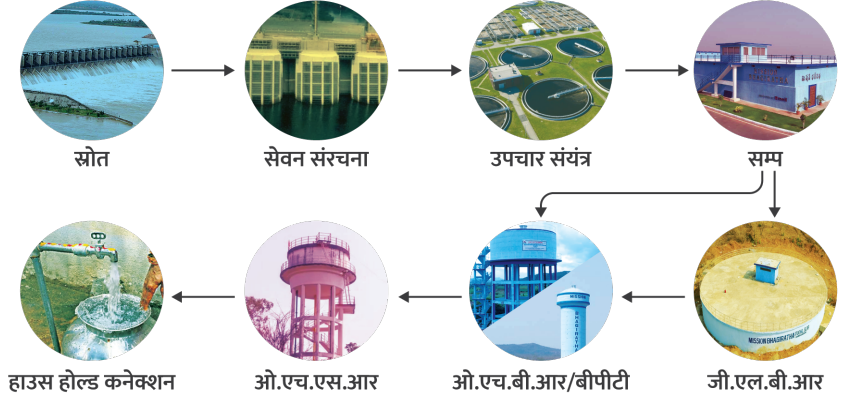
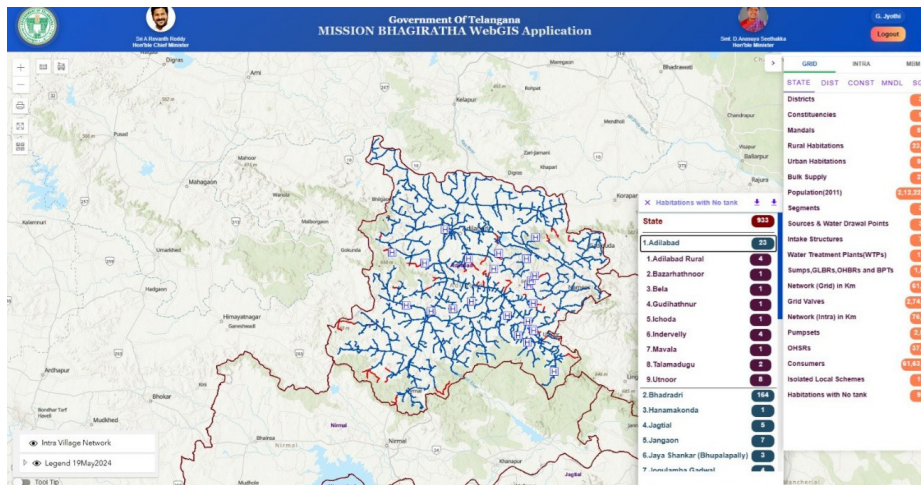
प्लेटफॉर्म में विकसित एक विशेष जीआईएस एडिटिंग टूल उच्च-रिज़ॉल्यूशन ईएसआरआई सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर ग्राम-स्तरीय पाइपलाइन का सटीक मानचित्रण सक्षम बनाता है।

कागज़-आधारित अभिलेखों से भू-संदर्भित डिजिटल एसेट्स की ओर यह परिवर्तन डेटा विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है, एसेट जीवनचक्र प्रबंधन को सक्षम बनाता है तथा दीर्घकालिक अवसंरचना योजना के लिए आधार प्रदान करता है।

रियल-टाइम जल आपूर्ति निगरानी डैशबोर्ड

प्लेटफॉर्म एक थीमैटिक, रंग-आधारित भू-स्थानिक डैशबोर्ड

▼ चित्र 9.1: मिशन भगीरथ वेबजीआईएस एप्लीकेशन



▲ चित्र 9.2

मिशन भगीरथ जल आपूर्ति प्रणाली

प्रदान करता है, जो राज्यभर में बस्ती-स्तरीय जल आपूर्ति की स्थिति का त्वरित अवलोकन सक्षम बनाता है।

आपूर्ति स्थिति वर्गीकरण:

- हरा – पूर्ण आपूर्ति
- नारंगी – औसत से अधिक आपूर्ति
- पीला – आंशिक आपूर्ति
- लाल – आपूर्ति नहीं

भू-स्थानिक दृश्यांकन के साथ परिचालन डेटा के एकीकरण से यह प्रणाली सेवा अंतराल की पहचान तथा पाइपलाइन क्षति, पम्प विफलता, विद्युत बाधा या स्रोत कमी जैसी परिचालन समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में सहायक होती है।

इससे निगरानी दक्षता बढ़ती है, प्रतिक्रिया समय घटता है और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होता है।

एकीकृत जल गुणवत्ता निगरानी

प्लेटफॉर्म राज्य की जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं का स्थानिक मानचित्रण करता है, जिसमें शामिल हैं:

- एनएबीएल मान्यता स्थिति
- परीक्षण मानक (रासायनिक एवं जीवाणु संबंधी)
- प्रयोगशाला उपकरण एवं अवसंरचना

- तकनीकी मानव संसाधन
- भू-स्थानिक लोकेशन

जीआईएस परिवेश में इन आंकड़ों के एकीकरण से राज्यभर में जल गुणवत्ता निगरानी अधिक सुदृढ़ एवं समन्वित होती है।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थानिक दृश्यांकन

उच्च-रिज़ॉल्यूशन ईएसआरआई सैटेलाइट इमेजरी के साथ एकीकरण से अवसंरचना एसेट्स का विस्तृत एवं सटीक भू-संदर्भित दृश्यांकन संभव होता है।

यह सुविधा पाइपलाइन संरक्षण के सत्यापन, स्थलाकृतिक विश्लेषण, भूमि उपयोग मूल्यांकन तथा नई अवसंरचना के सटीक नियोजन में सहायक होती है।

इमेजरी पर एसेट डेटा के ओवरले से स्थानिक सटीकता बढ़ती है तथा फील्ड-स्तरीय अनिश्चितताओं में कमी आती है।

राज्यव्यापी भू-स्थानिक जल अवसंरचना रिपॉजिटरी

यह प्लेटफॉर्म भारत के सबसे बड़े ग्रामीण जल जीआईएस रिपॉजिटरी में से एक का प्रबंधन करता है, जो संपूर्ण अवसंरचना जीवनचक्र—योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी, अनुरक्षण तथा नीतिगत निर्णय—के लिए एक एकीकृत डिजिटल आधार प्रदान करता है।

प्रणाली वर्तमान में राज्यभर में जल अवसंरचना तथा प्रशासनिक कवरेज से संबंधित व्यापक भू-स्थानिक डेटा का संधारण करती है:

प्रशासनिक कवरेज

- 32 जिले
- 99 निर्वाचन क्षेत्र
- 31 सेगमेंट
- 572 मंडल
- 23,671 ग्रामीण बस्तियाँ
- 943 शहरी बस्तियाँ

स्रोत एवं इंटेक अवसंरचना

- 32 सतही जल स्रोत
- 78 इंटेक संरचनाएँ

शोधन एवं भंडारण अवसंरचना

- 123 जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)

ई-गवर्नेंस उत्पाद और सेवाएँ

- 775 सम्प
- 190 ग्राउंड लेवल बैलेंसिंग रिजर्वार (जी.एल.बी.आर)
- 210 ब्रेक प्रेशर टैंक (बीपीटी)
- 691 ओवरहेड बैलेंसिंग रिजर्वार (ओ.एच.बी.आर)
- 36,473 ग्राम स्तरीय ओवरहेड सर्विस रिजर्वार (ओ.एच.एस.आर)

नेटवर्क अवसंरचना एवं कवरेज

- 1.35 लाख किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क
- 292 बल्क जल आपूर्ति कनेक्शन
- लगभग 2.4 करोड़ जनसंख्या का कवरेज

यह विस्तृत भू-स्थानिक रिपॉजिटरी एक विश्वसनीय एवं एकीकृत डेटा आधार के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर समन्वित अवसंरचना प्रबंधन तथा सूचित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाती है।

राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण

वेबजीआईएस प्लेटफॉर्म का एकीकरण पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल के साथ किया गया है, जिससे संरचित भू-स्थानिक डेटा विनिमय तथा पाइपलाइन नेटवर्क लेयर्स का राष्ट्रीय अवसंरचना ढांचे में मानकीकृत समावेशन संभव हो सका है। यह एकीकरण राज्य-स्तरीय अवसंरचना प्रणालियों और राष्ट्रीय योजना पहलों के बीच समन्वय स्थापित करता है, जिससे अवसंरचना विकास अधिक सुसंगत और एकीकृत रूप से संचालित होता है।

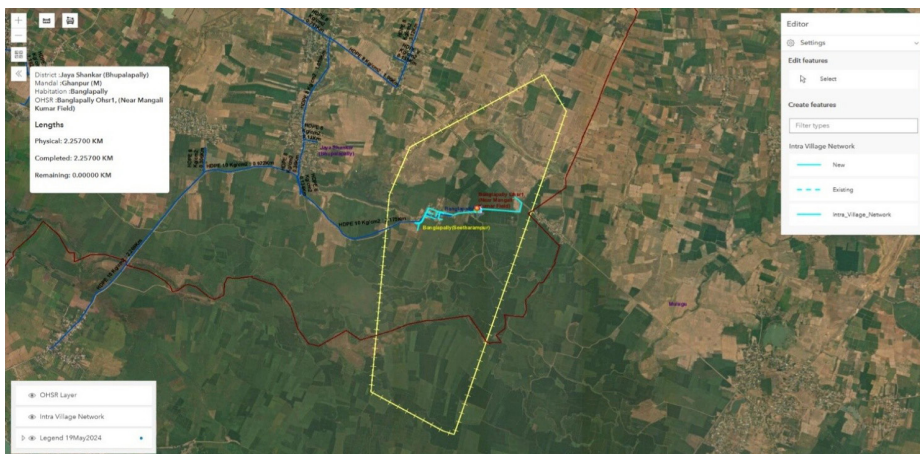
गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के साथ निर्बाध अंतर-संचालनीयता विभिन्न क्षेत्रों—जैसे सड़क, ऊर्जा, सिंचाई एवं दूरसंचार—के बीच बहु-क्षेत्रीय योजना निर्माण को भी सुदृढ़ करती है।

जल अवसंरचना को व्यापक राष्ट्रीय भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में समाहित करके यह प्रणाली विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा एकीकृत निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही

जीआईएस-सक्षम मानचित्रण और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड के उपयोग से प्रणाली की निगरानी और सेवा वितरण में पारदर्शिता सुदृढ़ हुई है। स्थान-आधारित विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता

▼ चित्र 9.3 : ग्राम के भीतर जल आपूर्ति नेटवर्क



मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मिशन भागीरथ विभाग डिजिटल रूपांतरण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मिशन भागीरथ का वेबजीआईएस-आधारित जल अवसंरचना निगरानी तंत्र एक सशक्त शासन उपकरण के रूप में उभरा है, जिसने राज्य की पेयजल आपूर्ति प्रणाली के योजना निर्माण, निगरानी तथा प्रबंधन की हमारी क्षमता को सुदृढ़ किया है।

वेबजीआईएस अनुप्रयोग सतही जल स्रोतों से लेकर बस्ती-स्तर तक पेयजल अवसंरचना का एंड-टू-एंड स्थानिक दृश्यांकन प्रदान करता है, जिससे प्रभावी एसेट निगरानी और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। इस पहल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे फील्ड इंजीनियरों द्वारा अल्प समय में लगभग 65,000 किलोमीटर ग्राम-स्तरीय पाइपलाइन नेटवर्क का डिजिटलीकरण है, जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एन.जे.जे.एम) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

कार्यात्मकता-आधारित एसेट डैशबोर्ड, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला संबंधी जानकारी तथा जल आपूर्ति स्थिति डैशबोर्ड जैसी उन्नत सुविधाओं ने पारदर्शिता, निगरानी और डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।

यह प्लेटफॉर्म शासन का एक अनिवार्य उपकरण बन गया है, जो तेलंगाना के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के विभागीय दृष्टिकोण के साथ पूर्णतः अनुरूप है। सिंचाई विभाग के जलाशयों के जल-स्तर डेटा के साथ इसका एकीकरण तथा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल के साथ एसेट जानकारी का समन्वय प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय को दर्शाता है।

मैं इस पहल के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी सहयोग एवं विशेषज्ञता के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।



श्री जी. कृपाकर, प्रमुख अभियंता (ईएनसी) विभागाध्यक्ष मिशन भागीरथ, तेलंगाना सरकार

विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर अधिक सुसंगत और साक्ष्य-आधारित पर्यवेक्षण को संभव बनाती है।

भूमिका-आधारित अभिगम (रोल-बेस्ड एक्सेस) के माध्यम से निर्णय-निर्माता रियल-टाइम के निकट अवसंरचना प्रदर्शन और सेवा स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। इससे एसेट्स और परिचालन प्रक्रियाओं की अनुसंधानीयता बढ़ती है, सेवा अंतराल की समय पर पहचान होती है तथा अधिक जवाबदेह और परिणामोन्मुख शासन को बढ़ावा मिलता है।

खंडित रिपोर्टिंग प्रणालियों से हटकर एक एकीकृत भू-स्थानिक डेटा फ्रेमवर्क की ओर यह परिवर्तन न केवल दृश्यता को बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन में संस्थागत जवाबदेही को भी सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

मिशन भागीरथ का वेबजीआईएस प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी के जल शासन के लिए एक समग्र, प्रौद्योगिकी-सक्षम ढांचा प्रस्तुत करता है। एंड-टू-एंड एसेट जियो-टैगिंग, बस्ती-स्तरीय सेवा निगरानी, रियल-टाइम विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड, उच्च-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, जल गुणवत्ता निगरानी तथा अंतर-विभागीय डेटा एकीकरण के माध्यम से इस प्रणाली ने ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना के योजना, निगरानी और प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया है।

यह प्लेटफॉर्म केवल अवसंरचना प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक डेटा-आधारित, गतिशील शासन मॉडल की ओर स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है। एकीकृत भू-स्थानिक परिवेश में संपूर्ण जल आपूर्ति नेटवर्क का दृश्यांकन, विश्लेषण और सतत निगरानी परिचालन दक्षता को बढ़ाता है, सेवा विश्वसनीयता में सुधार करता है तथा त्वरित और सूचित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाता है।

एक स्केलेबल और अंतर-संचालनीय प्रणाली के रूप में यह मॉडल अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों—जैसे सिंचाई, ऊर्जा वितरण और शहरी उपयोगिताओं—के लिए भी एक उपयोगी संदर्भ ढांचा प्रदान करता है, जहाँ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा वितरण में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना अधिकारी
एनआईसी तेलंगाना राज्य केंद्र
ए-ब्लॉक, बीआरकेआर भवन, टैंक बंड रोड
हैदराबाद, तेलंगाना - 500004
ई-मेल: sio-tg@nic.in, फोन: 040-23229474

संघमित्रा

एनआईसी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक आत्मचिंतन

8 मार्च 2026 को, नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रशासनिक ब्लॉक के सभागार में एक जीवंत और सार्थक आयोजन देखने को मिला, जब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर एनआईसी की महिला कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न प्रभागों से आउटसोर्स की गई महिला स्टाफ भी एकत्रित हुईं, ताकि संगठन और समाज में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित और सराहा जा सके।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसने आयोजन को एक औपचारिक, गरिमामय और प्रेरणादायक स्वर प्रदान किया। इसके बाद प्रतिभागियों के बीच रचनात्मकता और आपसी सहयोग को दर्शाने वाली विभिन्न गतिविधियों की एक सुविचारित और आकर्षक श्रृंखला प्रस्तुत की गई।

इस उत्सव में संगीत, सहकर्मियों द्वारा विचार-विमर्श, आत्मविश्वास से भरपूर और उत्साहपूर्ण रैप वॉक, तथा इंटरैक्टिव टीम-बिल्डिंग खेल जैसी विविध प्रस्तुतियाँ और सहभागिताएँ शामिल थीं। एक तकनीक-आधारित क्विज ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बौद्धिक आयाम जोड़ा, जो एनआईसी की कार्य संस्कृति में ज्ञान और विशेषज्ञता की केंद्रीय भूमिका को प्रभावी रूप से रेखांकित करता है। इन गतिविधियों ने न केवल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि एकता, सहयोग और साझा उद्देश्य की भावना को भी और अधिक मजबूत किया।

इस आयोजन की शोभा बढ़ाई एनआईसी के महानिदेशक, श्री अभिषेक सिंह ने, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों में श्री राजेश पाठक, श्रीमती साधना पाठक, श्री वीटीवी रमना और श्री अशोक कोल की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। उनकी उपस्थिति ने इस अवसर के महत्व को और अधिक रेखांकित किया और महिला पेशेवरों के योगदान को स्वीकारने और समर्थन देने के प्रति संगठन की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाया।

कार्यक्रम का एक विशेष और महत्वपूर्ण भाग वर्ष की महिला सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान था। उनकी वर्षों की समर्पित, निष्ठापूर्ण सेवा को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई, जिसने संगठन में उनके स्थायी और प्रेरणादायक योगदान को उजागर किया और सभी उपस्थित लोगों पर गहरी तथा सकारात्मक छाप छोड़ी।

अपने संबोधन में महानिदेशक ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और भारत के डिजिटल वर्गों में तंत्र को सशक्त बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि



विविधता और समावेशिता नवाचार और संगठनात्मक विकास के प्रमुख प्रेरक तत्व हैं, और एनआईसी एक समान, समावेशी और सहयोगात्मक कार्य वातावरण को निरंतर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस कार्यक्रम की संकल्पना और क्रियान्वयन कम समय में श्रीमती उषा सक्सेना, श्रीमती अनुपम श्रीवास्तव, श्रीमती राम्या राजमणिकम और श्रीमती ऋचा तिवारी द्वारा, डॉ. राजेश पाठक और श्री दीपक सक्सेना के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। प्रशासन, वित्त और अवसरचना प्रभागों द्वारा प्रदान किए गए सुचारु समन्वय और निरंतर सहयोग ने कार्यक्रम की सफलता को पूर्णतः सुनिश्चित किया।

एनआईसी के मल्टीमीडिया प्रभाग ने इस आयोजन का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया और इसके मुख्य अंशों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, जिससे कार्यक्रम की पहुँच सभागार से बाहर तक और भी अधिक व्यापक रूप से विस्तारित हुई।

यह आयोजन न केवल एनआईसी में महिलाओं की उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देने का सशक्त माध्यम बना, बल्कि संस्थानों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रभावशाली याद दिलाता है। इसने इस समझ को और मजबूत किया कि जहाँ तकनीक एनआईसी के मिशन की रीढ़ है, वहीं लोग—विशेष रूप से महिलाओं का समर्पण, धैर्य और दृढ़ता—वास्तव में इसकी प्रगति को निरंतर आगे बढ़ाते हैं।



आईडीसी तिरुवनंतपुरम् मॉडल

सरकारी अवसंरचना हेतु सुरक्षित देव-ऑप्स प्रयोगशाला का निर्माण

संपादित : संपादित : मोहन दास विश्वम्



मो हाल के वर्षों में माइक्रोसर्विस आधारित और क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर की ओर बढ़ते बदलाव ने सरकारी अनुप्रयोगों के डिजाइन और डिलीवरी के तरीके को धीरे-धीरे बदल दिया है। पहले जहाँ सिस्टम धीमी गति से विकसित होते थे, वहीं अब तेज बदलाव, निरंतर एकीकरण और मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। हालाँकि, सरकारी अवसंरचना के भीतर यह परिवर्तन नियंत्रित, संप्रभु और नीति-अनुरूप वातावरण में ही लागू किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में एनआईसी के आईडीसी तिरुवनंतपुरम् में स्थापित देव-ऑप्स लैब सामने आती है जो केवल एक तकनीकी सेटअप नहीं, बल्कि सरकारी सीमाओं के भीतर आधुनिक एप्लिकेशन जीवनचक्र प्रबंधन का एक कार्यशील मॉडल है।

एनआईसी सीईएम कोचि द्वारा स्थापित यह लैब एक हैंड्स-ऑन लर्निंग और डेमो प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार की गई है। यह आईडीसी अवसंरचना के भीतर समर्पित वर्चुअल मशीनों का उपयोग करते हुए एक वास्तविक एंटरप्राइज देव-ऑप्स सिस्टम का अनुकरण करती है। प्रत्येक मशीन को एक विशेष भूमिका दी गई है, और सभी मिलकर एक ऐसा एकीकृत वातावरण बनाती हैं जहाँ विकास, परिनियोजन, सुरक्षा और मॉनिटरिंग एक निरंतर और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं।

कोड से नागरिक सेवा तक: एक एकीकृत देव-ऑप्स आर्किटेक्चर

आईडीसी देव-ऑप्स लैब का मूल एक सुव्यवस्थित पाइपलाइन है, जो स्रोत कोड से शुरू होकर सुरक्षित और मॉनिटर की गई सेवा डिलीवरी तक पहुँचती है। यह केवल अलग-अलग टूल्स का समूह नहीं है, बल्कि एक निरंतर और आपस में जुड़े हुए कार्यप्रवाह का हिस्सा है, जहाँ प्रत्येक घटक दूसरे के साथ समन्वय में काम करता है।

यह प्रक्रिया वर्जन-कंट्रोल कोड से शुरू होती है, स्वचालित एकीकरण और परीक्षण से गुजरती है, फिर कंटेनर आधारित परिनियोजन तक पहुँचती है, और अंततः सुरक्षित तथा नियंत्रित एक्सेस लेयर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक सेवा प्रदान करती है और यह सब निरंतर मॉनिटरिंग के तहत होता है।



जयश्री सुरेश
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
jayshree@nic.in



एनआईसी आईडीसी त्रिवेन्द्रम का देवऑप्स लैब आधुनिक सरकारी अनुप्रयोग वितरण के लिए एक सुरक्षित, स्केलेबल और नीति-अनुपालन मॉडल प्रस्तुत करता है। गिट, जेनकिंस, डॉकर, कुबेर्नेट्स, कीक्लोक और ईएलके जैसे टूल्स को एकीकृत करते हुए, यह लैब संप्रभु अवसंरचना के भीतर स्वचालित विकास, परिनियोजन, निगरानी और शासन को सक्षम बनाती है, जो सुदृढ़ एवं नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं का समर्थन करती है।



विकास और एकीकरण: पाइपलाइन की आधारशिला

अनुप्रयोग के जीवनचक्र की शुरुआत गिट से होती है, जो एक वितरित वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और सहयोगात्मक विकास का आधार प्रदान करता है। केंद्रीकृत रिपॉजिटरी के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि हर बदलाव रिकॉर्ड हो, उसका ऑडिट किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस लिया जा सके—जो कि सरकारी सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

जैसे ही कोड कमिट किया जाता है, जेनकिंस इस पाइपलाइन को सक्रिय कर देता है। यह ऑटोमेशन सर्वर बिल्ड प्रक्रिया को संचालित करता है, टेस्ट केस चलाता है और अनुप्रयोग को परिनियोजन के लिए तैयार करता है—वह भी बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के। यहाँ ध्यान केवल गति पर नहीं, बल्कि स्थिरता और दोहराने योग्य प्रक्रिया पर होता है।

इसी चरण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोनारक्यूब को एकीकृत किया गया है, जो स्थिर कोड विश्लेषण के माध्यम से संभावित कमजोरियों की पहचान करता है, कोडिंग मानकों का

पालन सुनिश्चित करता है और तकनीकी ऋण को कम करता है। ऐसे सिस्टम में, जहाँ विश्वसनीयता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, यह प्रारंभिक सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

कंटेनरीकरण और परिनियोजन: सुसंगतता और संप्रभुता सुनिश्चित करना

मान्यकरण के बाद अनुप्रयोगों को डॉकर के माध्यम से कंटेनर के रूप में पैकेज किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अनुप्रयोग विभिन्न वातावरणों में एक जैसा व्यवहार करें और विकास तथा प्रोडक्शन सिस्टम के बीच किसी भी प्रकार का अंतर समाप्त हो जाए।

इन कंटेनर इमेज को आईडीसी अवसंरचना के भीतर स्थित एक निजी रजिस्ट्रि में संग्रहीत किया जाता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संवेदनशील सरकारी अनुप्रयोग पूरी तरह एनआईसी के नियंत्रित वातावरण में ही बने रहते हैं, जिससे डेटा संप्रभुता और नियंत्रित अभिगम दोनों मजबूत होते हैं।

परिनियोजन का प्रबंधन क्यूबर्नेट्स द्वारा किया जाता है, जो इस लैब का मुख्य ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। यह ऑटो-स्केलिंग, सेल्फ-हीलिंग, लोड बैलेंसिंग और संसाधनों के कुशल उपयोग जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। साथ ही, यह कार्यभारों को व्यवस्थित रूप से विभाजित और अलग-अलग वातावरणों में संचालित करने में सक्षम है, जिससे संचालन दक्षता और शासन दोनों सुनिश्चित होते हैं।

जटिल परिनियोजन को सरल बनाने के लिए हेल्म का उपयोग किया जाता है, जो एक पैकेज मैनेजर के रूप में कार्य करता है। इसकी मदद से अनुप्रयोगों को आसानी से डिप्लॉय, अपग्रेड या रोलबैक किया जा सकता है, जिससे संचालन का बोझ कम होता है और विभिन्न वातावरणों में सुसंगतता बनी रहती है।

सुरक्षा और शासन: वितरित प्रणाली में केंद्रीकृत नियंत्रण

माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर में, जहाँ विभिन्न सेवाएँ अलग-अलग डोमेन में आपस में जुड़ी होती हैं, पहचान और अभिगम प्रबंधन एक केंद्रीय विषय बन जाता है। आईडीसी लैब में यह जिम्मेदारी कीक्लोक द्वारा निभाई जाती है, जो एक केंद्रीकृत आइडेंटिटी प्रोवाइडर के रूप में कार्य करता है।

ओऑथर और ओपनआईडी कनेक्ट जैसे प्रोटोकॉल के समर्थन के साथ, कीक्लोक सिंगल साइन-ऑन, रोल-आधारित अभिगम नियंत्रण और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता एक बार प्रमाणित होकर कई सेवाओं

तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्रशासक भूमिकाओं और अनुमतियों पर सूक्ष्म स्तर का नियंत्रण बनाए रखते हैं।

इसके साथ ही अपाचे एपीआईसिक्स, एपीआई गेटवे के रूप में कार्य करता है, जो पूरे सिस्टम के लिए एकीकृत प्रवेश द्वार प्रदान करता है। यह आने वाले अनुरोधों को उपयुक्त बैकएंड सेवाओं तक निर्देशित करता है और साथ ही प्रमाणीकरण, दर-सीमा निर्धारण तथा अनुरोध सत्यापन से संबंधित नीतियों को लागू करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि माइक्रोसर्विस तक पहुँच हमेशा सुरक्षित और नियंत्रित रहे।

अवसंरचना स्तर पर रैंचर केंद्रीकृत क्लस्टर प्रबंधन प्रदान करता है। यह प्रशासकों को क्लस्टर, वर्कलोड और नीतियों का एक समग्र दृश्य देता है, जिससे वितरित वातावरण का प्रबंधन सरल होता है और शासन व्यवस्था अधिक मजबूत बनती है।

और किसी भी असामान्य स्थिति पर तेजी और सटीकता के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

यह निरंतर दृश्यता सुनिश्चित करती है कि सिस्टम केवल कार्यशील ही न रहे, बल्कि पूर्वानुमेय और उत्तरदायी भी बना रहे।

व्यवहार में कार्यप्रवाह: एक निरंतर और नियंत्रित जीवनचक्र

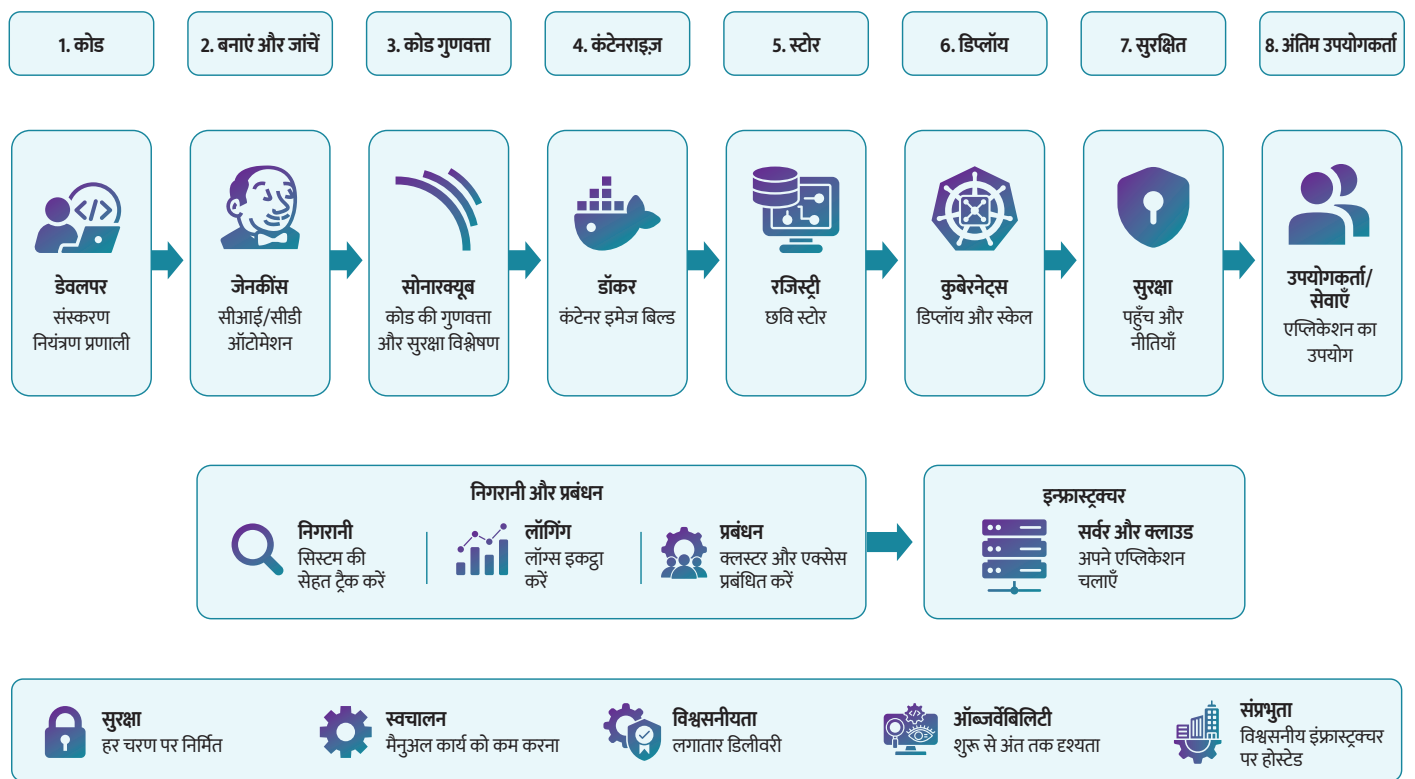
यदि इस लैब को प्रारंभ से अंत तक देखा जाए, तो यह केवल टूल्स का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवंत पाइपलाइन है।

एक डेवलपर कोड को रिपोजिटरी में कमिट करता है। इसके बाद जेनकिंस स्वचालित रूप से बिल्ड और टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करता है। सोनारक्यूब कोड की गुणवत्ता की जाँच करता है। डॉकर अनुप्रयोग को कंटेनर के रूप में पैकेज करता है, जिन्हें सुरक्षित रूप

स्केलेबल सरकारी देव-ऑप्स के लिए एक मॉडल

एनआईसी के आईडीसी तिरुवनंतपुरम् में स्थापित देव-ऑप्स लैब सरकारी तंत्र में अनुप्रयोग डिलीवरी को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट के रूप में सामने आती है। यह दर्शाती है कि किस प्रकार ओपन-सोर्स और एंटरप्राइज स्तर के टूल्स को एक समेकित आर्किटेक्चर में जोड़ा जा सकता है, जो सार्वजनिक अवसंरचना की विशेष आवश्यकताओं सुरक्षा, संप्रभुता और शासन का सम्मान करते हुए देव-ऑप्स की गति और लचीलापन भी प्रदान करता है।

प्रशिक्षण और डेमो प्लेटफॉर्म की भूमिका से आगे बढ़ते हुए, यह लैब एक और महत्वपूर्ण मूल्य प्रस्तुत करती है—



▲ चित्र 11.1 एंड-टू-एंड डेवऑप्स पाइपलाइन

ऑब्जर्वेबिलिटी: सिस्टम को गतिशील रूप में समझना

किसी भी सिस्टम की विश्वसनीयता केवल उसके डिज़ाइन पर नहीं, बल्कि उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी पर निर्भर करती है। आईडीसी देव-ऑप्स लैब में इस आवश्यकता को ईएलके स्टैक एलास्टिकसर्च, लॉगरस्टैश और किबाना के माध्यम से पूरा किया गया है।

अनुप्रयोगों, कंटेनरों और अवसंरचना से प्राप्त लॉग्स को एकत्रित कर वास्तविक समय में प्रोसेस किया जाता है। किबाना डैशबोर्ड सहज और स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हैं, जिससे प्रशासक सिस्टम की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं, त्रुटियों का पता लगा सकते हैं

से निजी रजिस्ट्री में संग्रहीत किया जाता है। क्यूबर्नेट्स परिनियोजन का प्रबंधन करता है, जबकि हेल्म रिलीज़ प्रबंधन को सरल बनाता है।

उपयोगकर्ता एपीआईसिक्स के माध्यम से सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करते हैं, जहाँ कीव्लोक द्वारा प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाता है। इसी दौरान, ईएलके स्टैक लगातार सिस्टम के व्यवहार की निगरानी करता है और रैंचर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

इस प्रक्रिया का प्रत्येक चरण अगले चरण से जुड़ा हुआ है, जिससे एक ऐसा जीवनचक्र बनता है जो पूरी तरह स्वचालित, सुरक्षित और हर स्तर पर मॉनिटर किया जा सकता है।

ऐसा मॉडल जिसे विभिन्न विभाग अपनाकर स्केलेबल, भरोसेमंद और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

ऐसे समय में, जब तकनीक से गति और जिम्मेदारी दोनों की अपेक्षा की जाती है, आईडीसी देवऑप्स लैब यह साबित करती है कि ये दोनों एक साथ संभव हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जयश्री सुरेश
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
माइक्रोसर्विसेज उत्कृष्टता केंद्र (सीईएम) प्रभाग
केंद्रीय भवन, ए-ब्लॉक, तृतीय तल, सी.एस.ई.जेड
कोच्ची, केरल - 682037
ईमेल: jayshree@nic.in, फ़ोन: 0484-46578611

एंड्रॉइड के लिए नियतात्मक सत्यापन

एंड्रॉइड अनुप्रयोगों के लिए व्यावहारिक बहु-चरणीय
निर्धारक सत्यापन तकनीक

संपादित : सी. जे. एंटनी



मोबाइल अनुप्रयोग प्रायः ऐसे परिवेश में संचालित होते हैं जो केवल आंशिक रूप से विश्वसनीय होते हैं। यद्यपि सर्वर सुरक्षित रहता है, परंतु क्लाउंट डिवाइस उपयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है, जिससे आक्रमणकारी एपीके फ़ाइल तक पहुंच प्राप्त करने के बाद अनुप्रयोग का निरीक्षण, संशोधन अथवा स्वचालन कर सकते हैं।

सामान्य सुरक्षा पद्धतियाँ स्थिर क्लाउंट पहचानकर्ताओं, जैसे डिवाइस आईडी अथवा इंस्टॉलेशन टोकन, पर निर्भर करती हैं। इनकी प्रमुख कमजोरी यह है कि ये स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं। यदि कोई आक्रमणकारी स्थिर आईडी प्राप्त कर ले, तो वह अनिश्चित काल तक क्लाउंट का प्रतिरूपण कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान समाधान प्रायः जटिल क्रियोग्राफिक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जिससे संगणनात्मक लागत बढ़ती है तथा एकीकरण कठिन हो जाता है। प्रस्तावित समाधान “निर्धारक व्यवहार” पर आधारित है। इसका अर्थ है कि सर्वर किसी एक स्थिर मान की जांच करने के बजाय समय के साथ क्लाउंट की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उसका सत्यापन करता है।

सुरक्षा जोखिम परिदृश्य और डिज़ाइन लक्ष्य

यह प्रणाली मानती है कि आक्रमणकारी अनुप्रयोग बाइनरी का निरीक्षण कर सकता है, ट्रैफिक की निगरानी कर सकता है तथा अनुरोधों को स्वचालित बना सकता है, परंतु उसे सर्वर-साइड लॉजिक तक पहुंच प्राप्त नहीं होती। उद्देश्य पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि हमले के प्रयास को अत्यधिक कठिन बनाना है।

डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम डिवाइस प्रभाव के साथ हल्का निष्पादन, यादृच्छिकता के साथ निर्धारक व्यवहार, सर्वर द्वारा सत्यापनीय स्थिति प्रगति तथा जटिल कुंजी प्रबंधन को समाप्त कर कम परिचालन लागत सुनिश्चित करना है।

क्लाउंट-साइड स्थिति और प्रगति

यह तंत्र क्लाउंट द्वारा बनाए रखी गई अनुक्रम स्थिति पर आधारित है। यह स्थिति एक साधारण पूर्णांक के रूप में प्रदर्शित होती है, जो प्रत्येक सफल इंटरैक्शन के बाद आगे बढ़ती है।



डॉ. अंबाती बुबली सागर
वैज्ञानिक - बी
sagar.ambati@nic.in



एंड्रॉइड अनुप्रयोगों के लिए विकसित यह हल्की निर्धारक सत्यापन तकनीक भारी क्रियोग्राफी पर निर्भर हुए बिना मोबाइल ए.पी.आई. सुरक्षा को सुदृढ़ बनाती है। स्थिर क्लाउंट पहचानकर्ताओं के स्थान पर यह पद्धति एप्लिकेशन के एपीके हस्ताक्षर तथा क्रमिक अनुक्रम का उपयोग करते हुए गतिशील सत्यापन मान उत्पन्न करती है। यह दृष्टिकोण स्टेटलेस सर्वर-साइड सत्यापन को सक्षम बनाता है, रीप्ले हमलों का प्रतिरोध करता है तथा जटिल कुंजी प्रबंधन से बचाव करते हुए सरल बाइट-स्तरीय परिचालनों के माध्यम से संगणनात्मक दक्षता बनाए रखता है। कम ओवरहेड, स्केलेबिलिटी तथा सहज एकीकरण इसे बड़े स्तर पर एंड्रॉइड परिनिर्माण के लिए उपयुक्त बनाते हैं।



अनुप्रयोग पुनः प्रारंभ होने पर निरंतरता बनाए रखने के लिए क्लाउंट स्थानीय संग्रहण में न्यूनतम प्रगति संकेतक सुरक्षित रखता है।

यह मान किसी पहचान, प्रमाण-पत्र अथवा संवेदनशील विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह केवल निर्धारक सत्यापन अनुक्रम में वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। संग्रहित मान का स्वयं में कोई स्वतंत्र सुरक्षा महत्व नहीं है। यदि कोई आक्रमणकारी इसे प्राप्त भी कर ले, तब भी उसे कोई परिचालन लाभ प्राप्त नहीं होता। यदि इसे हटाया, रीसेट अथवा परिवर्तित किया जाए, तो क्लाउंट और सर्वर के बीच अनुक्रम संरक्षण बाधित हो जाता है तथा बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा तर्क के सत्यापन स्वाभाविक रूप से विफल हो जाता है।

यह दृष्टिकोण संग्रहित स्थिति को हल्का और गैर-संवेदनशील बनाए रखते हुए परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करता है। अनुक्रम केवल अग्रिम दिशा में प्रगति करता है। क्लाउंट सर्वर त्रुटि प्रतिक्रियाओं के आधार पर पुनः-सिंक्रोनाइज करने का प्रयास नहीं करता, जिससे नकली अथवा रीप्ले त्रुटि स्थितियों के माध्यम से स्थिति हेरफेर को रोका जा सके।

मान व्युत्पत्ति पाइपलाइन (क्लाउंट)

स्थिर पहचानकर्ता प्रेषित करने के बजाय, क्लाउंट प्रत्येक अनुसंधान के लिए निर्धारक बहु-चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक नया सत्यापन मान तैयार करता है।

सीड जनरेशन

यह प्रक्रिया एप्लिकेशन के एपीके हस्ताक्षर हैश से प्राप्त आधार सीड से प्रारंभ होती है। इससे यह तंत्र किसी विशिष्ट बिल्ड से संबद्ध हो जाता है। सीड स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित रहता है और कभी प्रेषित नहीं किया जाता।

स्थितिगत निष्कर्षण

सीड का एक छोटा भाग वर्तमान अनुक्रम स्थिति के आधार पर चुना जाता है। जैसे-जैसे स्थिति आगे बढ़ती है, अलग-अलग भागों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रत्येक अनुसंधान में विविधता बनी रहती है और साथ ही सर्वर पर उसका पुनरुत्पादन भी संभव रहता है।

रूपांतरण और ऑफफुस्केशन

चयनित भाग पर बिट-स्तरीय रूपांतरण लागू किए जाते हैं, जैसे बिटवाइज रोटेशन तथा एक्सओआर परिचालन, ताकि उसकी प्रस्तुति बदली जा सके। संरचनात्मक अस्पष्टता बढ़ाने के लिए प्रेषित स्ट्रिंग में अतिरिक्त गैर-अर्थपूर्ण वर्ण भी जोड़े जाते हैं। सत्यापन के दौरान इन वर्णों की उपेक्षा की जाती है।

इंटीग्रेटी मार्कर

रूपांतरित भाग से एक चेकसम तैयार किया जाता है। इससे गहन सत्यापन से पहले ही भ्रष्ट अथवा छेड़छाड़ किए गए मानों को अस्वीकार करना संभव हो जाता है।

सर्वर-साइड पुनर्निर्माण

सर्वर स्टेटलेस तरीके से कार्य करता है। किसी मान को प्राप्त करने पर सर्वर डिफ्रिप्शन का प्रयास नहीं करता। इसके बजाय, वह अपेक्षित परिणाम का निर्धारक रूप से पुनर्निर्माण करता है।

- **पारसिंग:** आगत संदेश से एन्कोडेड अनुक्रम स्थिति निकाली जाती है।

- **सीड पुनर्गणना:** एप्लिकेशन हस्ताक्षर की संग्रहीत प्रति का

उपयोग करते हुए सर्वर उसी आंतरिक सीड को पुनः उत्पन्न करता है।

- **सिमुलेशन:** सर्वर अपेक्षित मान प्राप्त करने के लिए समान निष्कर्षण और रूपांतरण चरणों को लागू करता है।
- **तुलना:** प्राप्त मान की तुलना व्युत्पन्न मान से की जाती है। इसके लिए सटीक मिलान आवश्यक होता है।

स्वतंत्र सत्यापन

चूंकि सर्वर आवश्यकता अनुसार सीड की पुनर्गणना करता है, इसलिए उसे क्लाइंट सीक्रेट्स संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक अनुरोध का सत्यापन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यदि अनुरोध वैध होता है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है; अन्यथा, “गलत अनुक्रम” अथवा “अमान्य चेकसम” जैसे विशिष्ट कारण प्रकट किए बिना उसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

सुरक्षा विश्लेषण

प्रस्तावित तंत्र अपनी शक्ति असममित प्रयास सिद्धांत से प्राप्त करता है।

- **क्लाइंट के लिए:** संगणनात्मक लागत अत्यंत न्यूनतम है। इसमें सरल बाइट रूपांतरण शामिल हैं, जो मानक डिवाइसों पर तीव्र गति से निष्पादित होते हैं।
- **आक्रमणकारी के लिए:** वैध अनुरोध तैयार करने हेतु संपूर्ण आंतरिक व्युत्पत्ति पाइपलाइन की पुनरावृत्ति आवश्यक होती है। साधारण रीप्ले प्रयास प्रभावी नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक इंटरैक्शन के साथ अनुक्रम स्थिति आगे बढ़ती रहती है।
- **क्लॉनिंग के प्रति प्रतिरोध:** केवल अनुप्रयोग बाइनरी का स्वामित्व पर्याप्त नहीं है। अधिकृत सर्वर-साइड संदर्भ डेटा तथा निर्धारक स्वरिखण के अभाव में उत्पन्न मानों का सत्यापन संभव नहीं होता।
- **समान विफलता व्यवहार:** सभी सत्यापन विफलताएँ एक समान परिणाम उत्पन्न करती हैं। इससे आक्रमणकारी त्रुटि-आधारित परीक्षण के माध्यम से आंतरिक लॉजिक का अनुमान नहीं लगा सकते।

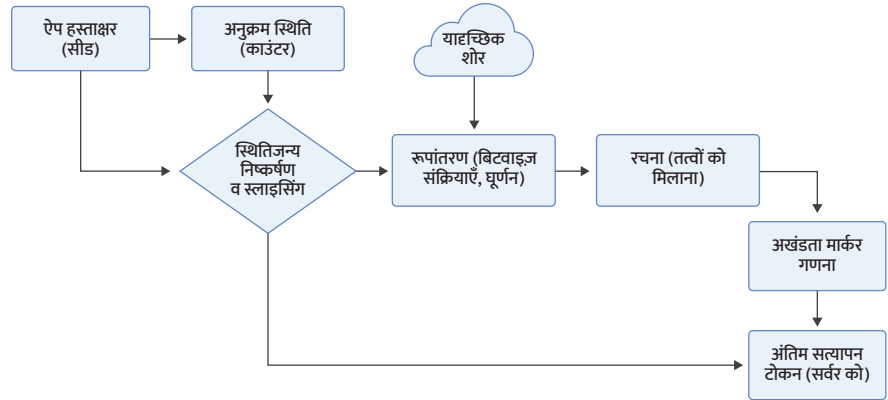
परिचालन एवं परिनियोजन लाभ

अभियांत्रिकी दृष्टिकोण से यह पद्धति बड़े स्तर के परिनियोजन के लिए व्यावहारिक है।

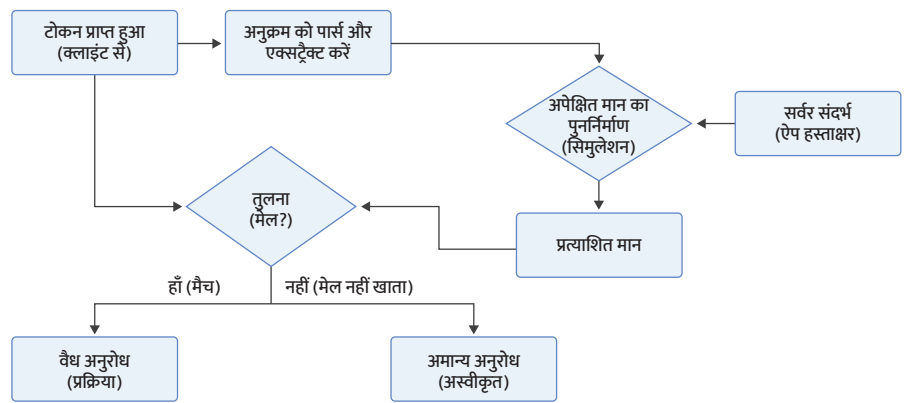
- **स्थिर प्रदर्शन:** सत्यापन लॉजिक निश्चित आकार के बाइट

▼ तालिका : प्रस्तावित निर्धारक सत्यापन तकनीक और पारंपरिक दृष्टिकोणों के बीच प्रमुख अंतर

विशेषता	स्थिर पहचानकर्ता (जैसे डिवाइस आईडी)	भारी क्रियोग्राफी (जैसे क्लाइंट प्रमाण-पत्र)	प्रस्तावित निर्धारक पद्धति
क्लाइंट पहचानकर्ता	स्थिर एवं अपरिवर्तनीय मान	निजी कुंजी	गतिशील, प्रत्येक अनुरोध के साथ प्रगति करने वाला
रीप्ले सुरक्षा	नहीं (आसानी से पुनः उपयोग संभव)	उच्च (नॉन्स/टाइमस्टैम्प के माध्यम से)	प्रगतिशील अनुक्रम-आधारित टोकनों के कारण पुनः उपयोग अत्यंत कठिन
सर्वर स्थिति	स्टेटफुल (आईडी संग्रहित करनी होती है)	स्टेटफुल (प्रमाण-पत्र/कुंजियों का प्रबंधन)	स्टेटलेस (आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण)
संगणनात्मक लागत	अत्यंत कम	उच्च (जटिल गणितीय परिचालन)	कम (बिटवाइज परिचालन)
प्रमुख कमजोरी	चोरी एवं रीप्ले के प्रति संवेदनशील	प्रबंधन और परिनियोजन में जटिल	क्लाइंट बाइनरी लॉजिक जे.एन.आई. तथा ऑबफुस्केशन के माध्यम से संरक्षित



▲ चित्र 12.1 क्लाइंट-साइड प्रक्रिया



▲ चित्र 12.2 सर्वर-साइड पुनर्निर्माण

परिचालनों पर आधारित है और प्रत्येक अनुरोध के लिए स्थिर समय ओ(1) में कार्य करता है। उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने पर भी प्रदर्शन प्रभावित नहीं होता।

- **डेटाबेस निर्भरता का अभाव:** सत्यापन के लिए प्रति-उपयोगकर्ता डेटाबेस लुकअप की आवश्यकता नहीं होती, जिससे विलंबता तथा सर्वर लोड कम होता है।
- **स्टेटलेस सत्यापन:** प्रत्येक अनुरोध का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिससे क्षैतिज स्केलिंग सरल हो जाती है।
- **ऑफलाइन तत्परता:** क्लाइंट तात्कालिक नेटवर्क पहुंच के

बिना भी अपनी प्रगति स्थिति प्रारंभ एवं आगे बढ़ा सकता है।

- **सहज एकीकरण:** यह लॉजिक विशेष अनुमतियों अथवा पृष्ठभूमि सेवाओं की आवश्यकता के बिना मानक अनुप्रयोग वर्कफ्लो में एकीकृत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह कार्य भारी क्रियोग्राफिक आदान-प्रदान पर निर्भर हुए बिना मोबाइल एपीआई सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक व्यावहारिक निर्धारक सत्यापन पद्धति प्रस्तुत करता है। एप्लिकेशन बिल्ड हस्ताक्षर तथा प्रगतिशील आंतरिक अनुक्रम के साथ सत्यापन को जोड़कर यह तकनीक प्रतिरूपण एवं स्वचालित दुरुपयोग के लिए आवश्यक प्रयास को बढ़ा देती है।

इसकी हल्की संगणना, स्टेटलेस सर्वर सत्यापन तथा सरल परिनियोजन इसे बड़े स्तर के मोबाइल परिवेशों के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जहाँ प्रदर्शन और परिचालन सरलता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

डॉ. अंबाती बुबली सागर

वैज्ञानिक - बी
एनआईसी, आंध्र प्रदेश राज्य इकाई, ए-ब्लॉक
तृतीय तल, आर एंड बी भवन, एम.जी. रोड, लक्ष्मीपेट
विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश - 520010
ईमेल: sagar.ambati@nic.in, फ़ोन: 0866-2468371

आधुनिक साइबर सुरक्षा संचालन में सीम की भूमिका

सरकारी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में खतरे की पहचान, परिचालन दृश्यता और लचीलापन सुदृढ़ करना

संपादित : मोहन दास विश्वम्

आज के तेजी से विकसित होते साइबर-खतरे के परिदृश्य में, सरकारी विभाग सार्वजनिक सेवाओं, नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों और महत्वपूर्ण अवसंरचना संचालन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता और व्यापकता के कारण सुरक्षा निगरानी और घटना-प्रतिक्रिया के लिए एक केंद्रीकृत एवं सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है।

सिक्वोरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट (सीम) इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठनों को सर्वर, एंडपॉइंट, अनुप्रयोगों और नेटवर्क उपकरणों से अभिलेखीय डेटा एकत्रित करने, सहसंबंध स्थापित करने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। कच्चे घटना डेटा को उपयोगी सुरक्षा अंतर्दृष्टि में परिवर्तित करते हुए, सीम प्रणालीगत गतिविधियों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और वास्तविक समय में असामान्य व्यवहार की पहचान करने में सहायता करता है।

घटनाओं के पारस्परिक संबंध और अभिलेखों के एकरूपीकरण के माध्यम से सीम संभावित खतरों की पहचान करता है, प्राथमिकता आधारित चेतावनियाँ देता है और समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह डिजिटल साक्ष्य जांच, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा सर्ट-इन और एनआईसी जैसे राष्ट्रीय ढाँचों के अनुरूप अनुपालन में सहायक होता है।

संवेदनशील डेटा और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने वाले सरकारी संगठनों के लिए, सीम एक आधारभूत क्षमता के रूप में कार्य करता है। यह न केवल सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करता है, बल्कि परिचालन दृश्यता को बेहतर बनाता है और उभरते साइबर जोखिमों के विरुद्ध संस्थागत लचीलापन सुनिश्चित करता है।



एस. वी. च. सुब्बा राव
उप महानिदेशक व एसआईओ
sagar.ambati@nic.in



एरिना किरन कुमार
तकनीकी निदेशक
erina.kiran@nic.in



सीम अब केवल अभिलेख प्रबंधन उपकरण नहीं रहा, बल्कि आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के लिए एक बुद्धिमान सुरक्षा आधार के रूप में विकसित हो रहा है। केंद्रीकृत दृश्यता, उन्नत विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्षमताओं के संयोजन के माध्यम से यह संस्थानों को प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा से सक्रिय सुरक्षा की ओर ले जाता है। विशेषकर जटिल सरकारी वातावरण में यह सुदृढ़, अनुपालक और भविष्य-तैयार साइबर सुरक्षा संचालन के लिए अनिवार्य बन गया है।



सीम प्रौद्योगिकी कैसे कार्य करती है

सीम समाधान एक संरचित और सतत प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करते हैं, जिसमें किसी संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश से सुरक्षा-संबंधी डेटा का संग्रहण, प्रसंस्करण और विश्लेषण किया जाता है। इसमें प्रणाली अभिलेख, उपयोगकर्ता गतिविधियाँ, नेटवर्क यातायात, अंतिम उपकरण, अनुप्रयोग और सर्वर शामिल होते हैं, जिससे सुरक्षा घटनाओं की व्यापक दृश्यता प्राप्त होती है।

सीम प्रणाली के कार्य को निम्नलिखित प्रमुख चरणों के माध्यम से समझा जा सकता है:

- **डेटा संग्रहण:** सीम प्लेटफॉर्म विभिन्न स्रोतों से अभिलेख और घटना डेटा एकत्रित करते हैं, जैसे अग्नि-प्राचीर (फायरवॉल), अनधिकृत प्रवेश पहचान प्रणालियाँ, सर्वर, डेटाबेस और मेघ परिवेश, जिससे संपूर्ण अवसंरचना पर व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है।
- **डेटा मानकीकरण और समेकन:** एकत्रित डेटा को एक समान प्रारूप में ढाला जाता है, जिससे विभिन्न प्रणालियों से प्राप्त घटनाओं

की सामूहिक तुलना और विश्लेषण संभव हो सके।

- **घटना सहसंबंध:** सीम पूर्व-निर्धारित नियमों, सांख्यिकीय प्रतिमानों और खतरा-सूचना के आधार पर संबंधित घटनाओं को जोड़ता है, जिससे ऐसे पैटर्न की पहचान होती है जो दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का संकेत दे सकते हैं।

- **खतरा पहचान और चेतावनी:** सहसंबंध और विश्लेषण के आधार पर प्रणाली असामान्यताओं की पहचान करती है और प्राथमिकता-आधारित चेतावनियाँ उत्पन्न करती है, जिससे सुरक्षा दल उच्च-जोखिम वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

- **प्रतिक्रिया और जाँच:** सीम घटना-प्रतिक्रिया में संदर्भित जानकारी प्रदान कर सहायता करता है, जिससे जाँच, नियंत्रण और सुधार की प्रक्रिया तेज और प्रभावी होती है। उन्नत प्रणालियाँ स्वचालित प्रतिक्रिया भी आरंभ कर सकती हैं।

यह संरचित कार्यप्रवाह सीम को विशाल मात्रा में कच्चे डेटा को उपयोगी सुरक्षा बुद्धिमत्ता में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है, जिससे संगठन समय रहते खतरों की पहचान कर सकें, प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकें और निरंतर सुरक्षा निगरानी बनाए रख सकें।

सीम के मुख्य घटक

एक सीम प्रणाली कई एकीकृत घटकों पर आधारित होती है, जो मिलकर सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में पूर्ण दृश्यता, पहचान और प्रतिक्रिया की क्षमता प्रदान करते हैं। ये घटक बड़े पैमाने पर डेटा संसाधित करने, खतरों की पहचान करने और सुरक्षा संचालन को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं:

- **अभिलेख डेटा प्रबंधन:** यह सीम की आधारशिला है, जो विभिन्न स्रोतों से अभिलेख डेटा का संग्रहण, भंडारण और प्रबंधन करता है। यह डेटा की अखंडता, मानकीकरण और विश्लेषण, लेखा-परीक्षण तथा अनुपालन के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

- **सुरक्षा घटना प्रबंधन (एसआईएम):** यह वास्तविक समय में सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण पर केंद्रित होता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जीवंत डेटा के सहसंबंध के माध्यम से यह संदिग्ध गतिविधियों की त्वरित पहचान और तत्काल चेतावनी उत्पन्न करता है।

- **सुरक्षा सूचना प्रबंधन (एसआईएम):** यह ऐतिहासिक डेटा के भंडारण और विश्लेषण का कार्य करता है, जिससे घटना जाँच, प्रवृत्ति विश्लेषण और अनुपालन प्रतिवेदन को समर्थन मिलता है।

- **घटना सहसंबंध और विश्लेषण:** यह विभिन्न प्रणालियों से प्राप्त डेटा को नियमों, सांख्यिकीय प्रतिमानों और खतरा-सूचना के आधार पर संयोजित करता है, जिससे जटिल या छिपे हुए खतरों की पहचान की जा सके।

• **उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण:** यह मशीन अधिगम के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और प्रणालियों के सामान्य व्यवहार का आधार निर्धारित करता है और असामान्यताओं, जैसे आंतरिक खतरों या समझौता किए गए खातों, की पहचान में सहायता करता है।

• **खतरा-सूचना एकीकरण:** यह बाहरी खतरा स्रोतों को शामिल कर पहचान क्षमता को सुदृढ़ करता है, जिससे ज्ञात हमलों के पैटर्न और उभरते जोखिमों की बेहतर पहचान हो सके।

• **चेतावनी और घटना-प्रतिक्रिया:** यह पहचाने गए खतरों के आधार पर प्राथमिकता-आधारित चेतावनियाँ उत्पन्न करता है और संरचित प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं—जॉच, नियंत्रण और सुधार—को समर्थन प्रदान करता है। उन्नत प्रणालियाँ स्वचालित प्रतिक्रिया भी सक्षम कर सकती हैं।

• **प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षण और अनुपालन:** यह डैशबोर्ड, प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षण अभिलेख प्रदान करता है, जो नियामकीय अनुपालन के लिए आवश्यक होते हैं, साथ ही सुरक्षा स्थिति और परिचालन प्रवृत्तियों की समझ भी देते हैं।

सीम का एआई आधारित विकास

जैसे-जैसे साइबर खतरे आकार और जटिलता में बढ़ रहे हैं, पारंपरिक सीम प्रणालियाँ अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अधिगम से संचालित बुद्धिमान एवं अनुकूलनशील मंचों में विकसित हो रही हैं। यह परिवर्तन संगठनों को केवल प्रतिक्रियात्मक निगरानी से आगे बढ़कर पूर्वानुमान आधारित और स्वचालित सुरक्षा संचालन की दिशा में सक्षम बना रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीम समाधान वास्तविक समय और ऐतिहासिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण कर पैटर्न, असामान्यताओं और उभरते आक्रमण तरीकों की अधिक सटीक पहचान करते हैं। निरंतर सीखने की क्षमता के कारण ये प्रणालियाँ सूक्ष्म विचलनों को भी पहचान सकती हैं, जो आंतरिक खतरों, समझौता किए गए खातों या अज्ञात हमलों का संकेत हो सकते हैं।

स्वचालन आधुनिक सीम क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समन्वय ढाँचों के साथ एकीकृत होकर, सीम प्रणालियाँ पूर्व-निर्धारित प्रतिक्रियाएँ आरंभ कर सकती हैं, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और सुरक्षा घटनाओं को शीघ्र नियंत्रित किया जा सकता है। इससे प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है और सुरक्षा दलों पर कार्यभार भी कम होता है।

इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चेतावनियों की प्राथमिकता निर्धारण और अनावश्यक संकेतों को कम करने में भी सहायक होती है। संदर्भ-आधारित विश्लेषण के माध्यम से यह गलत चेतावनियों को फ़िल्टर करती है, जिससे सुरक्षा विश्लेषक उच्च-प्रभाव वाले खतरों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है।

सीम का विकास उभरते साइबर सुरक्षा ढाँचों और संरचनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। मेघ परिवेश, शून्य-विश्वास मॉडल और विस्तारित पहचान एवं प्रतिक्रिया मंचों के साथ एकीकरण से वितरित और मिश्रित अवसंरचनाओं में दृश्यता का दायरा बढ़ रहा है। साथ ही, डेटा गोपनीयता और नियामकीय अनुपालन पर बढ़ते जोर ने शासन और लेखा-परीक्षण की तैयारी में सीम की भूमिका को और सुदृढ़ किया है।

भविष्य में सीम और अधिक विस्तार योग्य, स्वचालित और संदर्भ-सजग प्रणाली के रूप में विकसित होगा—जो केवल निगरानी उपकरण नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय बुद्धिमत्ता स्तर बनेगा। यह विकास विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में संगठनों को लचीलापन बढ़ाने, सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और उन्नत साइबर खतरों से आगे रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सीम कार्यान्वयन के लिए श्रेष्ठ अभ्यास

प्रभावी सीम कार्यान्वयन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएँ और मानव संसाधन संगठन के सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप हों। एक सुव्यवस्थित सीम प्रणाली न केवल खतरे की पहचान को बेहतर बनाती है, बल्कि दीर्घकालिक दक्षता और विस्तार क्षमता भी सुनिश्चित करती है।

• **स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें:** सीम के उपयोग हेतु स्पष्ट लक्ष्य तय करें, जैसे खतरा पहचान, अनुपालन या घटना-प्रतिक्रिया। इससे प्राथमिकताएँ तय करने और प्रणाली को सही ढंग से विन्यस्त करने में सहायता मिलती है।

• **समग्र डेटा एकीकरण सुनिश्चित करें:** अग्नि-प्राचीर, अंतिम उपकरण, पहचान प्रणालियाँ, अनुप्रयोग और मेघ परिवेश से अभिलेखों को एकीकृत करें, ताकि व्यापक दृश्यता और सटीक पहचान संभव हो।

• **महत्वपूर्ण स्रोतों को प्राथमिकता दें:** प्रारंभ में उच्च-मूल्य प्रणालियों जैसे सक्रिय निर्देशिका, नेटवर्क उपकरण और मेघ मंचों पर ध्यान केंद्रित करें।

• **निरंतर निगरानी और सुधार सक्षम करें:** सहसंबंध नियमों, डैशबोर्ड और चेतावनियों की नियमित समीक्षा और अद्यतन करें, ताकि बदलते खतरे के अनुरूप प्रणाली प्रभावी बनी रहे।

• **स्वचालन और खतरा-सूचना का उपयोग करें:** स्वचालन और समन्वय क्षमताओं को शामिल कर प्रतिक्रिया प्रक्रिया को सरल बनाएं तथा खतरा-सूचना स्रोतों को अद्यतन रखें।

• **दल की क्षमता और प्रशिक्षण सुदृढ़ करें:** सुरक्षा संचालन दल को आवश्यक कौशल प्रदान करें, जिससे वे चेतावनियों को समझ सकें, घटनाओं की जांच कर सकें और प्रणाली का अनुकूलन कर सकें।

• **विभागीय सहयोग को बढ़ावा दें:** सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और अनुपालन दलों के बीच समन्वय स्थापित करें, ताकि संचार और प्राथमिकताओं में सामंजस्य बना रहे।

• **अनुपालन और लेखा-परीक्षण की तैयारी सुनिश्चित करें:** अभिलेख संरक्षण, प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षण मार्ग सुनिश्चित कर नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रणाली को तैयार रखें।

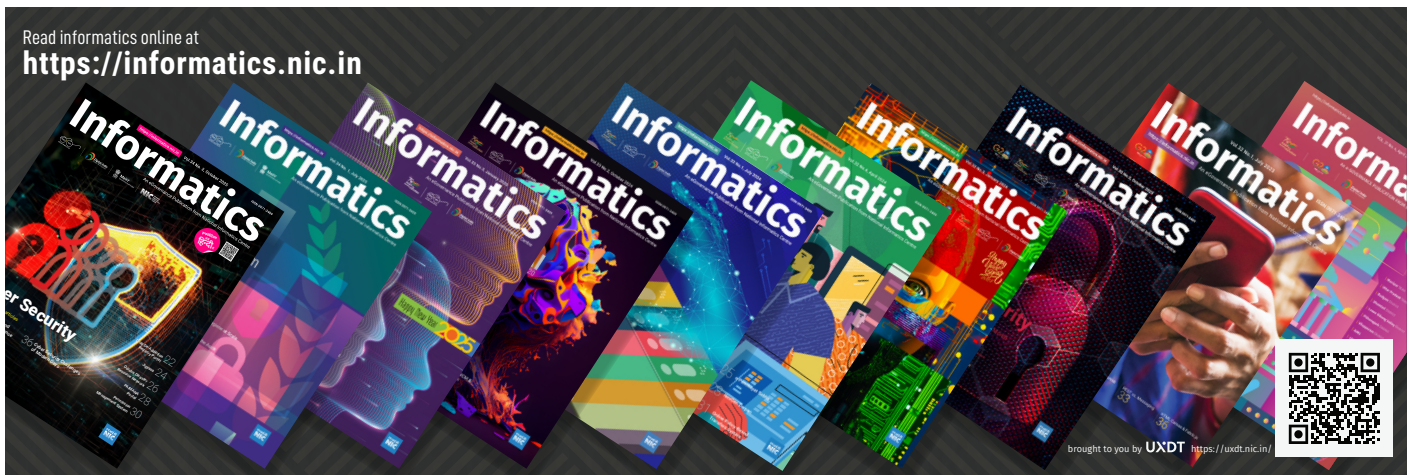
निष्कर्ष

आज के गतिशील खतरे के परिदृश्य में सीम साइबर सुरक्षा का एक प्रमुख घटक बन चुका है, जो एकीकृत दृश्यता, वास्तविक समय पहचान और उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेशन इसे और अधिक बुद्धिमान और अनुकूलनशील बना रहा है, जिससे तेज़ खतरा पहचान, बेहतर चेतावनी प्राथमिकता और प्रभावी घटना-प्रतिक्रिया संभव हो रही है।

जैसे-जैसे साइबर खतरे विकसित होते रहेंगे, सीम संगठनात्मक लचीलापन बढ़ाने, अनुपालन सुनिश्चित करने और सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वचालन और पूर्वानुमान आधारित क्षमताओं की दिशा में इसका निरंतर विकास सुरक्षा संचालन को अधिक प्रभावी और संगठन के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप बनाएगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

एस. वी. च. सुब्बा राव
उप महानिदेशक एवं एसआईओ
एनआईसी आंध्र प्रदेश राज्य केंद्र
तृतीय तल, आर एंड बी बिल्डिंग, एमजी रोड
विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश - 520010
ईमेल: sio-ap@nic.in, फ़ोन: 0866-2468341



ऐपस्केप

मोबाइल तकनीक सरकारों के लिए अपने नागरिकों की सेवा करने का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी है। इसने संचार और सहयोग के लिए पारंपरिक भौतिक नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह कहीं अधिक किफायती और सुलभ भी है, जिससे बेहतर नागरिक-सरकार संपर्क के माध्यम से राष्ट्र को मजबूती मिलती है। इस संपर्क को और मजबूत करने के लिए, एनआईसी ने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 730 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स का एक संग्रह तैयार किया है। ऐपस्केप के इस अंक में हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स को शामिल किया गया है। ये ऐप्स प्रशासन, विकास, वित्त, सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।



एमसैनिक

एमसैनिक ऐप, जिसे एम-सैनिक कल्याण के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री द्वारा सैनिक कल्याण निदेशालय, मध्य प्रदेश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसे एनआईसी एमपी स्टेट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप और इसके साथ उपलब्ध सैनिक कल्याण पोर्टल कई उपयोगी सुविधाएँ प्रदान करते हैं:

मुख्य विशेषताएँ:

- उपयोगकर्ता सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए विस्तृत प्रोफ़ाइल बना सकते हैं।
- विभिन्न उपलब्ध कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
- ऐप में जानकारी के प्रबंधन और संगठन को सुगम बनाता है।
- उपयोगकर्ता अपनी पात्रता की जाँच कर सकते हैं।
- विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक फॉर्म और पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- ऐप के माध्यम से आवेदन जमा और स्वीकृत किए जा सकते हैं।
- आवेदन या योजनाओं से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होती है।

यह ऐप पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें विभिन्न सेवाओं और योजनाओं तक आसान, सुलभ और सुव्यवस्थित पहुँच प्रदान करता है।

👤 विजय विश्वकर्मा (sio-mp@nic.in)

एनआईसी ऐप्स से संबंधित प्रश्नों के लिए कृपया संपर्क करें

एंड्रॉइड
संदीप सूद
ईमेल: sood.sandeep@nic.in | फोन: 0177-2880890

आईओएस
रॉय जोसेफ
ईमेल: roy.joseph@nic.in | फोन: 9447722682

स्कूल सुरक्षा ऐप

यह मोबाइल ऐप स्कूलों की सुरक्षा और आपदा से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली समाधान है। राज्य भर के स्कूलों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया यह ऐप आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन की गई कई सुविधाओं से लैस है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **डेटा संग्रहण और प्रविष्टि:** स्कूल आपातकालीन निकास, अग्नि सुरक्षा उपकरण, निकासी योजना और बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
- **स्वाचालित आपदा प्रबंधन योजना निर्माण:** प्रदान किए गए डेटा के आधार पर ऐप प्रत्येक स्कूल के लिए विस्तृत और अनुकूलित डीएमपी तैयार करता है, जिससे समय बचत और सटीकता सुनिश्चित होती है।
- **प्रगति निगरानी डैशबोर्ड:** एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य के सभी स्कूलों में डीएमपी की प्रगति और अपडेट को रियल-टाइम में ट्रैक किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है।
- **उपयोगकर्ता पहुंच:** ऐप का उपयोग स्कूल प्रशासकों और संबंधित अधिकारियों को दिया जाता है, जिससे वे सुरक्षा उपायों की समीक्षा और अपडेट आसानी से कर सकते हैं।
- **केंद्रीकृत डेटा भंडारण:** ऐप सभी स्कूलों के सुरक्षा संबंधी डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है, जिससे पूरे राज्य में एकसमान आपदा तैयारी सुनिश्चित होती है।

इन विशेषताओं को एकीकृत करके, ऐप न केवल स्कूलों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देता है बल्कि संस्थानों को अच्छी तरह से तैयार रहने के लिए सशक्त भी बनाता है।

👤 अजय कुमार चहल (sio-hp@nic.in)

अतिथि केरल

अतिथि केरल एक बहुभाषी एंड्रॉइड एप्लिकेशन है जिसे केरल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याण को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल 2023 में एक वेब पोर्टल के साथ लॉन्च किया गया यह ऐप, राज्य के श्रम विभाग की पहल के अंतर्गत श्रमिकों, नियोक्ताओं और ठेकेदारों के सुगम पंजीकरण को सुनिश्चित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **श्रमिक एवं नियोक्ता पंजीकरण:** प्रवासी श्रमिक, ठेकेदार और नियोक्ता ओटीपी आधारित प्रमाणिकरण के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत, शैक्षणिक, कौशल और रोजगार से संबंधित आवश्यक जानकारी अपलोड की जाती है।
- **विशिष्ट पहचान:** प्रत्येक पंजीकृत प्रवासी श्रमिक को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वे विभिन्न राज्य कल्याण योजनाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- **बहुभाषी इंटरफेस:** यह ऐप कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे केरल के प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयोग आसान हो जाता है।
- **सूचनाएं एवं अपडेट:** श्रमिकों को ऐप के नोटिफिकेशन मॉड्यूल के माध्यम से कल्याण योजनाओं से संबंधित समय-समय पर जानकारी और अपडेट प्राप्त होते रहते हैं।

अतिथि केरल प्रवासी श्रमिकों के डेटा को केंद्रीकृत कर कल्याण सेवाओं को सरल बनाता है, डुप्लिकेशन कम करता है और सरकारी योजनाओं तक पहुंच बेहतर करता है। यूनिक आईडी और आधिकारिक पंजीकरण से सुरक्षा व जवाबदेही बढ़ती है। यह ऐप ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए पंजीकरण व प्रबंधन को भी आसान बनाता है।

👤 डॉ. सुचित्रा प्यारे लाल (sio-ker@nic.in)

पीएमएमवीवाई सॉफ्ट

पीएमएमवीवाई सॉफ्ट ऐप को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विकसित किया गया है। यह भारत सरकार की मातृत्व लाभ योजना है। यह ऐप लाभार्थियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे मातृत्व लाभों का वितरण अधिक कुशल और सुलभ बनता है।

- **लाभार्थी पंजीकरण:** पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पंजीकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एस) और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा आधार और मातृत्व कार्ड जैसे दस्तावेजों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **आवेदन ट्रैकिंग:** आवेदन की स्थिति और भुगतान वितरण की रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे पारदर्शिता होती है।
- **भूमिका-आधारित उपयोगकर्ता पहुंच:** ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एस, आशा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और सहायक नर्स मिडवाइफ के लिए अलग-अलग लॉगिन सुविधा, जिससे प्रबंधन आसान होता है।
- **सुरक्षित डेटा प्रबंधन:** उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक के माध्यम से उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- **मल्टी-यूजर सपोर्ट:** विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित कर लाभार्थी प्रबंधन को प्रभावी बनाता है।
- **बहुभाषी समर्थन:** कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, जिससे अधिक लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होती है।

इस योजना के तहत पहले बच्चे के लिए ₹5,000 और दूसरी बेटी के लिए ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह ऐप मातृ कल्याण सेवाओं की उपलब्धता, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाता है।

👤 टिमोथी डीखार (hog-womenchild@nic.in)

राजस्थान सोशल पेंशन

राजस्थान सोशल पेंशन ऐप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एस.जेड.ई.डी), राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन और बुनियादी आजीविका का सहारा मिल सके।

इन योजनाओं की आधारशिला भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और अन्य आवश्यक परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। इसी दिशा में भारत सरकार ने वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की शुरुआत की, जिससे गरीब और वंचित वर्गों के समर्थन के लिए एक संगठित ढांचा तैयार किया गया।

यह ऐप पेंशन सेवाओं में सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से लाभार्थी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और भुगतान से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। सेवाओं के डिजिटलीकरण के द्वारा यह ऐप सुनिश्चित करता है कि लाभ समय पर और बिना किसी पेशानी के सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

👤 डॉ. पी. गायत्री (sioraj@nic.in)

थिरुकोइल

थिरुकोइल ऐप एक अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो तमिलनाडु के मंदिरों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इसमें 48 प्रमुख श्रेणी के मंदिर शामिल हैं और समय के साथ इसमें और मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, जिससे यह एक समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर का विस्तृत संग्रह बनता जा रहा है।

यह ऐप इतिहास और तकनीक का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। इसमें थला वरलारु के माध्यम से 6वीं शताब्दी ईस्वी से जुड़े मंदिरों का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है, साथ ही मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियाँ, शिल्पकला और चित्रों के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा, मंदिर के समय, पूजा-विधि और दैनिक एवं विशेष आयोजनों का अद्यतन कैलेंडर भी प्रदान किया जाता है।

- **वर्चुअल टूर:** श्रद्धालु मंदिर जाने से पहले डिजिटल रूप से दर्शन और वातावरण का अनुभव कर सकते हैं।
- **धार्मिक ग्रंथ:** थिरुमुरै और नालाथिर दिव्य ग्रंथम जैसे पवित्र ग्रंथ तमिल भाषा में पढ़ने और सुनने (ऑडियो) के लिए उपलब्ध हैं।
- **लाइव दर्शन:** मंदिरों के लाइव दर्शन की सुविधा।
- **रूट मैप और नजदीकी मंदिर सुझाव:** यात्रा को आसान बनाने के लिए मार्गदर्शन और आसपास के मंदिरों की जानकारी।
- **संपर्क विवरण:** मंदिर प्रशासन से संपर्क हेतु आवश्यक जानकारी।

इन सभी सुविधाओं के माध्यम से, थिरुकोइल ऐप श्रद्धालुओं को एक सहज, समृद्ध और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, चाहे वे कहीं भी हों।

👤 श्री कमलकन्नन एम. (sio.tn@nic.in)

सेवा सुविधा

सेवा सुविधा छत्तीसगढ़ के सी.एस.एम.सी.एल रिटेल शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विकसित एक आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन है। यह ऐप कर्मचारी प्रबंधन को सरल बनाने, संचार को बेहतर करने और आवश्यक कार्यस्थल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

- मुख्य विशेषताएं:
- **वेतन प्रबंधन:** कर्मचारी अपनी मासिक वेतन संबंधी पूरी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें आय, कटौतियाँ, कुल वेतन (ग्रॉस पे) और शुद्ध वेतन (नेट पे) शामिल हैं।
- **अवकाश आवेदन:** उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के लिए सीधे ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे स्वीकृति प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है।
- **दुकान शिकायत एवं फीडबैक प्रणाली:** कर्मचारी दुकान से संबंधित समस्याओं को देख सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और CSMCL प्रबंधन के साथ फीडबैक या महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं, जिससे जवाबदेही और कार्यकुशलता में सुधार होता है।
- **सी.एस.एम.सी.एल सूचनाएं:** कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अपडेट और घोषणाएं रियल-टाइम में प्राप्त होती हैं।

अपनी सुरक्षित प्रणाली और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस के साथ, सेवा सुविधा ऐप गोपनीयता, सुविधा और प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है, जिससे यह सी.एस.एम.सी.एल. रिटेल आउटलेट्स के कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है।

👤 तेज नारायण सिंह (sio-cg@nic.in)

भारत और तंजानिया ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर

भारत और तंजानिया ने 29-30 अप्रैल 2026 को दार-एस-सलाम में आयोजित भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के पाँचवें सत्र के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और प्रौद्योगिकी-आधारित सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। बैठक में दोनों देशों ने डिजिटल शासन, रियल-टाइम भुगतान प्रणालियों, डिजिटल पहचान सेवाओं तथा ई-कॉमर्स ढांचे में सहयोग विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा तंजानिया के विदेश एवं पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्रालय के स्थायी सचिव सैमुअल विलियम शेलुकिंडो ने की। दोनों पक्षों ने डिजिटल परिवर्तन को आर्थिक सहयोग और सार्वजनिक सेवा वितरण का महत्वपूर्ण आधार बताया।

चर्चा के दौरान भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, विशेष रूप से 'इंडिया स्टैक', को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। दोनों देशों ने रियल-टाइम भुगतान प्रणाली, डिजिटल पहचान सेवाओं तथा डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म के उपयोग और संभावित सहयोग पर विचार-विमर्श किया। ई-कॉमर्स विनियमन तथा डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि डिजिटल अवसंरचना सुशासन, सेवा वितरण तथा प्रशासनिक दक्षता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोनों पक्षों ने तकनीक-सक्षम सार्वजनिक प्रशासन तथा डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली को भविष्य के सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना।

स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा हुई, जिससे तंजानिया के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाई जा सके। शिक्षा क्षेत्र में आईआईटी मद्रास जांजीबार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के उभरते क्षेत्रीय केंद्र के रूप में रेखांकित किया गया।

बैठक के दौरान दोनों देशों ने अवसंरचना, ऊर्जा, कृषि और जल प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में



भी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत की विकास साझेदारी के अंतर्गत तंजानिया में जल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

बैठक के समापन पर दोनों पक्षों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवाचार और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासनिक सहयोग को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति का अगला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत ने डिजिटल बाल स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने हेतु आर.बी.एस.के 2.0 दिशानिर्देश जारी किए

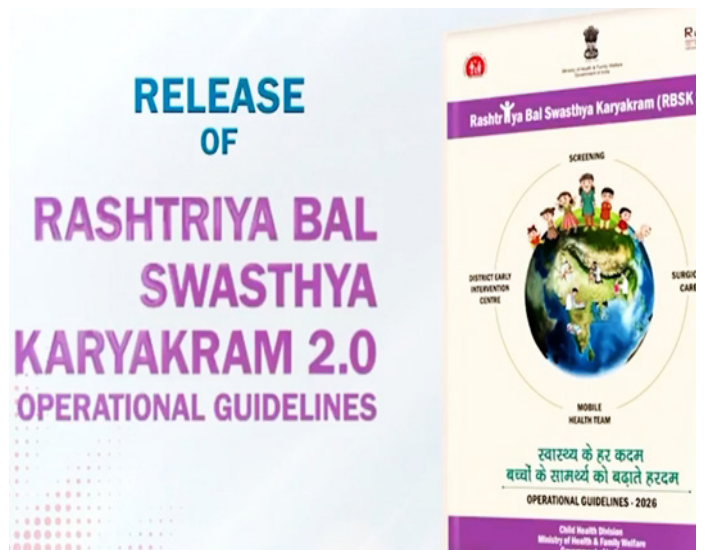
भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के) 2.0 के अद्यतन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों, रियल-टाइम निगरानी तथा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण पर विशेष बल दिया गया है।

संशोधित ढांचा कार्यक्रम के 4डी दृष्टिकोण—जन्म दोष, रोग, कमी तथा विकासात्मक विलंब—को आगे बढ़ाते हुए गैर-संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य तथा बच्चों और किशोरों में व्यवहार संबंधी समस्याओं को भी शामिल करता है।

आर.बी.एस.के 2.0 के अंतर्गत मोबाइल स्वास्थ्य दल आंगनवाड़ी केन्द्रों और विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच जारी रखेंगे। साथ ही, संरचित डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र के माध्यम से रेफरल प्रणाली और उपचार की निरंतरता को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

नए दिशानिर्देशों में डिजिटल हेल्थ कार्ड, रियल-टाइम डेटा सिस्टम तथा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल किए गए हैं, जिससे कार्यक्रम की निगरानी, पारदर्शिता तथा डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। यह ढांचा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास क्षेत्रों के बीच समन्वय को भी प्रोत्साहित करता है, ताकि बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को मजबूत किया जा सके।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो



भारत ने आपदा चेतावनी हेतु राष्ट्रव्यापी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया



भारत ने आपदाओं और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी आपात स्थितियों के दौरान मोबाइल फोन पर रियल-टाइम, भू-स्थान आधारित चेतावनी संदेश भेजने के लिए राष्ट्रव्यापी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस.) लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना तथा नागरिकों के साथ आपातकालीन संचार को अधिक प्रभावी करना है।

इस प्रणाली का शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है।

पारंपरिक एसएमएस अलर्ट के विपरीत, सीबीएस. प्रणाली निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद सभी मोबाइल उपकरणों पर तुरंत चेतावनी संदेश प्रसारित कर सकती है, यहां तक कि नेटवर्क व्यस्त होने

की स्थिति में भी। यह प्लेटफॉर्म 2जी से 5जी तक की मोबाइल प्रौद्योगिकियों को समर्थन देता है तथा बहुभाषीय और स्थान-विशिष्ट चेतावनी संदेशों के साथ उच्च-प्राथमिकता सूचनाएं जारी करने में सक्षम है।

इस प्रणाली को सीएपी-आधारित 'सचेत' आपदा चेतावनी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन चेतावनियों का त्वरित और मानकीकृत प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। लॉन्च के दौरान आयोजित राष्ट्रव्यापी परीक्षण ने विभिन्न क्षेत्रों और दूरसंचार नेटवर्कों में एक साथ उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया।

अधिकारियों के अनुसार, यह पहल प्रौद्योगिकी-आधारित आपदा तैयारी तथा देशभर में सार्वजनिक सुरक्षा संचार को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

यूपीआई ने पूरे किए 10 वर्ष, भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र हुआ और मजबूत

भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर चुका है और आज यह देश के डिजिटल भुगतान तंत्र तथा वित्तीय समावेशन का प्रमुख आधार बन गया है। अप्रैल 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नियामकीय पर्यवेक्षण में शुरू की गई यह प्रणाली पिछले एक दशक में लेनदेन संख्या और मूल्य दोनों में तेजी से विस्तारित हुई है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यूपीआई के माध्यम से 24,162 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए, जिनका कुल मूल्य ₹314 लाख करोड़ से अधिक रहा। 21 बैंकों से शुरू हुआ यह नेटवर्क अब 703 सहभागी बैंकों तक विस्तारित हो चुका है।

अगस्त 2025 में यूपीआई ने पहली बार एक महीने में 2,001 करोड़ लेनदेन का आंकड़ा पार किया, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 2,163 करोड़ तक पहुंच गया। कुल लेनदेन संख्या में लगभग 63 प्रतिशत हिस्सेदारी व्यक्ति-से-व्यापारी (पी.2.एम.) भुगतानों की रही, जो दैनिक खुदरा भुगतानों में इसके व्यापक उपयोग को दर्शाती है।

यूपीआई को वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण पहचान मिली है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक रियल-टाइम भुगतान लेनदेन में मात्रा के आधार पर इसकी हिस्सेदारी लगभग 49 प्रतिशत रही। यूपीआई-आधारित भुगतान अब सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरीशस सहित कई देशों में स्वीकार किए जा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यूपीआई के अगले चरण में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों तक पहुंच बढ़ाने, प्रणाली की मजबूती को और बेहतर बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान साझेदारियों को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।



स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक मिलियन साइबर सखियों को तैयार करने के लिए “ई-सेफहर” पहल शुरू की

भारत ने “ई-सेफहर” नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 2029 तक ग्रामीण भारत की एक मिलियन महिलाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाना है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सी-डैक हैदराबाद द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से लागू की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के “सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता” कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित यह पहल डिजिटल मंचों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन, आजीविका और सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने वाली ग्रामीण महिलाओं में साइबर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करेगी।

कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश और ओडिशा में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से होगी, जिसके बाद इसे पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा। सी-डैक हैदराबाद बहुभाषी प्रशिक्षण सामग्री विकसित करेगा, जबकि रिलायंस फाउंडेशन सामुदायिक आधारित प्रशिक्षण मॉडल के जरिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगा।

एस. कृष्णन ने कहा कि यह पहल दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा कौशल प्रदान कर “साइबर सुरक्षित भारत” के दृष्टिकोण को मजबूत करेगी।

ईशा अंबानी ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने और डिजिटल तकनीकों का आत्मविश्वास के साथ उपयोग करने में मदद करेगा, जिससे वे अपने जीवन और आजीविका को बेहतर बना सकें।



यह पहल स्थानीय भाषाओं की सामग्री, ऑडियो-विजुअल मॉड्यूल और मिश्रित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से साइबर जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और ग्रामीण समुदायों में सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करेगी।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत पाली और विरासत भाषाओं के संरक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से विरासत और अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत कर रहा है, जिसमें प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की प्राचीन भाषा पाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया “भाषिणी” पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में “पाली भाषा संरक्षण और डिजिटल कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकास” विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन बौद्ध अध्ययन के उन्नत अध्ययन केंद्र के सहयोग से किया गया।

इस पहल का उद्देश्य पाली भाषा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल भाषा उपकरण विकसित करना है। सीमित डिजिटल डाटा और भाषाई संसाधनों के कारण पाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में “कम संसाधन वाली भाषा” माना जाता है। कार्यशाला में डाटा सेट निर्माण, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, ऑडियो संग्रह, भाषाई सत्यापन और विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी पर चर्चा हुई।

अमिताभ नाग ने भारतीय भाषाओं में ज्ञान प्रणालियों और डिजिटल सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले डाटा सेट विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और भाषा समुदायों के सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

कार्यशाला में “भाषिणी” के कई भाषा प्रौद्योगिकी उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया, जिनमें पाठ अनुवाद के लिए “अनुवाद”, वाणी आधारित अनुवाद के लिए “वाणी अनुवाद”, दस्तावेज अनुवाद के लिए “लेखा अनुवाद” और बहुभाषी वीडियो रूपांतरण के लिए “चित्र अनुवाद” शामिल थे। “भाषिणी” मोबाइल एप्लिकेशन और “भाषा दान” प्लेटफॉर्म का भी प्रदर्शन किया गया, जो रियल-टाइम अनुवाद और समुदाय आधारित भाषा डाटा योगदान को समर्थन प्रदान करते हैं।



अधिकारियों ने कहा कि यह पहल भारत में समावेशी बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने तथा डिजिटल नवाचार के माध्यम से सांस्कृतिक और विरासत भाषाओं के संरक्षण के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत ने डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए “संपन्न” प्लेटफॉर्म का विस्तार किया



भारत ने अपने प्रमुख डिजिटल पेंशन प्रबंधन प्लेटफॉर्म “संपन्न” (पेंशन लेखांकन एवं प्रबंधन प्रणाली) का विस्तार करते हुए गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट प्राधिकरण को इससे जोड़ा है, ताकि पेंशन और वित्तीय संचालन को डिजिटल रूप से संचालित किया जा सके।

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विकसित और दूरसंचार विभाग के नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स कार्यालय द्वारा संचालित “संपन्न” पेंशन प्रक्रिया के पूरे जीवनचक्र को डिजिटलाइज करता है — आवेदन, स्वीकृति, लेखांकन और भुगतान तक।

यह क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन शिकायत निवारण और सिंगल-विंडो इंटरफेस जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे कागजी कार्यवाही, देरी और प्रशासनिक जटिलताओं में कमी आती है।

अधिकारियों ने कहा कि नए सार्वजनिक संस्थानों द्वारा “संपन्न” को अपनाना इसकी विस्तार क्षमता और विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में व्यापक एकीकरण की संभावनाओं को दर्शाता है। वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म प्रति माह लगभग ₹1,650 करोड़ की पेंशन वितरित कर रहा है और अब तक करीब ₹72,000 करोड़ का भुगतान कर चुका है।

सरकार ने डाक विभाग and दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त पेंशनभोगियों के लिए “संपन्न” के व्यापक उपयोग की संभावनाएँ तलाशने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित और तकनीक-आधारित शासन को और मजबूती मिलेगी।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत ने सुरक्षित मतगणना के लिए क्यूआर कोड आधारित पहचान प्रणाली शुरू की

भारत ने आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान मतगणना केंद्रों की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण को मजबूत करने के लिए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान प्रणाली शुरू की है।

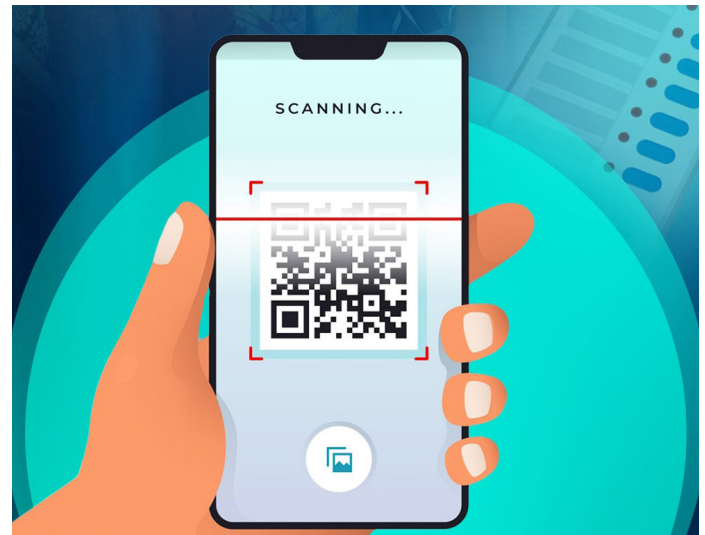
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म के अंतर्गत यह प्रणाली 4 मई 2026 को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और कुछ उपचुनाव क्षेत्रों में मतगणना के दौरान लागू की जाएगी।

नई तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत शुरुआती जांच बिंदुओं पर अधिकारियों द्वारा फोटो पहचान पत्रों की मैन्युअल जांच की जाएगी, जबकि मतगणना हॉल में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य संवेदनशील मतगणना क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना है।

क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना कर्मियों, तकनीकी कर्मचारियों, उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों को जारी किए जाएंगे। मीडिया कर्मियों के लिए मौजूदा प्राधिकरण प्रक्रिया जारी रहेगी और मतगणना केंद्रों के पास विशेष मीडिया केंद्र बनाए जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती और प्रणाली के सुचारु संचालन के निर्देश दिए गए हैं ताकि मतगणना प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो





छत्तीसगढ़ के माननीय राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकुराम वर्मा द्वारा भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डायवर्जन सुविधा का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व सेवाओं तक नागरिकों की पहुँच को आसान बनाने और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से दो प्रमुख डिजिटल पहल—भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा और ऑटो-डायवर्जन (रीक्लासिफिकेशन) सुविधा—का शुभारंभ किया है। इन पहलों का उद्घाटन 9 फरवरी 2026 को माननीय राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़, श्री टंकुराम वर्मा द्वारा किया गया।

भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट के माध्यम से नागरिक अब सीधे व्हाट्सऐप पर भूमि एवं राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। नागरिक अपने मोबाइल में 7289056060 नंबर सेव करके व्हाट्सऐप पर संदेश भेजकर तुरंत संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध प्रमुख सेवाएँ हैं: 1. भूमि से संबंधित जानकारी; 2. राजस्व न्यायालय से संबंधित जानकारी; 3. मोबाइल नंबर लिंकिंग; 4. आधार नंबर लिंकिंग हेतु आवेदन; 5. किसान क्रेडिट बुक के लिए आवेदन; 6. नामांतरण (म्यूटेशन) के लिए आवेदन; तथा 7. अन्य राजस्व विभाग से संबंधित नागरिक सेवाएँ। यह पहल नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक तेज, सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी अवसर पर राज्य सरकार ने ऑटो-डायवर्जन (रीक्लासिफिकेशन) सुविधा भी शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक अब भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही या कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भूमि चयन से लेकर प्रीमियम एवं शुल्क की गणना तथा ई-चालान के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान तक पूरी प्रक्रिया स्वचालित कर दी गई है।

प्राप्त आवेदनों को परीक्षण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा और 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समयावधि में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो डिम्ड डायवर्जन प्रमाणपत्र स्वतः जारी हो जाएगा, जिससे नागरिकों को अनावश्यक विलंब से राहत मिलेगी। यह सुविधा आधिकारिक पोर्टल <https://revenue.cg.nic.in/citizenrequest/> के माध्यम से उपलब्ध है।

अधिकारियों के अनुसार, ये पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने तथा राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

- सत्येश कुमार शर्मा, छत्तीसगढ़

ओडिशा में निरीक्षण बंगलों के लिए ई-आईबी ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का शुभारंभ

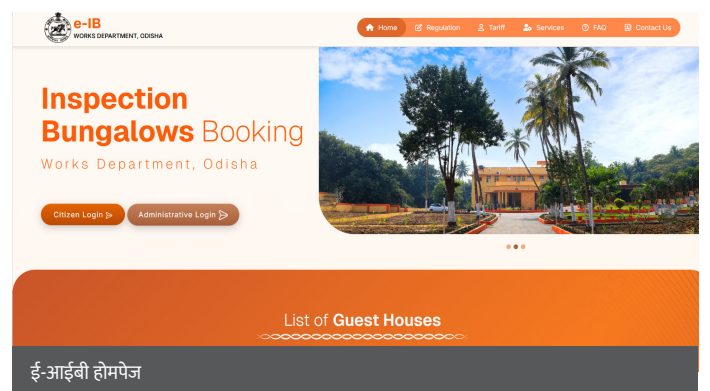
ओडिशा सरकार के कार्य विभाग ने सरकारी अतिथि गृहों और निरीक्षण बंगलों के डिजिटल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-आईबी ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली (<https://eibworks.odisha.gov.in>) शुरू की है। इस पोर्टल का उद्घाटन माननीय कार्य मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने लोक सेवा भवन में किया। इस अवसर पर कार्य विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय सिंह, एनआईसी के अधिकारी तथा राज्यभर के इंजीनियर उपस्थित रहे।

इस प्रणाली को प्रारंभिक चरण में तीन स्थानों पर पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया है: 1. भुवनेश्वर: पीडब्ल्यूडी निरीक्षण बंगले, सत्यानगर; 2. पुरी: निर्माण निवास; तथा 3. कोणार्क: पीडब्ल्यूडी निरीक्षण बंगले।

यह पोर्टल पारंपरिक मैन्युअल बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कार्यप्रवाह से प्रतिस्थापित करता है। उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग अनुरोध जमा कर सकते हैं तथा सत्यापन के लिए पहचान दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदन स्वतः संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी के पास भेज दिए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

आरक्षण चार श्रेणियों के अंतर्गत प्रबंधित किए जाते हैं: 1. राज्य अतिथि एवं वीआईपी; 2. ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी; 3. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी; तथा 4. सामान्य नागरिक।

इस प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन भुगतान गेटवे भी शामिल है तथा रियल-टाइम डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से कमर्सें की उपलब्धता, राजस्व संग्रह और स्वीकृतियों की निगरानी की जा सकती



है। इस प्रणाली को एनआईसी द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है तथा इसका प्रबंधन मुख्य निर्माण अभियंता (आर एंड बी), सेंट्रल सर्कल, भुवनेश्वर द्वारा किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, ई-आईबी पोर्टल निरीक्षण बंगलों की बुकिंग और प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-हितैषी बनाएगा। पायलट चरण की सफलता के बाद इसे राज्य के अन्य निरीक्षण बंगलों तक विस्तारित करने की योजना है।

- जयंत कुमार मिश्रा, ओडिशा

हिमाचल प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री ने 'हिम-अतिथि' पोर्टल का शुभारंभ किया

माननीय उपमुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, श्री मुकेश अग्निहोत्री ने 20 जनवरी 2026 को हिम-अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल (<https://himatithi.nic.in>) सरकारी विभागों के विश्राम गृहों की बुकिंग के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने ग्राम संपदा ऐप, क्यूआर कोड आधारित मनरेगा (एम.जी.एन. आर.ई.जी.ए.) डेटा युक्त सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने लखपति दीदी/ महतारी सदन पुस्तिका तथा माँ अभियान प्रकाशन का विमोचन भी किया।

एनआईसी, हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित यह पोर्टल नागरिकों और पर्यटकों को राज्यभर में स्थित जल शक्ति विभाग के 87 विश्राम गृहों में ऑनलाइन कमरा बुक करने की सुविधा देता है। बुकिंग के बाद उपयोगकर्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुष्टि संदेश प्राप्त होता है। साथ ही, आवेदक पोर्टल पर "बुकिंग स्थिति जांचें" विकल्प के माध्यम से अपनी बुकिंग की स्थिति देख सकते हैं तथा "बुकिंग रद्द करें" विकल्प के जरिए बुकिंग रद्द भी कर सकते हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग और लोक निर्माण विभाग पहले ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जबकि जल शक्ति विभाग इस पोर्टल को अपनाने वाला तीसरा विभाग बन गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, बुकिंग प्रक्रिया सरल होगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।

यह पोर्टल कोषागार एवं लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश के ई-चालान भुगतान गेटवे से एकीकृत है, जिससे ऑनलाइन बुकिंग से प्राप्त राशि सीधे सरकारी कोषागार में जमा हो जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल-टाइम डैशबोर्ड के जरिए विश्राम गृहों की अधिभोग स्थिति और राजस्व की निगरानी भी कर सकते हैं।



हिमाचल प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा रेस्ट हाउस बुकिंग के लिए हिम-अतिथि पोर्टल का शुभारंभ

इस अवसर पर डॉ. अभिषेक जैन, आईएएस, सचिव; इर. अंजू शर्मा, इंजीनियर-इन-चीफ; इर. अनिल मेहता, मुख्य अभियंता सहित जल शक्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एनआईसी हिमाचल प्रदेश से श्री अजय सिंह चहल, स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान माननीय उपमुख्यमंत्री और जल शक्ति विभाग के सचिव ने विभागीय कार्यों के लिए एनआईसी द्वारा विकसित ई-संचालन / वर्क्स एमआईएस सॉफ्टवेयर की भी सराहना की।

- संदीप सूद, हिमाचल प्रदेश

राजस्थान में 'पहचान' सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

राजस्थान सरकार ने 15-16 जनवरी 2026 को जयपुर में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 'पहचान' पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया गया, जिसमें पंजीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा पोर्टल पर उपलब्ध नई सुविधाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

दो दिवसीय कार्यशाला में 41 जिलों से 550 से अधिक प्रतिभागियों—जिला रजिस्ट्रार, ब्लॉक अधिकारी, उप-रजिस्ट्रार तथा निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों—ने भाग लिया।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्री विनेश सिंहवी ने समय पर पंजीकरण और प्रमाणपत्रों के डिजिटल हस्ताक्षर के महत्व पर बल दिया, ताकि नागरिकों को सेवाएँ शीघ्रता से उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का भी आग्रह किया।

एनआईसी के वरिष्ठ निदेशक (आईटी) श्री अमित अग्रवाल ने 'पहचान' प्रणाली की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब पंजीकरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो चुकी है और आगे डेटा की शुद्धता, सुरक्षा तथा डेटा विश्लेषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि पहचान पोर्टल का डेटा आरजीआई-सीआरएस, यू.आई.डी.ए.आई, जन आधार तथा अन्य सरकारी योजनाओं से एकीकृत है।

कार्यशाला के दौरान एनआईसी अधिकारियों ने पोर्टल में किए गए नवीन अपडेट प्रस्तुत किए, तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की तथा पहचान व्हाट्सएप बॉट का प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से नागरिकों को पंजीकरण सेवाएँ और अधिक सरलता से उपलब्ध हो सकेंगी।

एनआईसी राजस्थान द्वारा विकसित 'पहचान' राज्य में जन्म, मृत्यु, मृतजन्म तथा विवाह पंजीकरण के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पिछले 12 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। वर्तमान में यह प्रणाली 15,000 से अधिक रजिस्ट्रार एवं उप-रजिस्ट्रार तथा 2,400 से अधिक निजी अस्पतालों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है, जिससे राज्य में नागरिक पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध सुनिश्चित हो रही है।

- इन्फॉर्मेटिक्स न्यूजडेस्क, एनआईसी मुख्यालय



पहचान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला की एक झलक



चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में आयोजित मेडलीपर कार्यशाला की एक झलक

एनआईसी हरियाणा ने चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में मेडलीपर पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की

एनआईसी हरियाणा ने 14 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में मेडलीपर (मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्टिंग) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने किया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सहित अन्य गणमान्य अतिथि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मेडलीपर कम्पैडियम का विमोचन किया गया तथा मेडलीपर मोबाइल एप्लिकेशन

का सॉफ्ट लॉन्च भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म मेडिको-लीगल परीक्षण और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे न्याय प्रणाली में मानकीकरण, पारदर्शिता और कार्यक्षमता में सुधार होगा।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न राज्यों में मेडलीपर प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित रणनीतियाँ, सर्वोत्तम प्रथाएँ और चुनौतियाँ भी साझा कीं।

अधिकारियों ने बताया कि एनआईसी हरियाणा के तकनीकी सहयोग से विकसित यह प्लेटफॉर्म मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होगा और न्याय वितरण प्रक्रिया को अधिक तेज और विश्वसनीय बनाने में योगदान देगा।

- दीपक सावंत, हरियाणा

ओडिशा ने डेटा-आधारित शासन को सशक्त बनाने के लिए जिला जियो-पोर्टल लॉन्च किया

ओडिशा के सभी 30 जिलों को कवर करने वाला व्यापक जीआईएस-आधारित प्लेटफॉर्म 'ओडिशा जिला जियो-पोर्टल' का शुभारंभ 17 दिसंबर 2025 को माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग द्वारा किया गया। इसका शुभारंभ भुवनेश्वर में आयोजित जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) सम्मेलन के दौरान हुआ।

यह पोर्टल विभिन्न स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटासेट को एकीकृत करता है, जिनमें प्रशासनिक सीमाएँ, प्राकृतिक संसाधन, संचार नेटवर्क, कृषि परिसंपत्तियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित डेटा शामिल हैं। जिला स्तर की भू-स्थानिक जानकारी के लिए एकल एक्सेस प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया यह पोर्टल योजनाकारों और प्रशासकों को डेटा-आधारित निर्णय लेने, योजना निर्माण और निगरानी में सहायता प्रदान करेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मुकेश महालिंग ने शासन में जियोस्पेशियल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और नीति-निर्माण को और मजबूत करेगी।

इस अवसर पर डॉ. प्रदीप कुमार राउत, विशेष सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (ओ.सी.ए.सी) और डॉ. अशोक कुमार होता, उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी ओडिशा सहित एनआईसी के राज्य एवं जिला इकाइयों के अधिकारी उपस्थित रहे।



ओडिशा के माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग द्वारा 17 दिसंबर 2025 को ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स जियो-पोर्टल का शुभारंभ

अधिकारियों के अनुसार, यह जियो-पोर्टल जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- ए. के. होता, ओडिशा



मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा ई-कैबिनेट प्रणाली का शुभारंभ



मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ई-कैबिनेट प्रणाली का शुभारंभ किया

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ई-कैबिनेट प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया, जो राज्य में डिजिटल शासन और पेपरलेस प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर माननीय उपमुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय कैबिनेट मंत्रीगण भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने जानकारी दी कि आगामी दो से तीन कैबिनेट बैठकें हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएंगी, जिनमें भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार की भागीदारी होगी। इसके बाद कैबिनेट बैठकों को ई-कैबिनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन आयोजित करने की योजना है, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी होगी।

ई-कैबिनेट प्रणाली को कैबिनेट बैठकों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसमें एजेंडा प्रसारण, नोट साझा करना, दस्तावेजों तक सुरक्षित पहुँच और निर्णयों का रिकॉर्ड जैसे सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इससे कागज के उपयोग में कमी आएगी, विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा तथा मंत्रियों को आवश्यक दस्तावेज समय पर और सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान एनआईसी के वरिष्ठ निदेशक श्री अमित जैन ने मंत्रिपरिषद के समक्ष ई-कैबिनेट प्रणाली का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं, कार्यप्रवाह और सुशासन में इसके लाभों पर प्रकाश डाला गया। यह सत्र एनआईसी मध्यप्रदेश के उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ) श्री कमलेश जोशी तथा संयुक्त निदेशक श्री मनीष मालवीय की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, ई-कैबिनेट प्रणाली के कार्यान्वयन से सरकारी निर्णय प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और गति में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा यह मध्यप्रदेश शासन की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटल रूपांतरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- सुषमा मिश्रा, मध्यप्रदेश

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की छह ऑनलाइन एप्लीकेशनों का शुभारंभ किया

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व परिषद, उत्तराखंड की छह नागरिक-केंद्रित ऑनलाइन एप्लीकेशनों का शुभारंभ किया। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), उत्तराखंड द्वारा विकसित इन एप्लीकेशनों का उद्देश्य नागरिकों को प्रमुख राजस्व सेवाएँ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव, राजस्व परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी, तथा आईटीडीए और सर्ट-इन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त तथा विभिन्न तहसीलों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

इन नई डिजिटल सेवाओं के माध्यम से नागरिक अब भूमि अभिलेख, कैडस्ट्रल मानचित्र, भूमि हिस्सेदारी संबंधी जानकारी, भूमि उपयोग अनुमति, कृषि ऋण प्रक्रिया तथा राजस्व वसूली प्रबंधन जैसी सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इन एप्लीकेशनों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता को कम करना और राजस्व प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाना है।

अधिकारियों के अनुसार, यह पहल राज्य में पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन को सुदृढ़ करेगी तथा राजस्व सेवाओं की उपलब्धता और दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी।



उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राजस्व परिषद, उत्तराखंड की छह नागरिक-केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ

- चंचल गोयल, उत्तराखंड



एनआईसी ओडिशा के डी.ई.पी.एम.ओ.एस को राष्ट्रीय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समित में सम्मानित किया गया

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ओडिशा को नई दिल्ली में आयोजित 6वें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समित एंड अवॉर्ड्स में अपने डी.ई.पी.एम.ओ.एस प्रोजेक्ट के लिए “डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एंशोरिंग रूरल कनेक्टिविटी एंड डिजिटल सर्विसेज अवॉर्ड” प्राप्त हुआ है।

एम.एस.एम.ई विभाग के लिए विकसित डी.ई.पी.एम.ओ.एस ने एक ऐसी समस्या का शांतिपूर्वक समाधान किया है, जो अक्सर छोटे व्यवसायों की गति को धीमा कर देती है — कागजी कार्यवाही, देरी और लंबी प्रक्रियाएं। पंजीकरण, निरीक्षण और रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं को ऑनलाइन लाकर, इस प्लेटफॉर्म ने सरकारी सहायता को तेज, अधिक पारदर्शी और ओडिशा भर के एमएसएमई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिक सुलभ बना दिया है।

यह पुरस्कार मोहम्मद मोजीबुल्लाह खान, निदेशक (आईटी), सुधांशु कुमार महापात्र, उप निदेशक (आईटी), एनआईसी ओडिशा, और संजय कुमार मिश्रा, निदेशक, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग (ईपी एंड एम), ओडिशा द्वारा प्राप्त किया गया। यह सम्मान दर्शाता है कि जब तकनीक को सरलता और उद्देश्य के साथ डिजाइन किया जाता है, तो यह छोटे उद्यमियों के लिए शासन को कम दूर और अधिक सहयोगी बना सकती है, जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।



एनआईसी नुआपाड़ा अधिकारी को चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया

श्री विनयकुमार तिवारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ), एनआईसी नुआपाड़ा, को भुवनेश्वर स्थित स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 समारोह के दौरान “बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट” श्रेणी में सम्मानित किया गया।

यह सम्मान श्री आर. एस. गोपालन, आईएएस, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा, तथा श्री मधुसूदन पाथी, आईएएस, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ओडिशा द्वारा, नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के सफल, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी संचालन में श्री तिवारी के महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

डीआईओ एवं नोडल अधिकारी के रूप में, श्री तिवारी ने चुनाव प्रक्रिया के तकनीकी एवं साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत निर्वाचन आयोग के साथ उनके समन्वय तथा महत्वपूर्ण चुनावी एप्लिकेशनों के प्रभावी प्रबंधन ने चुनाव संचालन को सुचारु, पारदर्शी और दक्ष बनाने में सहायता की।

उन्हें तकनीक-आधारित चुनाव प्रबंधन के प्रति समर्पित सेवा और प्रतिबद्धता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा के कार्यालय द्वारा प्रशंसा प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया।



श्री अजय सिंह चहल
उप महानिदेशक व एसआईओ
हिमाचल प्रदेश



डॉ. सुचित्रा प्यारेलाल
उप महानिदेशक व एसआईओ
केरल और लक्षद्वीप



श्रीमती सीमांतनी सेनगुप्ता
उप महानिदेशक व एससी
सिक्किम

कृतज्ञता एवं सम्मान सहित

कि सी प्रकाशन की शक्ति केवल उसमें प्रकाशित समाचारों और विशेष लेखों में ही नहीं होती, बल्कि उन व्यक्तियों की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और मार्गदर्शन में भी निहित होती है, जो पर्दे के पीछे रहकर उसकी संपादकीय दिशा को आकार देते हैं।

हमारे हमारे आदरणीय संपादकीय सलाहकार श्री अजय चहल, डॉ. सुचित्रा प्यारे लाल एवं श्रीमती सीमांतनी सेनगुप्ता के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के अवसर पर, हम *इन्फॉर्मेटिक्स* के प्रति उनके अमूल्य मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपनी हार्दिक सराहना एवं गहन आभार व्यक्त करते हैं। उनकी सूझबूझ, निष्ठा और विचारशील

दृष्टिकोण ने इस प्रकाशन को समृद्ध बनाने तथा ई-गवर्नेंस पारितंत्र में इसकी सशक्त पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यद्यपि संपादकीय योगदान प्रायः सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते, फिर भी वे किसी प्रकाशन की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और चरित्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स के साथ उनका जुड़ाव सदैव सम्मान, आदर और कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा।

- प्रधान संपादक, इन्फॉर्मेटिक्स